लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-90
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, ३० मई, १९६२

९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाकखानों में लिखने का कागज

+

†११६४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सभी डाकखानों में लिखने के कागज की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं । संभवतया माननीय सदस्यों का इशारा उन फार्मों की कमी की ओर है जिन पर जनता के साथ डाकखाना पत्र-व्यवहार करता है । पश्चिम बंगाल सर्किल के डाकखानों जैसे बड़ा बाजार (कलकत्ता), कृशनगर मुख्यालय, मिदनापुर मुख्यालय, दार्जिलिंग मुख्यालय, बीडन स्ट्रीट टी० एस० ओ० तथा दमदम सब पोस्ट आफिस में कुछ समय के लिये इन फार्मों की कमी थी । अब स्थिति सामान्य है ।

(ख) पी० एण्ड टी० फार्म स्टोर, कलकत्ता से फार्मों का कम संभरण होने के कारण अस्थाई कमी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

1181 (Ai) LSD—1.

(ग) स्थानीय रूप से छपवाकर, पी० एण्ड टी० फार्म स्टोर, कलकत्ता से मंगवाकर स्थिति ठीक कर ली गई और वहां पर कोई कमी नहीं है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने बताया कि अब स्थिति ठीक है। क्या यह सच है कि पत्र-व्यवहार के फार्मों तथा लेखन पत्रों का संभरण काम बढ़ जाने की तुलना में कम है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने बताया कि कठिनाई अस्थाई थी। परन्तु अब स्थिति सामान्य है। कठिनाई कागजों के संभरण के कारण थी। और जब तक हम अपने देश में कागज के निर्माण में आत्म निर्भर नहीं हो जायें तब तक कमी रहेगी।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि "सिचुएशन इज़ नाऊ नार्मल"। मेरा अपना जहां तक अनुभव है, वह बताता है कि नार्मल होने पर भी फार्म्स की बड़ी कमी रहती है। दिल्ली में भी हमारे पार्लियामेंट हाउस में बहुत से फार्म्स नहीं मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष उपाय किये जा रहे हैं ताकि कम से कम जो बड़े बड़े डाकखाने हैं, उनमें इनकी कमी न होने पाए ?

श्री जगजीवन राम : यहां पर उन फार्म्स का सवाल था जो जनता के साथ कारेसपोंडेंस के लिये, पत्र-व्यवहार के लिये, पोस्ट आफिस के अधिकारी काम में लाते हैं। जहां तक दूसरे फार्म्स का तालुक है, जैसा मैंने कहा हमारे मुल्क में कागज़ का अभाव है और जितनी मुल्क की आवश्यकतायें कागज़ की हैं, उतना कागज़ हमारे यहां उत्पन्न नहीं हो रहा है और जब तक वह स्थिति रहेगी, तब तक कुछ न कुछ कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि कागज की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि विभागातिरिक्त डाकखानों जिनमें ब्रान्च पोस्ट मास्टरों को काम के लिये कागज़ खरीदना पड़ता है, को इसके लिये धन दिया जाता है ?

†**श्री जगजीवन राम** : उनको धन दिया जाता है। स्टेशनरी खरीदने के लिये एक निश्चित मान है और हमने आपातकाल में स्थानीय रूप से क्रय की अनुमति दी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग की कागज़ की कुल कितनी आवश्यकता है तथा कितनी पूरी की गई है ? क्या उन्होंने इसका अनुमान लगाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल पश्चिम बंगाल के संबंध में है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने बताया कि देश में कागज की कमी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार सारा मामला खड़ा हो जाता है। श्री ब० कु० दास।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा निवेदन है कि कुछ दिन...

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अनुमति नहीं दी।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या ब्रान्च डाकखानों में आपातकाल के लिये कोई उपबन्ध है जिससे वह कागज़ तथा अन्य सामान खरीद सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगजीवन राम : उपबन्ध है। परन्तु इस मामले में काम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने बताया कि यह फार्म जनता से पत्र-व्यवहार के काम आते हैं परन्तु जब इनकी कमी होती है तो भी हम पत्र-व्यवहार अन्य कागजों पर करते ही हैं।

†श्री वारियर : इन फार्मों की छपाई के लिये डाक विभाग में क्या व्यवस्था है ? यह विभागीय तौर पर किया जाता है अथवा गैर-सरकारी ठेके पर ?

†श्री जगजीवन राम : अधिकांशतः यह विभागीय होता है परन्तु कुछ आपातकालीन मामलों में कागज स्थानीय रूप से खरीद कर स्थानीय रूप से छपाई की हम अनुमति देते हैं।

†श्री प्रभात कार : फार्मों की कमी के कारण डाक तथा तार के राजस्व में बहुत हानि होती है। इनको छपाई के लिये देने से पूर्व क्या प्रत्येक डाकखाने की आवश्यकता पर विचार कर लिया जाता है ?

†श्री जगजीवन राम : इसी आधार पर आर्डर दिए जाते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का उत्तर देते समय माननीय मंत्रियों को मेरी ओर देखना चाहिये। कभी कभी मैं प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं परन्तु उत्तर दे दिया जाता है।

†श्री बसुमतारी : क्या इस प्रकार की शिकायत है कि कागज की कमी के कारण आसाम में टेलीफोन गाइड नहीं छपवाई गई और जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल से आसाम कैसे। अगला प्रश्न।

स्टीमरों की मरम्मत का कारखाना

+

†*११६५. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में स्टीमरों की मरम्मत का एक कारखाना (वर्कशाप) स्थापित करने की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या कोई रक़म नियत की गई थी; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह योजना पूरी हो जायेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

†श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि कोचीन के इस कारखाने के लिये दूसरी योजना में १ करोड़ रुपये की राशि अलग रख दी गई थी ?

†श्री जगजीवन राम : जी नहीं। मैं ऐसा नहीं समझता। दूसरी योजना में ऐसा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि ५ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ रुपये डाक यार्ड के असैनिक निर्माण के लिये थे तथा १ करोड़ रुपया कारखाना बनाने के लिये था ? क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से वह इस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न।

सेवा निवृत्त डाक-तार कर्मचारी द्वारा आत्महत्या

†११६६. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग के एक सेवा निवृत्त कर्मचारी ने, उसे पेंशन और उपदान (ग्रैच्युटी) न दिये जाने के कारण हुई वित्तीय कठिनाइयों के कारण, जबलपुर में अभी हाल में आत्महत्या कर ली ;

(ख) यदि हां, तो उसके सेवा निवृत्त होने और परिणाम स्वरूप आत्महत्या के बीच कितना समय बीता है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है ; और

(घ) उसका क्या नतीजा निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) जांच से मालूम हुआ कि टेलीग्राफ स्टोर विभाग के एक बढ़ई जो १०-१-६१ को सेवानिवृत्त हुआ था, ने १९-३-६२ को आत्महत्या कर ली थी। वह काम पर अंशदायी भविष्य निधि के लाभों का अधिकारी था। उसका १७५४ रुपये २ नये पैसे का अंशदान उसको २८-३-६१ को दिया गया था। उसने १६-३-६२ के निवृत्ति के बाद पेंशन योजना का विकल्प किया था और निधि में सरकारी अंशदान लेना स्वीकार किया तथा १९-३-६२ को आत्महत्या कर ली। उसका डाकखाना बचत बैंक में पर्याप्त धन था और कलकत्ता के पास जमीन भी थी। स्पष्ट है कि आत्महत्या का कारण शारीरिक था तथा पेंशन तथा उपदान का मामला तय होने में विलम्ब नहीं था।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या पेंशन तथा उपदान के मामले विलम्ब से तय होने के बारे में डाक तथा तार विभाग में अकसर शिकायतें मिलती हैं तथा यदि हां, तो क्या विभाग इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाने जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : जो मामला यहां बताया गया है उसमें विलम्ब नहीं हुआ था। आत्महत्या का कारण कुछ और था।

†श्री जगजीवन राम : डाक तथा तार विभाग पर विलम्ब का लांछन नहीं लगाया जाना चाहिए। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि : जो आदमी ...

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों से एक विनय करनी है । जितना वक्त वे इस बात पर लगाते हैं "क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि", इत समय में तो वह सवाल हो जाएगा । इस वास्ते व कोशिश करें कि इसको न कहा जाए ।

श्री अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे—(हंसी) । माननीय मंत्री जी बतलायेंग कि जब कोई आदमी रिटायर होता है तो उसके पेंशन पेपर इत्यादि ज्यादा से ज्यादा कितने समय में बन जान चाहियें, और उसको पेंशन मिल जानी चाहिये ?

श्री जगजीवन राम : जल्दी से जल्दी यह काम हो जाना चाहिये ।

†**श्री वारियर**: क्या पुलिस को आत्महत्या के बाद मृत व्यक्ति के शव से कोई कागज मिला था जिसमें आत्महत्या का कारण बताया गया हो ? क्या कोई जांच की गई थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि उस व्यक्ति ने गरीबी के कारण आत्महत्या की थी । बचत बैंक में पर्याप्त रकम जमा थी। भविष्य निधि के दिए जाने में विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री बड़े : ऐसे कितने केसेज पेंडिग हैं जिनमें रिटायर होने के एक या दो साल तक पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में पेंशनें नहीं मिली हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह जानकारी में लिये तो नहीं फिरता हूं । माननीय सदस्य कृपा करके अलग सुचना दें ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी**: बहुत सारे केसेज होंगे ।

श्री बड़े : बहुत हों या कम हों, कम से कम यह तो बतला सकते हैं कि एक हैं, या दो हैं या कितने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जब इन्फार्मेशन हो, तब पता चल सकता है कि एक है या ज्यादा हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि मृत्य व्यक्ति के पास एक पत्र मिला था और यदि हां, तो क्या उस पत्र में आत्म हत्या के कारण बताये थे ?

†**श्री जगजीवनराम** : जी नहीं ।

सोन नदी पर पुल बनाने के लिये धन देना

†*११६८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या परिवहन तथा सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सोन नदी पर पुल बनाने के लिए सरकार ने धन देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह धन कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ऋण कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा पुल बनाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा उसके लिए समस्त विश्व में टेंडर दे दिए गए हैं। उस तक पहुंचने वाली सड़कों के प्राक्कलनों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) पुल के लिए २१०.५५ लाख रुपये का तथा सड़कों के लिए २९.२० लाख रुपये।

†**श्री भागवत झा आजाद**: क्या पुल का निर्माण आरम्भ करने के लिये तथा पूरा करने के लिए कोई समय अनुसूची बनाई गई है ?

†**श्री जगजीवन राम**: ऐसे सभी मामलों में एक मोटे तौर पर समय अनुसूची बना ली जाती है।

†**श्री भागवत झा आजाद**: इसका कुल व्यय क्या होगा तथा इसमें केन्द्रीय सरकार के धन के अतिरिक्त राज्य सरकार का अंशदान क्या होगा ?

†**श्री जगजीवन राम**: मैं समझता हूं कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता मिली है और शेष व्यय केन्द्रीय सरकार विभिन्न निधियों से वहन करेगी।

श्री बृ० बि० मेहरोत्रा: क्या इस पुल को बनाने का ठेका किसी विदेशी कम्पनी को दिया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपये में दिया गया है ?

श्री जगजीवन राम: शायद माननीय सदस्य ने उत्तर को ठीक से नहीं सुना। बतलाया गया है कि विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

डाक तथा तार सेवा

†*११६९. **श्री अ० स० सहगल**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार डाक तथा तार विभाग में सल्वर तथा विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या तत्काल गतिशील उपाय कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४९]**

श्री अ० स० सहगल: जिन सर्विसेज को जनता को देने के लिये खास तौर से स्टेटमेंट में बतलाया गया है, उन की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हुई है, इस के बारे में क्या खयाल है ?

श्री जगजीवन राम: जी हां, पूर्ति करने का प्रयत्न किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: जो फैक्ट्स हों वे पूछे जाने चाहियें। खयाल नहीं पूछे जाते।

†**श्री दी० च० शर्मा**: विवरण में बताया गया है कि डाक तथा तार बोर्ड के अधिकार तथा कार्यों को बढ़ाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह विचार किस दिशा में किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** प्रशासन की सभी दिशाओं में ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या विभागीय डाकखानों के अचानक अधीक्षण तथा निरीक्षण के बारे में कोई आदेश है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैंने बताया कि निरीक्षण तथा अधीक्षण काम के लिए एक निदेशक का पद बनाया गया है और हम अधीक्षण पर बल देने जा रहे हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या इन प्रस्तावों में टेलीफोन विभागों में सुधार करना भी शामिल है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जरुर।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या भवन निर्माण कार्यक्रम के लिए स्थापित विशेष विभाग की रिपोर्ट सरकार को मिली है क्योंकि इसके न होने के कारण विभाग के कार्यवहन में बड़ी कठिनाई होती है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह व्यवस्था हाल में ही हुई है और हमे प्रगति देखनी है । इसमें मुझे संदेह नहीं है कि वह निर्माण कार्य में शीघ्रता करेंगे ।

†**श्री नी० श्रीकन्तन नायर :** क्या यह सच है कि रजिस्टर्ड लिफाफे के दिल्ली तक पहुंचने में सप्ताह लग जाता है जबकि साधारण लिफाफा जल्दी पहुंच जाता है ?

†**श्री जगजीवन राम :** डाक तथा तार में इसको विश्वव्यापी नहीं समझना चाहिए । कभी कभी देर हो जाती है और हम उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री वारियर :** ट्रंक लाइनों के काउन्टर पर अर्जेन्ट कालों तथा सुपर अर्जेंट कालों के लिये हमेशा अधिक ध्यान दिया जाता है जब कि साधारण कालों को शीघ्र नहीं लिया जाता है ?

†**श्री जगजीवन राम :** क्योंकि लाइनें तथा सर्किट सीमित हैं तथा अर्जेंट कालें बहुत बढ़ती जा रही हैं ।

†**श्री अ० सि० सहगल :** विभाग में गवेषणा संगठन कब लागू हो जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** निर्णय किया गया है और शीघ्र स्थापना हो जायेगी।

†**श्री वारियर :** सर्किटों को बढ़ाने के लिये तथा लौगरेंज ट्रंक कालों को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह दीर्घकालीन नीति है ।

†**श्री वारियर :** जी नहीं । ऐसा अभी भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पीने के पानी की संभरण-योजनाएं

†*११७०. **श्री हरिश्चन्द्र माथर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में पीने के पानी के कार्यक्रमों पर कितना धन व्यय हुआ तथा वर्ष १९६२-६३ में (१) नगरीय क्षेत्रों, और (२) ग्रामीण क्षेत्रो में कितना धन व्यय किया जायेगा ;

(ख) जोरदार मांग और सभा में दिनांक १९ मार्च, १९६२ को प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रख कर क्या मामले पर पुनः विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो निष्कर्ष क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९६१-६२ के दौरान पीने के पानी के कार्यक्रम पर खर्च की गयी रकम और स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन १९६२-६३ में किया गया खर्च इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	१९६१-६२ में खर्च की गयी रकम	१९६२-६३ में खर्च की जाने वाली रकम
	(लगभग)	(लगभग)
शहरी क्षेत्र	२०.२२	१८.१५
ग्रामीण क्षेत्र	४.५	३.२९

२. देश में पानी की सप्लाई-स्थिति की समीक्षा की गयी है और सरकार ग्रामीण तथा शहरी कार्यक्रमों के संबंध में अधिक शीघ्र प्रगति आवश्यक समझती है । विचार यह है कि ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, यदि संभव हो तो, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही पूरा हो जाये और शहरी कार्यक्रम अगले पन्द्रह वर्षों में पूरा किया जाये । इन उद्देश्य की पूर्ति की सुविधा के लिये एक केन्द्रीय पानी और सफाई बोर्ड कायम करने का विचार है । इसके कार्य ऐसे होंगे जिससे चालू कार्यक्रम अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और देश के प्रत्येक गांव को अच्छा पीने का पानी दिलाने के लिये कार्यवाही शुरू करने और संभव न्यूनतम अवधि में शहरी जलपूर्ति और सफाई योजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ग्रामीण जलपूर्ति के लिये अनुमानित आवश्यकता कितनी है और उसे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० द० स० राजू : अनुमान है कि संपूर्ण ग्रामीण जलपूर्ति योजना के लिये २०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय जलपूर्ति और सफाई योजना में एक सिफारिश यह है कि ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये और केन्द्र तथा राज्यों में जलपूर्ति और सफाई बोर्ड कायम किये जांय। इस सिफारिश पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री कहते हैं कि ग्रामीण जलपूर्ति के लिये करीब २०० करोड़ रुपये की जरूरत होगी और तीसरी योजना में सारा कार्यक्रम पूरा करने का विचार है। इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री १९६१–६२ में इसके लिये ४.५ करोड़ रुपये की रकम किस प्रकार ठीक समझते हैं और यह किस प्रकार है कि १९६२–६३ में यह रकम भी घटाकर ३.२९ करोड़ रुपये कर दी है, जैसा कि विवरण से मालूम होता है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : माननीय सदस्य जिस रकम का निर्देश करते हैं वह चालू वर्ष के लिये नियत की गयी रकम है। तीसरी योजना की संपूर्ण अवधि के लिये विभिन्न मंत्रालयों के लिये बांटी गयी रकम ८० करोड़ रुपये के लगभग है। इसी कारण यह बोर्ड स्थापित किया गया है कि योजना में रखी गयी रकम बढ़ाने के लिये दूसरे जरियों की संभावना का पता लगाने और ग्रामीण जलपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाये।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था कि ४.५ करोड़ रुपये की यह थोड़ी सी रकम भी घटाकर ३.२९ करोड़ रुपये क्यों कर दी गयी ? जब हम कार्यक्रम बढ़ाने जा रहे हैं जिसके लिये लगभग २०० करोड़ रुपये की जरूरत है, तो इससे सम्बद्ध मंत्रालय ने भी यह रकम ४.२५ करोड़ रुपये से घटाकर ३.२९ करोड़ रुपये क्यों कर दी है ?

†श्री बड़े : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और सभा पटल पर रखे गये विवरण मे फर्क है।

†डा० सुशीला नायर : मैं समझती हूं कि इस साल के बजट में जो व्यवस्था की गयी है वह शायद पिछले साल की बची हुई योजनाओं के लिये है। अब अनेक माननीय सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुये मंत्रालय का ग्रामीण जलपूर्ति योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार है।

†श्री जसवन्त मेहता : ग्रामीण जलपूर्ति योजना की तीव्र आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार का तीसरी योजना के अन्तर्गत संसाधनों के अलावा दूसरे संसाधन ढूंढने का सरकार का विचार है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो वह पहले ही बता चुकी हैं।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : माननीय मंत्री ने बताया है कि ग्रामीण जलपूर्ति योजना को कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये जायेंगे। भूखंड अलग अलग हैं। सप्लाई के किन किन जरियों को काम में लाया जा रहा है ?

†डा० सुशीला नायर : मैं सभी संभव साधनों की विस्तृत सूची नहीं दे सकती। उदाहरण के लिये, मैं कुछ बता सकती हूं। माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि जलपूर्ति के संबंध में, राजस्थान सबसे खराब जगह है। जैसलमेर के कुछ भूखंडों में गहरे नलकूपों का उपयोग करने का विचार है। हम नलकूपों का भी उपयोग करने की संभावना का पता लगायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीया मंत्रिणी जी के ध्यान में यह बात आयी है कि राज्य सरकारों को यह शिकायत है कि जो योजनाएं भेजी जाती हैं उनको स्वीकार करने में बड़ी देरी हो जाती है। क्या इस बारे में जो नियम हैं उनमें कोई संशोधन किया जायेगा ?

डा० सुशीला नायर : ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने अभी तक तो आयी नहीं है। अभी तो इतना वक्त ही नहीं हुआ है कि कोई ढिलाई की शिकायत कर सके ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या पिछले साल की अपेक्षा चालू वर्ष में ग्रामीण जलपूर्ति योजना पर कम रुपया खर्च करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० सुशीला नायर :** जी नहीं ।

श्री विभति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो गांवो में पीने के पानी का इन्तिजाम कर रही है, क्या उसके लिये उसने कोई सरल तरीका निकाला है जिससे सरकारी रुपया भी ठीक तरह खर्च हो और गांव वालों को पानी भी मिल जाये ? क्या कोई ऐसा तरीका सरकार अपनाना चाहती है कि कुवें खोदने का काम गांववाले करें और यह काम सरकारी मशिनरी के पास न पड़ा रहे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** गांवो वाले सदस्य इसमें मदद कर सकते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह कहा गया है कि १९६१–६२ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लगभग ४.५ करोड़ रुपया खर्च किया गया और १९६२–६३ में लगभग ३.२९ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। फिर भी माननीय मंत्री कहते हैं हम चालू वर्ष में कम रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** यही बात श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने पूछी थी ।

†**डा० सुशीला नायर :** इसमें कोई असंगति नहीं है। यह तो चालू बजट की व्यवस्था है। संसद से अनुपूरक अनुदान मांगने के लिये हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या हम यह समझें कि बजट मांगों से चालू वर्ष के लिये सरकार की योजनाओं का दिग्दर्शन नहीं होता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इससे सरकार की योजनाओं का अवश्य पता चलता है लेकिन मंत्रालय फिर मांग कर सकता है या योजना आयोग नियत रकम बढ़ा सकता है और वह यहां पर प्रस्तुत होगा ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बजट में चाहे जो भी हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है क्या उसके खर्च करने का कोई ऐसा सरल तरीका अपनाने का विचार है कि जिससे आसानी से कुवें खुद सकें और लोगों को पानी मिल सके ?

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि कुंवा पार्लियामेंट या केन्द्रीय सरकार की मारफ्त नहीं खुदवाया जाता। यह काम स्टेट गवर्नमेंट की मारफत और उससे भी आगे जाकर पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मारफत करवाया जाता है और वहां पर माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथर:** विवरण में बताया गया है कि केन्द्रीय पानी और सप्लाई बोर्ड स्थापित किया जानेवाला है। इस समय एक ओर स्वास्थ्य मंत्रालय है, दूसरी ओर सामुदायिक विकास मंत्रालय है और राज्य सरकारें तीसरा अभिकरण है। ये तीनों ही ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के संबंध में खर्च कर रही हैं। तो इस बोर्ड और तीनों निकायों में समन्वय किस प्रकार किया जाता है? इन तीनो मंत्रालयों का इस बोर्ड के साथ क्या संबध होगा?

डा० सुशीला नायर : तीन नहीं बल्कि चार या पांच मंत्रालयों को पीने के पानी से संबद्ध इस केन्द्रीय बोर्ड से एक साथ लाने का विचार है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय है, सामुदायिक विकास मंत्रालय है, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह मंत्रालय है। इस केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत संपूर्ण कल्पना यह है कि इन सभी मंत्रालयों के प्रयत्नों का समन्वय किया जाये ताकि हम इस समस्या को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा सकें।

रक्सौल हवाई अड्डा

†*११७२. **श्री विभति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चम्पारन, बिहार के रक्सौल में हवाई अड्डे के निर्माण को पूरा करने की निश्चित तिथि के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह तिथि क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली–काठमांडू सेवा के विमान मार्ग में रक्सौल पर रुकेंगे ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रक्सौल को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). पैसेंजर शेड और अप्रोच रोड के अलावा रक्सौल पर बाकी दूसरे काम तकरीबन पूरे हो चुके हैं। एयरोड्रोम पर सभी कामों के पूरा होने के लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है।

(ग) और (घ). फिलहाल ऐसी कोई तजवीज नहीं है।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल के इम्पारटेंस को देखते हुये सरकार दिल्ली से काठमांडू और रक्सौल को लिंक करना चाहती है जैसे कि पाकिस्तान ने कराची से काठमांडू को लिंक किया है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने कहा, अभी तो आई० ए० सी० के पास ऐसी कोई तजवीज नहीं है लेकिन अगर रक्सौल जानेवाले यात्रियों की इतनी संख्या हो कि वहां हवाई जहाज ले जाना आवश्यक हो तो आई० ए० सी० इस पर विचार करेगी।

श्री विभूति मिश्र : वहां यह काम चार पांच छः साल से चल रहा है। क्या सरकार कोई अवधि निश्चित करेगी कि इतने दिनों में इस काम को पूरा कर देना चाहिये, या कि इसी तरह से काम चलता रहेगा ?

श्री जगजीवन राम : रफ्तार की तेजी या नरमी इस पर भी मुनहसिर करती है कि स्थान कैसा है। लेकिन अब मैं देखूंगा कि काम जल्दी हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ० गो० सेन :** इस हवाई अड्डे के महत्व को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि बरास्ना जोगबानी एक दूसरी रेल तथा सड़क है, क्या वहां भी एक हवाई अड्डा बनाने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहला हवाई अड्डा तो पहले बनने दीजिये। अगला प्रश्न।

रेलवे में अपराध

†*११७४. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऊंची श्रेणियों के डिब्बों में विशेषकर रात्रि के समय यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रहार और हिंसा के कृत्यों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उन के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उत्तर रेलवे पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, १९६२ में कितनी दुर्घटनायें हुईं जिन में यात्रियों को जोखिम उठानी पड़ी ; और

(घ) इन में से कितने मामले क्रमशः लूट-मार और हत्या से सम्बन्ध रखते थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह से सावधान है लेकिन ऊपरी दर्जों के यात्रियों पर खासकर रात के समय, हमले और मारपीट की कार्रवाइयां बढ़ नहीं रही हैं।

(ख) गाड़ियों में अपराध रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। इसके बावजूद, रेलवे ने अपनी ओर से रेल यात्रा में यथासंभव सुरक्षा के लिए कुछ सावधानी के उपाय किये हैं। इनमें से कुछ उपाय सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताये जा चुके हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५०]**

(ग) और (घ). उत्तर रेलवे में (एक फरवरी और एक अप्रैल, १९६२ में) डकैती के दो वाकयात हुए थे। इनमें ऊपरी दर्जों के यात्रियों को खतरा हुआ था।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार को मालूम है कि कुछ बदमाश लोग गाड़ी चलने से ठीक पहले गाड़ी में चढ़ते हैं और तब शरारत करने के लिए मौके का इन्तजार करते रहते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह तो उनका एक तरीका है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** यदि हां, तो महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस तैनात करने की कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** डिब्बों में चढ़ने वाले लोगों के पास ठीक-ठीक टिकट हो सकते हैं और यदि किसी के पास टिकट हो तो हम उसे, चाहे वह डाकू ही क्यों न हो, डिब्बे में चढ़ने से रोक नहीं सकते ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यह भी कहा जाता है कि रेलों में शरारत करने वाले कुछ गिरोह रेलवे पुलिस के साथ मिले जुले होते हैं । क्या सरकार ने इन गिरोहों तथा रेलवे पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए कुछ किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे पुलिस ने कई गिरोहों को बिल्कुल नष्ट कर दिया है और यह रेलवे संरक्षण बल के सहयोग से बाकी गिरोहों को भी नष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न कर रही है ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री महोदय बराबर यह कहते हैं कि ला एंड आर्डर स्टेट का सब्जैक्ट है । रेलवेज जो कि सेंटर का एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कर्तव्य नहीं है कि जो यात्री रेलों पर सफर करें उन की वह रक्षा करे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा तो है कि बावजूद इसके कि यह सब्जैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है फिर भी रेलवेज इस का इंतजाम कर रही है ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले माननीय मंत्री ने बतलाया था कि जो वाकयात हुए । मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक वाक्या हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** जहां तक राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि यह ने केवल उनका उत्तरदायित्व बल्कि उनका ही एकमात्र अधिकार है। जहां कहीं किसी राज्य में केन्द्रीय सरकार के वर्कशाप या कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान हों, वहां शांति और व्यवस्था कायम रखना न केवल उनका उत्तरदायित्व बल्कि उनका ही एक मात्र अधिकार है । लेकिन हम यह न समझें कि वे अपना कर्त्तव्य नहीं करेंगे। उनका पूरा-पूरा सहयोग है लेकिन उसके बावजद रेलवे में जुर्म होते हैं जैसे और किसी जगह भी हो सकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** जनता की नजर में आया है कि रेलगाड़ियों में कुछ गिरोह चीजें बेचने वालों और भिखारियों के तौर पर काम करते हैं और सामान्यतया अपराध करते हैं क्या सरकार ने रेल में सफर करने वाले विक्रेताओं और भिखारियों के ऐसे गिरोहों को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री शाह नवाज खां :** जी हां । समय समय पर ऐसे उदाहरण हमारी नज़र में आये हैं और खासकर ऐसे लोगों के लिए हमने गहरी कार्यवाही शुरू की है ।

दिल्ली में बिजली की समान दरें

†***११७५. श्री शिवचरण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्रों में बिजली, पंखों, घरेलू बिजली और औद्योगिक बिजली की भिन्न-भिन्न दरें हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में समान दरें करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी हां। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा ली जाने वाली दरें अधिक ऊंची हैं।

(ख) नयी दिल्ली नगरपालिका के बिजली विभाग के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल करने और यह सुझाव देने के लिये कि उसकी दरों को दिल्ली नगर निगम द्वारा ली जाने वाली दरों के बराबर घटाया जा सकता है या नहीं, कर शुल्क मंत्रणा समिति नियुक्त की गयी है। उस समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री शिवचरण गुप्त**: क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में ही जैसे नरेला, शाहदरा और बाकी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न दरें हैं ?

†**श्री अलगेशन**: मैं नहीं जानता कि ये क्षेत्र दिल्ली नगर निगम या नयी दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत है। मुझे इसके लिए अलग सूचना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: नयी दिल्ली नगरपालिका का क्या रुख है और क्या उसने इस मामले में अपनी राय केन्द्रीय सरकार को बता दी है और क्या यह समिति उसके परामर्श से बनायी गयी है ?

†**श्री अलगेशन**: जी हां। इस मंत्रणा समिति में नयी दिल्ली नगरपालिका का भी एक प्रतिनिधि है।

†**श्री महेश्वर नायक**: बिजली के घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपभोग के लिए दरों में क्या अन्तर है ?

†**श्री अलगेशन**: नयी दिल्ली नगरपालिका में घरेलू बिजलीघर की दर ६ नये पैसे प्रति किलोवाट घंटा और १ नया पैसा प्रतिकिलोवाट घंटा बिजली कर है। १० किलोवाट घंटे तक वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली के लिए दर १३ नये पैसे प्रति किलोवाट घंटा और १ नया पैसा प्रति किलोवाट घंटा बिजली कर है। औद्योगिक बिजली के लिए १० किलोवाट से ऊपर १०० किलोवाट तक, पहले २००० किलोवाट के लिए माहवार दर दिल्ली बिजली सप्लाई कम्पनी का थोक दर और १०० प्रतिशत ऊपर है।

मिश्र समिति का प्रतिवेदन

*११७६. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी संस्थाओं और पंचायतों के परस्पर सम्बन्धों के बारे में श्री एस० डी० मिश्र के सभापतित्व में नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर विचार पूरा हो गया है

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अभी तक केवल पांच राज्य सरकारों अर्थात् महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू तथा काश्मीर ने ही अपने विचार सूचित किए हैं । अन्य राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी** : ये निर्णय कब किये जायेंगे और सभा पटल पर विवरण कब रखा जायेगा ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और सामुदायिक विकास मंत्री ने स्वत: सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजे हैं । हमें शीघ्र ही उनके उत्तर मिलेंगे । आशा है कि हम जुलाई में अन्तिम रूप से इस विषय पर विचार करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि यह रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद सभी सहकार मंत्री इस रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले थे और यदि हां, तो क्या इस पर चर्चा हुई है और राज्य सरकारों की क्या राय है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : वास्तव में सहकार मंत्रियों ने ३० अक्तूबर, १९६१ को इस रिपोर्ट पर विचार किया था और उन्होंने सामान्य रूप से इस समिति की सिफारिशें मंजूर की थीं । लेकिन यह ठीक समझा गया कि पंचायती राज मंत्रियों से भी परामर्श किये जायें और पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकार विभागों के बीच समन्वय करने में और भी बहुत सी बातें थीं इसलिये इस संपूर्ण प्रलेख पर विचार किया जाये यही उपयुक्त समझा गया । इसीलिये सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस रिपोर्ट के लिये आंकड़े इकट्ठे करने के लिये इस समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा करना उचित समझा था या उसने सिर्फ यही जरूरी समझा कि राज्य सरकारें प्रश्नों का जवाब दे दें ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह एक कार्यकारी दल था । उसे दो महिनों के अन्दर रिपोर्ट देनी थी । यह समिति चार या पांच राज्यों में गयी थी लेकिन वह सभी राज्यों का दौरा नहीं कर सकी । उसने सभी राज्यों को प्रश्न सूचियां भेजी थीं और राज्यों के तथा सहकार संस्थाओं के मत प्राप्त हुये थे ।

†**श्री श्यामलाल सराफ** : क्या इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि संपूर्ण सहकारिता आन्दोलन पंचायतों और उपभोक्ता सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों और भूमि सहकारी समितियों जैसी संस्थाओं से संबद्ध किया जाना चाहिये ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सहकारिता आंदोलन को पंचायती राज आंदोलन के साथ संबद्ध करने का सरकार का विचार नहीं है उसका इतना ही आशय है कि दोहरा काम और परस्पर विरोध दूर करने के लिये दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में नारियल के वृक्षों को नष्ट करने वाला रोग

+

†*११७८. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुनहन :
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'जड़ और तना रोग' नामक एक वृक्ष रोग पिछले पांच वर्षों से केरल में नारियल के वृक्षों को नष्ट कर रहा है ;

(ख) क्या इस रोग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ;

(ग) इस रोग से प्रभावित वृक्षों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(घ) अब तक नष्ट हुये वृक्षों की क्या संख्या है ; और

(ङ) इस रोग को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) राज्य में नारियल के वृक्षों को नष्ट करने वाले दो अलग अलग रोग हैं जिन्हें "रूट (विल्ट)" और "स्टेन ब्लीडिंग" कहा जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस रोग से प्रभावित वृक्षों की ठीक ठीक संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है । अनुमान है कि केरल में नारियल के अन्तर्गत ११ एकड़ जमीन में से ६ एकड़ जमीन में यह रोग फैला हुआ है ।

(घ) नष्ट हुये वृक्षों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ङ) नारियल के पेड़ों के जड़ और तना रोगों का नियंत्रण करने के लिये छिड़काव की एक योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से कार्यान्वित की जा रही है ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या यह योजना वही है जो पिछले पांच वर्षों से चल रही है या वह कोई नयी योजना है ?

†डा० रामसुभग सिंह : जी हां । केरल सरकार और भारत सरकार साथ साथ काम कर रही हैं ।

†श्री अ० क० गोपालन : अभी जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि नारियल के कितने वृक्ष नष्ट हुये हैं वह संख्या सरकार को नहीं मालूम है । लेकिन केन्द्रीय नारियल समिति ने बताया है कि १९५९–६० में लगभग एक लाख पेड़ नष्ट हुये थे । इस बड़ी संख्या को देखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अनुसंधान और छानबीन प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई है, क्या सरकार कोई नयी कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामसुभग सिंह :** यह गलत है कि हमें संख्या मालूम नहीं है। हमें ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं है, लगभग संख्या अवश्य मालूम है। जैसा कि मैंने बताया कि ११ लाख एकड़ में से ६ लाख एकड़ में यह रोग फैला हुआ है। एक एकड़ नारियल बगीचे में लगभग ७० या ८० पेड़ होते हैं और इस तरह हमें नष्ट हुये पेड़ों की संख्या मालूम है। प्रश्न के दूसरे, भाग अर्थात् वह अनुसंधान प्रभावशाली सिद्ध हुआ है या नहीं, के संबंध में यह स्थिति है कि वह पत्ते के रोगों के मामले में प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, जड़ के रोगों के संबंध में नहीं। उस बारे में अभी अनुसंधान जारी है।

†**श्री वासुदेवन नायर :** इस बात को देखते हुये कि अभी तक किया गया सारा अनुसंधान केवल जड़ के रोगों के संबंध में ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है और काफी बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ नष्ट हुये हैं, क्या देश की किन्हीं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अधिक ऊंचे स्तर पर अनुसंधान कराने की सरकार की कोई योजना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में सरकार खाद्य तथा कृषि संगठन से परामर्श कर रही है। यह रोग केवल केरल राज्य में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों, खासकर फिलिपाइन्स और वेस्ट इन्डीज में भी फैला हुआ है। इसलिये कोई तरीका ढूंढ निकालने के संबंध में अनुसंधान करने का कार्यक्रम जारी है। यदि जरूरी हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अनुसंधान कराने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या यह सच है कि अनुसंधान केन्द्र द्वारा चलाये गये नमूने के बगीचों में यह रोग अधिक फैला हुआ है और यदि हां, तो क्या इसका कोई खास कारण है ?

†**डा० रामसुभग सिंह :** यह रोग छः जिलों में फैला हुआ है और हो सकता है कि उन नमूनों के जिलों में यह अधिक गम्भीर हो लेकिन हर जगह कुछ पेड़ नष्ट हुये हैं।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या सरकार ने रेडियो सक्रिय आइसोटोप का उपयोग कर रोग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**डा० रामसुभग सिंह :** कायमकुलम् में हमारे अनुसंधान केन्द्र में यह पता लगा है कि यह रोग इस कारण अधिक व्यापक हो रहा है कि केरल में असाधारण वर्षा हुई है और इस रोग के नियंत्रण के लिये जो खाद आदि इस्तेमाल की जा रही है वह भारी वर्षा के कारण बह जाती है। इसलिये वे भी इस विशिष्ट कारण को रोकने के लिये कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री वारियर :** क्या ये कीटाणुनाशक द्रव्य आकाश से हेलीकोप्टर हवाई जहाजों द्वारा छिड़के जाते हैं या जमीन से पंप के द्वारा छिड़के जाते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में, हवाई जहाजों द्वारा छिड़काव करना संभव नहीं है यद्यपि केरल के लोग गैर-सरकारी तौर पर दो हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह रोग ऐसा है कि हाथ से और मशीनों से खाद देकर इसे रोका जा सकता है क्योंकि इसमें जड़ आदि खोदना होगा और पत्तियों को काटना भी होगा। इसलिये, हवाई जहाजों से यह आसान नहीं होगा। आप छिड़काव कर सकते हैं लेकिन वर्षा के कारण सारा बह जाता है। पत्ते को ठीक ढंग से काटने की जरूरत है और तभी यह रोग रोका जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या यह रोग इसी देश का है या किसी विदेश से आया है ? क्या यह सच है कि ज्यों ही कोई दवा छिड़की जाती है, लालकीड़ा नामक कीड़ा जमीन में घुस जाता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : फिलिपाइन्स, वेस्ट इन्डीज़ और केरल में जो रोग फैला हुआ है वह प्रायः एक-सा ही है लेकिन वह इस अर्थ में देशी भी है कि पिछले ८० वर्षों से यह मौजूद है ।

†**श्री त्यागी** : क्या वह कीड़ा जमीन में चला जात है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जड़ें खराब हो जाती हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि करीब १२ साल पहले कायमकुलम् स्थित अनुसंधान केन्द्र ने खाद्य तथा कृषि संगठन के सामने इस मामले को रखा था ? यदि हां, तो क्या उस संगठन से कोई निदेश प्राप्त हुआ था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : खाद्य तथा कृषि संगठन के तकनीकी कार्यकारी दल ने जिसकी बैठक त्रिवेन्द्रम में हुई थी, यह मालूम किया था कि कायमकुलम् में जो अनुसंधान किया जा रहा था वह ठीक था । उसने यह सुझाव दिया था कि खाद्य तथा कृषि संगठन को उस केन्द्र की मदद करने के लिये कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह मालूम होता है कि यह बहुत पुराना रोग है । यदि ऐसा है तो इन वर्षों में इस रोग को रोकने के लिये सरकार ने कोई सावधानी क्यों नहीं बरती ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में, सावधानी तो नियमित रूप से बरती जा रही है । यह कहना गलत है कि इन वर्षों में कोई सावधानी नहीं बरती गयी है ।

†**डा० मा० श्री अणे** : माननीय मंत्री ने बताया है कि खाद्य तथा कृषि संगठन की किसी समिति ने कहा कि यह अनुसंधान केन्द्र ठीक ढंग से काम कर रहा है । क्या उनका यह कथन उस केन्द्र द्वारा अनुसंधान के परिणामों पर आधारित है या केवल इस कारण है कि वे परिणाम अनुसंधान प्रक्रियाओं के बारे में उनकी कल्पनाओं के अनुरूप हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : खाद्य तथा कृषि संगठन के तकनीकी कार्यकारी दल ने जब यह कहा कि वह अनुसंधान ठीक ढंग से चल रहा है तब वह दूसरे अनुसंधान केन्द्रों को किसी तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं था क्योंकि दुनिया में और कहीं भी ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है । इसलिये केरल की स्थिति के बारे में यही उनकी कल्पना है ।

चावल क्षेत्र

†***११७९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल क्षेत्रों को बिल्कुल समाप्त करने के लिये किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंची है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या पूर्वी क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार किया जायेगा, कि उसमें बिहार भी शामिल हो जाये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा–सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख) चावल क्षेत्रों को बिल्कुल समाप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । यद्यपि सरकार की नीति, जहां कहीं संभव हो, फालतु और कमी वाले क्षेत्रों को मिलाकर चावल क्षेत्रों की संभावना बढ़ाना है किसी न किसी रूप में क्षेत्रीय (जोनल) पद्धति तब तक जारी रहेगी जब तक कि देश चावल में आत्म-निर्भर नहीं हो जाता ।

(ग) जी, नहीं । बिहार को शामिल कर पूर्वी चावल क्षेत्र का विस्तार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा और बिहार के सीमांत क्षेत्रों में मूल्यों में विभिन्नता के कारण, बड़ी मात्रा में तस्कर व्यापार होता है और यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि तस्कर व्यापार न हो ।

†**श्री शिन्दे** : सरकारी जानकारी के अनुसार यह ठीक नहीं है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : मैं सीमांत क्षेत्र से आया हूं और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उड़ीसा के दूसरी ओर अधिक मूल्य होने के कारण.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन्हें इसका अनुभव है तो वह यह जानकारी अलग से मंत्री महोदय को दे दें ।

†**श्री हेडा**: जहां तक चावल का संबंध है, आंध्र प्रदेश को, जहां अत्यधिक फालतू चावल होता है, दक्षिण क्षेत्र में शामिल किया गया है और अब भी दक्षिण क्षेत्र फालतू वाला क्षेत्र है । क्या दक्षिण क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ताकि आंध्र प्रदेश का फालतू चावल इनको मिल सके ?

†**श्री शिन्दे** : सरकार यह नहीं समझती कि दक्षिण क्षेत्र फालतू वाला क्षेत्र है क्योंकि केरल जहां कमी है, दक्षिण क्षेत्र में शामिल है । जैसे की वर्तमान व्यवस्था है, सरकार यह समझती है कि दक्षिण क्षेत्र योजना उचित है और वहां पर फालतू चावल नहीं है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या चावल क्षेत्र के कारण चावल उगाने वाले किसानों को अन्य मंडियों में चालू भाव से कम मूल्य दिये जाते हैं ?

†**श्री शिन्दे** : माननीय सदस्या का विचार सही नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर चावल क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की संभावना है और यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के एक क्षेत्र के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पंजाब का चावल बड़े सस्ते दाम पर बिक रहा है और यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : यह सस्ता है । पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का एक क्षेत्र है। मूल्य पर नियंत्रण के लिये जो कदम उठाये गये हैं, वे काफी संतोषजनक हैं।

राजस्थान के लिये भाखड़ा और चम्बल की बिजली

†**११८१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान अभी तक भाखड़ा और चम्बल की बिजली का अपना अंश इस्तेमाल नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) शीघ्र ही बिजली को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक भाखड़ा का सम्बन्ध है, उपलब्ध बिजली का पूर्ण रूप से इस्तेमाल इसलिये नहीं किया गया, क्योंकि रतनगढ़ और बीकानेर में ग्रिड सब-स्टेशन कुछ आवश्यक सामान जैसे इस्पात के ढांचे, डी० सी० के सामान आदि के देर से प्राप्त होने के कारण जल्दी पूरे नहीं किये जा सके और चालू नहीं किये जा सके। चम्बल के मामले में इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि ग्रिड सब-सेक्शन और ट्रांसमिशन लाइनें अभी बन कर पूरी नहीं हुई हैं ।

(ग) रतनगढ़ और बीकानेर में ग्रिड सब-स्टेशनों के जून, १९६२ तक पूरा हो जाने और चालू हो जाने की आशा की जाती है । चम्बल से बिजली के मामले में ग्रिड सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों पर कार्य जारी है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है, जब कि इससे उपलब्ध सारी बिजली इस्तेमाल की जा सकेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के पूर्ण रूप से इस्तेमाल न किये जाने के कारण इस ओर हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : इसमें हानि का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस्तेमाल न किये जा सकने के कारण यदि इसका इस्तेमाल किया जाता तो कुछ और आय होती । उनका यह मतलब है। क्या कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : यदि बिजली का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता, तो यह ३८ मेगा वाट होती न कि ·२८ मेगावाट ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस बिजली को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने में राजस्थान सरकार को कितना समय लगेगा और यदि इसमें बहुत समय लगेगा, तो क्या सरकार का इस

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली को दिल्ली अथवा अन्य राज्यों में, जहां बिजली की कमी है, भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सै० अ० महदी** : जैसा मैं बता चुका हूं, एक योजना जून में पूरी होने वाली है और दूसरी के शीघ्र ही पूरा होने की आशा है और बहुत थोड़े समय में ही बिजली का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : चम्बल और भाखड़ा से राजस्थान को कितने किलोवाट घंटे बिजली दी गयी और कितने महीनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और यदि इसका इस्तेमाल किया जाता तो इससे कितनी आय होती ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री अलगेशन)** : चम्बल से राजस्थान को २३,००० किलोवाट लेना चाहिये थी वे अब केवल २००० किलोवाट ले रहे हैं। उल्लिखित निर्माण-कार्यों के पूरा होने पर वह पूरी बिजली ले सकेंगे। भाखड़ा से राजस्थान को २१,००० किलोवाट लेना चाहिये था ; वह अब केवल ६,००० किलोवाट ले रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर वह पूरी बिजली ले सकेंगे ।

†**श्री इकबाल सिंह** : भाखड़ा से राजस्थान सरकार को ३१,००० किलो-वाट देने का प्रस्ताव है परन्तु राजस्थान सरकार अब केवल ६,००० किलोवाट ले रही है । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बिजली को अन्य राज्यों में ले जाने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सारी बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं ।

†**श्री अलगेशन** : जी, हां । वह सारी बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं ।

श्री बड़े : ट्रांसमिशन स्टेशन न होने की वजह से चम्बल प्राजैक्ट को, क्या यह ठीक है कि एक लाख रुपये का घाटा हर साल होता है और साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रासमिशन स्टेशन न होने का कारण क्या है ?

श्री से० अ० महदी : जैसे बताया जा चुका है कि बहुत-सा सामान फारेन एक्सचेंज की कमी की वजह से नहीं मिल सका था, इस वजह से देरी हुई ।

श्री बड़े : मेरा सवाल था कि क्या एक लाख रुपये का घाटा होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

†*११८३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए और यह सुझाव देने के लिये कि क्या उन्हें कर सहायता के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता है एक सरकारी समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). इस बारे में परिवहन विकास परिषद् ने एक प्रस्ताव की सिफारिश की है । मामला विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों को, उनकी राय जानने के लिये भेजा गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : राज्य सरकारों को यह प्रस्ताव भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया जा सकता है : वह तो सभी राज्य परिवहन निगमों को आय-कर से छट देना पसन्द करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन राज्य सरकारों ने अब तक किस प्रकार की सहायता मांगी है और इन सहायता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक इस कर-सहायता का सम्बन्ध है, इसको राज्य सरकारों को भेजे बिना यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह सब राज्य निगमों को आय-कर से छूट देना पसन्द करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : किन कठिनाइयों के कारण राज्य उपक्रमों को हानि हो रही है जिससे सरकार को स्थिति का अध्ययन करने के लिये समिति बनानी पड़ी ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, नहीं । कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि प्राथमिक प्रावस्था में निगम लाभ नहीं कमा सकते और और यदि उनसे जब लाभ बहुत कम रहा, आय-कर लिया तो उससे लाभ कम हो जायेगा । वह अवसर था। वित्त मंत्रालय इस विचार से सहमत नहीं था। मैं स्वयं भी यह नहीं समझता कि जब तक वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो जाता, एक समिति किस हद तक लाभदायक होगी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या राज्य परिवहन उपक्रम लाभ नहीं कमा रहे हैं और उन्हें कर-मुक्ति की आवश्यकता है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह बात हर जगह लागू नहीं की जा सकती। प्राथमिक प्रावस्था में कुछ राज्य परिवहन निगम आत्म-निर्भर नहीं हो सकते। जैसे वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, वे लाभ कमाते हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : अब तक कितने राज्य निगम स्थापित किये गये हैं और किन राज्यों में ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे पास नाम नहीं हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि अनेक राज्य सरकारों ने राज्य परिवहन निगम स्थापित कर लिये हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या विभिन्न राज्यों में परिवहन उपक्रम चलाने में कोई एकरूपता है और क्या केन्द्रीय सरकार एकरूपता लाने का प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : एक रूपता बड़ा व्यापक शब्द है । राज्य परिवहन के मामले में एक रूपता लाना संभव नहीं है। जहां तक तरीके का सम्बन्ध है, तरीका लगभग समान

---

†मूल अंग्रेजी में

है। तीन पक्ष हैं—राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार जहां यह रेलवे और परिवहन मंत्रालय के जरिये भुगतान करती है और स्थानीय अधिकारी अथवा गैर-सरकारी पक्ष।

†**श्री वारियर** : वित्त विभाग द्वारा स्थापित किये गये विशेष 'सेल' ने राज्यों में कुछ गैर-सरकारी और सरकारी सड़क परिवहन उपक्रमों की जांच की है। वे राज्य कौन से हैं और कौन से छोड़ दिये गये हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे पास वह जानकारी नहीं है।

नौवहन व्यापार के लिय ब्रिटिश फर्म को ऋण

†११८४. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र के कलकत्ता-आसाम मार्ग पर नौवहन व्यापार करने वाली एक ब्रिटिश फर्म को भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को २ करोड़ रुपये (इण्डिया जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कम्पनीज लिमिटेड और रिवर्स स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड—प्रत्येक को १ करोड़ रुपया) का ऋण देने का निर्णय किया गया है ताकि वे कलकत्ता-आसाम मार्ग पर आवश्यक आई० डब्ल्यू० टी० सेवा के बनाये रखने के लिये पुराने जहाज बदल सकें।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें ऋण देने की शर्तें लिखी हैं। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—१५९/६२)**

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : विवरण में लिखी एक शर्त यह है कि कम्पनी लन्दन में और कलकत्ता में दोनों स्थानों पर—सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जांच के लिये—लेखा रखेगी। क्या मैं जान सकती हूं कि वह प्रतिनिधि कौन है जिसको सरकार ने इन लेखों के परीक्षण के लिये नियुक्त किया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : अभी यह अवसर नहीं आया है क्योंकि कम्पनी को अभी तक कोई रुपया नहीं दिया गया है।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या सरकार को पता है कि ऋण मंजूर करने के बाद, भाड़ा दर में ५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है ?

†**श्री जगजीवन राम** : उस का ऋण से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋण की शर्तों को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है और अभी तक कम्पनी ने कोई रुपया नहीं लिया है।

†**श्री बसुमतारी** : विवरण में यह कहा गया है कि २ करोड़ रुपये के ऋण से वे कुछ जहाज, उपकरण और अन्य सामान खरीदेंगे। किन शर्तों पर यह ऋण वापस लिया जायेगा ? अर्थात्, करार-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार द्वारा ऋण वापस लेने का क्या तरीका होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : करार में सब बातें हैं कि किस प्रकार किश्त वापस की जानी है, भुगतान कब आरम्भ होगा, ब्याज की दर क्या होगी, सरकार ऋण की वसूली किस प्रकार करेगी, आदि; सम्पदा सरकार को बन्धक रखी जायेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच रेलवे लाइन

†**११ श्री प० ला० बारूपाल:** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा और क्या रेलमार्ग मे कोई परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) किसानों की कितने एकड़ जमीन इस रेलवे लाइन के अन्तर्गत आयेगी ; और

(ग) क्या उपरोक्त जमीन के लिये मुआवजा नक़द धन के रूप में अथवा वैकल्पिक जमीन के रूप में दिया जायेगा और यदि वैकल्पिक जमीन दी जायेगी तो यह किन स्थानों पर आवंटित होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जब राजस्थान सरकार ज़मीन का कब्ज़ा उत्तर रेलवे को दे देगी और श्रमदान द्वारा मिट्टी डालने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर लेगी, तो काम तुरन्त शुरू कर दिया जायेगा । अभी से यह नहीं कहा जा सकता यह काम कब पूरा होगा । रेल मार्ग में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ख) लगभग १९४ एकड़ ।

(ग) उत्तर रेलवे राजस्थान सरकार को ज़मीन की कीमत नक़द चुकायेगी । इस बात का निर्णय राजस्थान सरकार को करना है कि ज़मीन के मालिकों को नक़द मुआवज़ा दिया जाय या ज़मीन के बदले में उन्हें कोई और ज़मीन दी जाय ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†***११७१. श्री द० सुब्रह्मण्यम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में यह योजना बनाई गई है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन नहर को मैसूर राज्य में मंगलौर से कुण्डापुर तक बढ़ा दिया जाये और इसे केरल राज्य की पश्चिम तट नहर प्रणाली से मिला दिया जाये ; और

(ख) क्या मुसाफिर और माल ले जाने के लिये नौका-सेवाओं के संचालन और जान व माल की हिफाज़त के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अजय नदी पर बांध

†*११७३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजय नदी पर बांध बनाने के प्रश्न पर बिहार के साथ मतभेद दूर करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय बोर्ड बनाने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव कार्यान्वित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन कैसा होगा ; और

(ग) क्या बोर्ड ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रिक्शा चालक संस्थाएं

*११७७. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्शा चालक संस्थाएं (रिक्शा पुलर्स सोसाइटीज़) बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी एक संस्था मद्रास में स्थापित की जायगी ।

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितनी और कैसी वित्तीय सहायता देने का विचार किया गया है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) मद्रास में एक समिति गठित की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय सरकार निम्न सुविधायें देगी :

(१) राज्य सरकारों को उतना ऋण दिया जायेगा जितना कि वे समितियों को रिक्शाएं खरीदने के लिये देंगी । इस की अधिकतम सीमा २०,००० रुपये प्रति समिति होगी ;

(२) राज्य सरकारों को प्रबन्धकीय व्यय के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु अनुदान । यह सहायता ३ से ५ वर्षों की अवधि में प्रति समिति ६०० रुपये तक दी जायेगी । यह वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के साथ ५० : ५० के आधार पर बांटी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

†*११८०. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३ मार्च, १९६२ को आंध्र प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इतनी कम खपत के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग २२ किलो-वाट ।

(ख) आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई के कारण द्वितीय योजना की कुछ बिजली परियोजनाओं के पूरा न हो सकने के कारण ।

हीराकुद बांध परियोजना

†*११८२. **श्री यो० ना० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद बांध परियोजना द्वारा पीड़ित सभी व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम दी गई है ?

†***सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी तक कुल क्षति पूर्ति के ९० प्रतिशत का भुगतान किया गया है ।

(ख) अब तक ४,३७,७२,६३८.८५ रुपये का भुगतान किया गया है ।

स्कूल स्वास्थ्य समिति की सिफारिश

†*११८५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) क्या स्कूल के बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था से सम्बन्धित सिफारिशें लागू करने को उच्च-प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री डा० सुशीला नायर)**:(क) और (ख). स्कूल स्वास्थ्य समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टर

†*११८६. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशिक्षित तथा अर्ह डाक्टर ग्राम्य क्षेत्रों के दवाखानों में जाना तथा वहां पर काम करना पसन्द नहीं करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को ग्राम्य क्षेत्रों के दवाखानों में राजी से या जबर-दस्ती भेजने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों ने डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिये आकर्षित करने के लिये (१) सेवा की शर्तों में सुधार करने ; (२) लोक-स्वास्थ्य अथवा बिना प्रैक्टिस का भत्ता देने ; और (३) निवास स्थान आदि की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये हैं ।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हताप्राप्त डाक्टरों को राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा दी गयी सुविधाओं और प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६१/६२]**

प्रयाग में मालगाड़ी से रेल कर्मचारियों का कट जाना

†*११८७. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री जि० मंडल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मई, १९६२ को प्रयाग रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर दो "की मैन" माल गाड़ी से कुचल कर मर गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). एक कीमैन और एक गैंगमैन गाड़ी से कुचल कर मर गये । काम करते समय वे सावधान न थे और लाल झण्डी लगा कर उन्होंने अपनी रक्षा नहीं की जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना चाहिए था ।

खड़गपुर से हल्दिया तक रेलवे लाइन

†*११८८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खडगपुर से हल्दिया पत्तन तक की नई लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइन डालने के लिए अपेक्षित भूमि अर्जित करने के बारे में कायवाही की जा रही है ;

(ग) क्या जमीन के मालिकों को कोई मुआवजा दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया जायगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, नहीं । सर्वेक्षण-कार्य हो रहा है ।

(ख) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद लाइन डालने के बारे में निर्णय किये जाने के बाद भूमि अर्जित करने का प्रश्न उठेगा ;

(ग) जी, हां । यह प्रश्न भूमि अर्जित करने के बाद उठेगा ।

(घ) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । भूमि भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की जायेगी । और भूमि आदि के लिये क्षतिपूर्ति भूमि अर्जन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

†*११८९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुभवी अधिकारियों का एक 'पूल' बनाने का है जो देश के बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में अधिक दक्षता से काम करें ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) और (ख). देश में असैनिक हवाई अड्डों का प्रभार असैनिक उड्डयन विभाग पर है और इन हवाई अड्डों पर इस विभाग के पदाधिकारी रहते हैं । इस विभाग के पदाधिकारियों का देश भर में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है । अतः पदाधिकारियों का कोई 'पूल' बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की देखभाल अनुभवी पदाधिकारियों द्वारा की जाती है ।

सड़क परिवहन प्रबन्ध के लिये त्रिदलीय निकाय

†*११९०. **श्री महेश्वर नायक** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों से सड़क परिवहन प्रबन्ध के लिये त्रिदलीय संस्थायें बनाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या प्रस्तावित संस्थाओं का कोई आदर्श विधान बनाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं को कौन से काम सौंपे जा सकते हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

"चम्पावती" यात्री पोत

†*११९१. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० मई, १९६२ को अथवा इस के निकट की किसी तिथि को अंडोवी नदी के मुहाने के निकट बम्बई-पंजिम सेवा का एक यात्री पोत "एस० एस० चम्पावती" उथले पानी में रेत में फंस गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां । १० मई, १९६२ को पंजिम बन्दरगाह में जाते हुए एक यात्री पोत "एस० एस० चम्पावती" रेत में फंस गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बम्बई नौसामुद्रिक नौवहन विभाग द्वारा पोत के जमीन में धंस जाने के कारणों की प्राथमिक जांच की जा रही है ।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†*११९२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध संभरण योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना राजधानी शहर की लगभग ७००० मन दूध प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरी करने के लिये बनाई गई है । यह योजना १५० मन दूध से १ नवम्बर, १९५९ को चालू हुई थी और अब इस में प्रतिदिन ३००० मन दूध की खपत है । यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६४ में यह ७००० मन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†*११९३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार कर्मचारियों को प्रति वर्ष स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये १००० छात्र-वृत्तियां देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर वार्षिक व्यय क्या होगा ; और

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधा अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी देने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) छात्रवृत्ति दे कर तकनीकी अध्ययन के लिये शिक्षा सहायता की योजना विचाराधीन है । इस को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

(ख) लगभग १.५ लाख रुपये व्यय होने की संभावना है ।

(ग) इसके अतिरिक्त कि रेलवे बोर्ड की भी लगभग ऐसी ही योजना है, कोई और जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

मुंगेर जिले को माल-डिब्बों का संभरण न किया जाना

†*११९४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २ मई, १९६२ के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित इस समाचार

---

†मूल अंग्रेजी में

की ओर गया है कि बिहार के मुंगेर जिले में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में विलम्ब रेलवे के कारण हुआ था ; और

(ख) क्या माल डिब्बों का संभरण करने से एकदम इन्कार कर दिया गया था और वहां पर एक भी माल डिब्बे का संभरण नहीं किया गया था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । यह बिहार राज्य के मुंगेर जिले में ईंट भट्टों को कोयले के संभरण के बारे में है ।

(ख) जी, नहीं। बाढ़ सहायता के लिये बिहार राज्य के लिये कोयला नियंत्रक ने जो भी आवंटन मंजूर किया था, वह रेलवे ने मार्च को छोड़ कर जबकि, कोयला खानों में इन्डेन्ट की कमी के कारण अधिक लदान नहीं हुआ, मार्च, १९६२ से मई, १९६२ की अवधि में रेलवे ने वह क्रियान्वित किया ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैंसरियां

†*११९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैंसरियों में लोगों को डाक्टरी जांच करवाने के लिए तथा दवाई लेने के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं तथा प्रतीक्षावधि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि विश्वविद्यालय

†२१६८. **श्री कर्णी सिंहजी :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के उत्तरी भाग में, जहां तीन नहरें हैं और प्रदर्शन कार्य के लिये देश में सब से बड़ा सूरतगढ़ फार्म है, यह विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना की जांच की गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि विश्वविद्यालय के स्थान के बारे में निर्णय करना राज्य सरकार का काम है । उदयपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय करने में प्रमुख बात वहां पर उपलब्ध सुविधायें हैं जैसे कृषि कालिज और गृह-विज्ञान कालिज का होना जोकि राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के संवैधानिक कालिज होंगे ।

उड़ीसा में आदिम जातीय खंड

†२१६९. **श्री उलाका** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने

---

†मूल अंग्रेजी में

की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में उड़ीसा में कितने आदिमजातीय खंड स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) क्या पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायतों और पंचायत समितियों में आदिमजातीय प्रतिनिधियों के लिये संरक्षण की कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) ६० ।

(ख) ३०५.१८ लाख रुपये ।

(ग) ग्राम पंचायत:—वार्डों का इस प्रकार विभाजन किया गया है कि उस में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का प्रतिनिधान हो सके ।

पंचायत समितियां :—समिति के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जबकि चुने हुए सदस्यों में वे लोग नहीं हैं, एक सदस्य अनुसूचित जातियों का और एक सदस्य अनुसूचित आदिम जातियों का, यदि उन की जनसंख्या कुल जनसंख्या से ५ प्रतिशत से कम नहीं है, चुना जायेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुपारी के वृक्षों का नष्ट होना

†२१७०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 'महाली' रोग से सुपारी के वृक्ष नष्ट होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जहां ऐसा होता है और नष्ट होने को क्या मात्रा है ; और

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण मालाबार, केरल में कोचीन का भाग, पश्चिम मैसूर, मैसूर के दक्षिण और उत्तर कनारा जिले और महाराष्ट्र ।

नष्ट होने की मात्रा का अनुमान कुल उत्पादन का २५ प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत तक लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मौनसून से पूर्व (मई के अन्त में) एक प्रतिशत बोरड़योक्स मिश्रण से सुपारी की शाखाओं में छिड़काव कर दिया जाता है। जुलाई-अगस्त में वर्षा रुकने पर यह छिड़काव फिर किया जाता है ।

'महाली' रोग से पीड़ित फसल वाले क्षेत्र में उपरोक्त उपाय से ७५ प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत तक फसल बचा ली गई है ।

केरल में बीमारियों के कारण काली मिर्च के पौधों का नष्ट होना

†*२१७१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ बीमारियों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि में काली मर्च के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि होती है ;

(ग) क्या इस मामले मे और बीमारी को रोकने के लिये उपचारिक उपायों के सम्बन्ध में कोई विशेष जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). केरल मे कुछ कालो मिर्च के वृक्षों को 'पोल्लू' और 'विल्ट' आदि बीमारियां लग जाती हैं किन्तु नीचे दिये गये आंकड़ों के आधार पर उपज मे कोई अधिक कमी नहीं होतो :—

	वर्ष	उत्पादन (टन)
(दूसरी योजना अवधि)	१९५६-५७	२८,८००
	१९५७-५८	२६,०००
	१९५८-५९	२५,०००
	१९५९-६०	२४,९००
	१९६०-६१	२६,६००
(तीसरी योजना का पहला वर्ष)	१९६१-६२	२६,५५०

(ग) और (घ). जी हां, अन्वेषण किया गया है और काली मिर्च अनुसन्धान केन्द्र, मनीपुर में किया भी जा रहा है । राज्य कृषि विभाग ने, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित काली मिर्च अनुसन्धान योजना के प्रविधिक कार्यक्रम के बारे में काम को गहन करने का विचार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५० प्रतिशत जुलाई के अन्त तक डी० डी० टी० छिड़कने और उसके पश्चात् महीने में एक बार, आवश्यकतानुसार दो या तीन बार डी० डी० टी० छिड़कना 'पोल्लू' बीमारी के लिये बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ है ।

'विल्ट' बीमारी के बारे में वृक्ष के सभी 'विल्ट' द्वारा प्रभावित अंशों को हटा कर और जला कर ताकि आगे न फैले, समूचे वृक्ष पर एक प्रति शत बोर्डेक्स मिक्सचर छिड़कना और छः गैलन पानी में एक औंस 'केरेसन' (गोला) को मिला कर भूमि को गीला करना, इस बीमारी को रोकने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं ।

राज्य कृषि विभाग द्वारा जिन नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई है तथा जो प्रभावी सिद्ध हुए हैं, उनका व्यापक प्रचार किया गया है ।

कीटनाशक दवाई छिड़कने के उपकरण उपयुक्त स्थानों पर रखे जाते हैं और किसानों को दिये जाते हैं । उपरोक्त नियंत्रण उपायों के परिणामों को देखा जाता है और उनसे यथासमय अच्छे परिणाम निकलने की आशा की जाती है ।

केरल में काली मिर्च का उत्पादन

†२१७२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काली मिर्च का कुल उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) १९५९–६० और १९६०–६१ में वर्षवार कितना निर्यात हुआ है ;

(ग) यदि उत्पादन में कमी हुई है तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) १९५९–६० और १९६०–६१ में निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) केरल में १९६१–६२ में काली मिर्च का कुल उत्पादन २६,५५० टन था ।

(ख) भारत से १९५९–६० और १९६०–६१ में निर्यात इस प्रकार हुआ है

वर्ष	मात्रा '०००' किलोग्रामों में
१९५९–६०	२०६७२
१९६०–६१	१७२०२

(ग) १९६०–६१ में उससे पहले वर्ष १९५९–६० के उत्पादन की तुलना में लगभग ०.२ प्रतिशत की बहुत मामूली कमी हुई है । केरल राज्य में इन दो वर्षों में उत्पादन इस प्रकार हुआ है :—

वर्ष	उत्पादन
१९६०–६१	२६६०० टन
१९५९–६०	२६५५० ,,

फूल आने और फसल के पकते समय मौसम खराब होने के कारण लगभग २० टन की कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५९-६० और १९६०-६१ में कमाई गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार थी :—

वर्ष	मूल्य "०००" रुपयों में
१९५९-६०	८१८१२
१९६०-६१	८४९७०

काली मिर्च के दाम

†२१७३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री पोट्टे काट्टु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में काली मिर्च के भाव क्या थे ;

(ख) इस समय बाजार भाव क्या हैं ; और

(ग) यदि भाव गिर गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पिछले तीन वर्षों में महीने के आखीर में चुने हुए स्थानों अर्थात् कोचीन और मद्रास में काली मिर्च के दामों का विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) मई, १९६२ के महीने के अन्त की कीमत कोचीन में ११४.०२ रुपये मन थी।

(ग) काली मिर्च के चालू दाम १९६० और १९६१ के दामों की तुलना में कम है किन्तु १९५९ के दामों से अधिक है। १९६० और १९६१ में दाम अधिक थे क्योंकि इन्डोनेशिया में उत्पादन कम होने के कारण हमारे निर्यात की मांग अधिक थी।

करियानकोड पुल

†२१७४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री पोट्टे काट्टु :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट सड़क पर करियानकोड पुल पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ग) काम कब आरम्भ किया गया था ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं।

(ख) मार्च, १९६३ तक पुल पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) १९५५ के आरम्भ में।

(घ) इस पुल का काम अनुसूची के अनुसार नहीं बढ़ सका, क्योंकि निर्माण करते हुए यह पाया गया कि चट्टान पर्याप्त गहराई पर उपलब्ध नहीं थी और जो मिट्टी वहां मिली उसकी पुल संभालने

†मूल अंग्रेजी में

की क्षमता इतनी कम थी कि वहा प्रारम्भ में सोचे गये ८२ फुट के स्पैन (विस्तार) को सहार नहीं सकती थी। इसलिये पुल के डिजाइन में बहुत परिवर्तन करना पड़ा। इस कारण काम जुलाई, १९५७ से मई, १९५९ तक बन्द रहा। अब काम प्रगति पर है।

करल में राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

†२१७५. **श्री म० क० कुमारन**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजपथ पर कितते पुल बनाये जा रहे हैं ;

(ख) निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) पांच (१) ब्योट्टापल्ली पुल।

(२) डाना पाडी पुल (३) वारीपुजहा पुल।

(४) कन्नेट्टिल पुल (५) मालाली पुल।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाठ्य विषय के रूप में सहकारिता

†२१७६. **श्री उलाका** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनमें पाठ्य विषय के रूप में सहकारिता को चालू करने की उनके मन्त्रालय ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने वाणिज्य उपाधि-पाठ्यक्रम में 'सहकारिता' को एक पृथक् वैकल्पिक विषय के रूप में जारी कर दिया है ;

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली में फरवरी, १९६२ में सहकारिता विषय पर हुई राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था ; और

(घ) उक्त प्रतियोगिता में कौनसा विश्वविद्यालय प्रथम रहा था ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) मन्त्रालय ने शिक्षा मन्त्रालय के परामर्श से यह फैसला किया है कि सहकारिता का विषय निम्न तरीके से स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जारी किया जाना चाहिये :—

(१) पहले से पांचवें दर्जे तक सरल कहानियों के द्वारा सहकारिता की पढ़ाई।

(२) ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये (छटे से आठवें दर्जे) तक समाज शास्त्र के विषय में इस विषय का अधिक विस्तृत वर्णन।

(३) उच्च माध्यमिक स्तर पर समाजशास्त्र के मुख्य विषय में सहकारिता के प्रारम्भिक ज्ञान का समावेश।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) बी० काम०, बी० कार्य (आनर्ज), बी० ए० में सहकारिता का वैकल्पिक विषय लगाना और सहकारिता तथा संबद्ध विषयों में बी० ए० (आनर्ज) उपाधि पाठ्यक्रम जारी किया जाना ।

(५) स्वातकोतर स्तर पर सहकारिता के विषय के गहन अध्ययन के लिए व्यवस्था जहां सहकारिता अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान आदि शिक्षाओं की एक शाखा हो सकती है ।

(६) पड़ौसी सहकारी संस्थाओं, सहकारिता के ऊपर निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, सहकारी स्टोर स्थापित करना तथा सहकारिता संबंधी अन्य पाठयक्रमातिरिक्त कार्यवाइयां करना ।

तदनुसार राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की गई है कि वे कालिजों और स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर सहकारिता का अध्ययन जारी करें। विविध राज्यों और विश्वविद्यालयों की इस प्रस्थापना के संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया रही है।

(ख) निम्न विश्वविद्यालयों में उन के वाणिज्य उपाधि पाठ्य क्रम में सहकारिता का एक पृथक विषय है :—

१. बंबई
२. गुजरात
३. आनन्द
४. बड़ौदा
५. आंध्र
६. अन्नामलाई
७. अलाहाबाद
८. केरल
९. गोरखपुर
१०. मद्रास
११. विक्रम
१२. बनारस
१३. लखनऊ
१४. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
१५. पटना
१६. उत्कल
१७. उस्मानिया
१८. मराठवाड़ा
१९. आगरा

(ग) निम्न विश्वविद्यालयों ने फरवरी, १९६२ में हुई सहकारिता संबंधी राजकीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था :—

१. आगरा विश्वविद्यालय
२. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली
३. वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
४. पटना विश्वविद्यालय
५. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
६. अलीगढ़ विश्वविद्यालय
७. एम० एस० विश्वविद्यालय
८. जादवपुर विश्वविद्यालय
९. आंध्र विश्वविद्यालय
१०. दिल्ली विश्वविद्यालय
११. उत्कल विश्वविद्यालय
१२. राष्ट्रीय ग्राम्य उच्च शिक्षा संस्था

(घ) जादवपुर विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम रहा था ।

मद्रास राज्य में पीने के पानी का संभरण

†२१७७. **श्री राजा राम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मद्रास राज्य में पीने के जाल के वितरण के लिए कितनी राशि रखी गई थी;

(ख) राज्य सरकार की मांग कितनी थी; और

(ग) कितनी योजनाएं इस में शामिल हैं और कितन गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता संबंधी योजनाओं के लिए १.५० करोड़ रुपये और नगरीय के लिए ९.५० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इस के अतिरिक्त ग्राम्य जल संभरण के लिए व्यवस्था स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई है ।

(ख) राज्य सरकार ने ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजनाओं के लिए ६.५० करोड़ और नगरीय योजनाओं के लिए २०·७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है ।

(ग) नगरीय कार्यक्रम के अन्तर्गत २४ जल संभरण और तीन नाली योजनाएं पूरी की जाएंगी जो दूसरी योजना में आरंभ की गई थीं । इस के अतिरिक्त ४७ नवीन जल संभरण और ११ नाली योजनाएं आरंभ की जाएंगी ।

ग्राम्य प्रक्रम के अन्तर्गत, ६५२० कूंएं लगाए जायेंगे और २९६ मिली जुली योजनाएं आरंभ की जाएंगी । इन के अतिरिक्त जल संभरण सुविधाओं की ६८२ गांवों में व्यवस्था की जाएगी जो गियाना कीड़ा बीमारी से प्रभावित हैं । राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ६५६ गांवों में योजनाएं पूरी होने की संभावना है ।

होगनक्कल परियोजना

†२१७८. **श्री राजा राम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने होगनक्कल परियोजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी थी; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) होगनक्कल परियोजना के निर्माण में सहायता देने के लिए मद्रास सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजीपुर डाकखाने का भवन

२१७९. **श्री सरजूपाण्डेय** : क्या **परिवहत तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) के मुख्य डाकघर का नया भवन बनाने का प्रस्ताव १९५८ से ही विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके बनाने में क्या कठिनाई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां ।

(ख) इमारत बनाने के लिए गाज़ीपुर अफीम फैक्टरी से ज़मीन प्राप्त कर ली गई है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रारम्भिक नक्शा की प्रतीक्षा की जा रही है।

गोरखपुर डिवीजन में टलीफोन कनेक्शन

२१८० **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर डिवीजन में मुख्य बाजारों, कस्बों तथा तहसीलों से टलीफोन कनेक्शन के लिये १९५८ से अब तक कितने प्राथना-पत्र मिले हैं;

(ख) उनमें से कितने कनेक्शन दिय गये हैं ; और

(ग) कितने कनेक्शनों के लिए प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३**]

उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था

२१८१ **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए कोई धन राशि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां, उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगर जल प्रदाय और सफाई योजनाओं के लिए १०४६.८४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं की जल प्रादाय योजनाओं के लिए ३३५.३२१ लाख रुपये की एक राशि अस्थायी रूप से निर्धारित की है ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

२१२८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण हेतु १९६२-६३ में कोई धन राशि मांगी है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) ९८.०० लाख रुपये ।

(ग) विविध राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए १९६२-६३ के बजट अनुक्लन में ९·४३ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का विचार है । इस निधि का राज्य-क्रम आवंटन विचाराधीन है ।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ

†२१८३. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य की दूसरी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अंतर्गत कौन-कौन परियोजनायें शामिल की गईं ;

(ख) योजना-काल के अन्त में ऐसी कितनी परियोजनायें कार्यान्वित की गईं और कितनी परियोजनायें बाकी रह गईं ;

(ग) समूचे रूप में कितने प्रतिशत सफलता मिली ;

(घ) तीसरी याजना में क्या नई योजनाएं आरम्भ की जा रही है ; और

(ङ) क्या भोपाल को जयपुर से एक राष्ट्रीय राजपथ द्वारा मिलाने का प्रस्ताव है जो कोटा होकर जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) और (ख). राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक सौ एक राष्ट्रीय राजपथ संबंधी कार्य शामिल किये गये थे जिनमें से सत्तावन कार्य पहली पंच वर्षीय योजना से लिये गये थे । इनमें से दूसरी पंच वर्षीय योजना में छयासठ कार्य किये गये और पैंतीस कार्य होने बाकी रहे। इन कार्यों का ब्यौरा सलंग्न विवरणों में दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–१६२/६२]**

(ग) तिहत्तर प्रतिशत ।

(घ) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–१६२/६२]**

(ङ) नहीं ।

जूनागढ़ का अनुस्थापन तथा अध्ययन केन्द्र

†२१८४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह तताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़ का अनुस्थापन तथा अध्ययन केन्द्र केन्द्रीय सरकार के अधीन है ;

(ख) केन्द्र किन-किन विषयों में प्रशिक्षण देता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्र में किस प्रकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्र सामुदायिक विकास, उसके दर्शन तथा विस्तार प्रविधियों, दल संगठन और सामूहिक संगठन, सामूहिक विकास प्रोग्राम के अनेक पहलुओं का विकास तथा जानकारी, प्रोग्राम आयोजन, कार्यपालन प्रशासन तथा निर्धारिण का अनुस्थापन कार्य तथा प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण देता है ।

(ग) अनुस्थापन प्रशिक्षण खण्ड विकास अधिकारियों, विस्तार अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिया जाता है । अध्ययन के पाठ्यक्रमों द्वारा प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण टेक्निकल विभागों के ज़िला अध्यक्षों, खण्ड विकास अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिया जाता है ।

(घ) पाठ्यक्रम	१९६०–६१	१९६१–६२
अनुस्थापन पाठ्यक्रम . .	१९७	१६८
कार्य पाठ्यक्रम .	११२	४३
अध्ययन पाठ्यक्रम . .	४४	५२

चीनी का उत्पादन

†२१८५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष १९६१–६२ में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी अवधि में आन्ध्र प्रदेश से कुल कितनी चीनी निर्यात की गई ; और

(ग) उसका मूल्य कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) १.८४ लाख मीट्रक टन (१ नवम्बर से १५ मई, १९६२ तक) ।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में निर्यात के लिए छोड़ी गई मात्रा में १६,१६४ मीट्रक टन आन्ध्र प्रदेश के कारखानों के लिए रखा गया था ।

(ग) चीनी का तट पर्यन्त निःशुल्क मूल्य लगभग १.७३४ रु० प्रति मीट्रक टन है ।

चावल का उत्पादन

†२१८६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उसी अवधि में अन्य राज्यों को कुल कितना चावल भेजा गया ; और

(ग) उसका कितना मूल्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** (क) लगभग ३६ लाख टन ।

(ग) और (घ). लगभग ४.४३ लाख टन जिसका मूल्य लगभग २८ करोड़ रुपये था ।

आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज

†२१८७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना-काल में आन्ध्र प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज खोले जायेंगे ; और

(ख) कालेज कहां-कहां खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना-काल में कोई नया चिकित्सा कालेज खोलने का आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

२१८८. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अब तक देश के किन-किन नगरों में लागू की जा चुकी है ; और

(ख) क्या चालू वर्ष में इस योजना के कुछ और नगरों में लागू होने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) दिल्ली ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को केवल बम्बई शहर में चालू करने का विचार है ।

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

†२१८९. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तीसरी पंच वर्षीय योजनाकाल में उड़ीसा के कितने गांवों में बिजली लगाने का विचार है ; और

(ख) गांवों में किन अनेक विद्युत व्यवस्थाओं से बिजली दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग दो सौ ।

(ख) हीरा कुद-तलचर ग्रिड, मचकुण्ड बिजली व्यवस्था और डीजिल से चलने वाले पृथक बिजली घरों से ।

उड़ीसा में ग्रामीण जल संभरण योजना

†२१९०. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में कितनी ग्रामीण जल संभरण योजनाएं लागू की जायेंगी ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) ऐसी कितनी योजनायें हैं और केन्द्रीय सरकार ने अब तक कुल कितना धन दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रखी जायेगी ।

उड़ीसा में चेचक और हैजा

†२१९१. **श्री उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष १९५९ से वर्ष १९६२ में अब तक, प्रतिवर्ष, उड़ीसा में कितने व्यक्तियों को चेचक, छोटी चेचक और हैज़ा हुआ ;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु उपरोक्त रोगों से हुई ; और

(ग) उपरोक्त छूत के रोगों की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). छोटी चेचक (चिकन पॉक्स) के रोगियों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह अधिक ध्यान देने योग्य रोग नहीं है ।

चेचक (स्माल पॉक्स) और हैज़ा संबंधी आवश्यक जानकारी निम्न है :—

	१९५९		१९६०		१९६१		१९६२	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
बड़ी माता .	८,०३४	१,९५४	१,६०३	२६६	२९६	१७	३४२	७२
हैज़ा . .	१९५	१०१	९८	४५	९१०	३७५	१२७	४३

(ग) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६.८८ करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है । इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि तीन वर्ष में समूची जन-संख्या को चेचक के टीके लगाये जायें । केन्द्रीय सरकार प्रोग्राम का अनावर्तक व्यय पूरा और आवर्तक व्यय ७५ प्रतिशत पूरा करेगी । भारत सरकार राज्य सरकारों को अपेक्षित मात्रा में जमा हुआ सूखा टीका भी देगी जो बिना किसी मूल्य के रूस से मिल रहा है ।

हैज़ा पर नियन्त्रण और अन्तिम समापन केवल चहूं ओर के वातावरण की स्वच्छता से हो सकता है । इसके लिये विशेष आवश्यकता इस बात की है कि कूड़ा ठीक से हटाया जाये और समाप्त किया जाये एवं जिन क्षेत्रों में हैज़ा महामारी का रूप लेता है वहां सुरक्षित जल उपलब्ध किया जाये । दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सरकार को ८ उपनगरीय जल सम्भरण और एक नाली योजनाओं को लागू करने के लिये ऋण रूप में ५३.०० लाख रु० दिये गये थे । वर्ष १९६१–६२ में राज्य को २३.८७ लाख रु० का ऋण दिया गया ।

राज्य की ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिए अभी तक राज्य को पहिली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्रमानुसार ६.०० लाख रु० और ५४.०६ लाख रु० के सहायता अनुदान दिये गये ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में परिवार नियोजन केंद्र

†२१९२. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितने केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(घ) उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशोला नायर)**: (क) से (घ). कहा जाता है कि उड़ीसा में नगरों में २८ और गांवों में ६० परिवार नियोजन केन्द्र हैं। अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में सड़कों का विकास तथा विस्तार

†२१९३. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य को सड़क विकास योजनाओं के लिये मार्च, १९६२ तक उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से कितना अनुदान प्राप्त हुआ ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि उसे राज्य में सड़कों के विकास तथा विस्तार के लिये अधिक वित्तीय सहायता दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ७७.८४ लाख रु०।

(ख) और (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) संचम से १६ लाख रु० दिये गये हैं। इस राशि से किये जाने वाले कार्यों का प्रोग्राम जुलाई, १९६१ में राज्य सरकार से मांगा गया था। यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†२१९४. **श्री उलाका** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सड़क परिवहन का विकास शिक्षा और परिवार नियोजन को प्राथमिकता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण परिवहन तथा संचार में उड़ीसा के पिछड़ेपन की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) हालांकि उच्चतम प्राथमिकता कृषि को दी जाती है, जिसमें पशु पालन और गांवों का औद्योगीकरण शामिल है, सड़क परिवहन शिक्षा और परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रोग्रामों पर भी उचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में उल्लेख है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) और (घ). ग्रामीण परिवहन तथा संचार के मामलों पर मुख्यकर राज्य सरकारें तथा पंचायती राज्य सरकारों कार्यवाही करती हैं। जहां कहीं आवश्यक और व्यावहारिक होता है वहां केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के प्रोग्राम के अनुसार दी जाती है।

पटना में चलते फिरते डाकघर

†२१९५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में चलते फिरते डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब अन्तिम निश्चय हो जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात के पैकिंग के नियम

२१९६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में इस्पात के पैकिंग के नियम ऐसे सख्त हैं कि इस्पात के कारखाने वालों को एक रुपया प्रतिटन अधिक व्यय करना पड़ता है ;

(ख) क्या इन नियमों में उचित हेर-फेर करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) उठाईगीरी की घटनाओं को कम करने और रास्ते में माल की कथित कमी के प्रश्न को लेकर माल भेजने वाले, पाने वाले और रेलवे के बीच झगड़ा रोकने के उद्देश्य से पैकिंग की शर्त निर्धारित की गयी है। यह शर्त भूतपूर्व इस्पात, लोहा और ईंधन मन्त्रालय की सलाह से एगल, छड़, राड आदि ढांचा बनाने के काम आने वाले कुछ हल्के लोहे या इस्पात के लिए निर्धारित की गयी है जब वे खले माल-डिब्बों में लादे जाते हैं। पैकिंग की इस शर्त के अधीन जो माल भेजा जाता है, उस पर लोहा और इस्पात नियन्त्रक ने पंजीकृत उत्पादकों को उपभोक्ताओं से प्रति टन १ रुपया अधिक लेने की अनुमति दी है। लेकिन पैकिंग की यह शर्त अनिवार्य नहीं है।

(ख) जी नदीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

२१९७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है ;

(ख) आयुर्वेद के उच्चस्तरीय पठन-पाठन के लिये भी क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ;

(ग) श्रीलंका में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिये जो परीक्षण और प्रबन्ध किये जा रहे हैं, सरकार के पास क्या उन से लाभ उठाने को कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ) आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिये लंका सरकार का किस प्रकार के परीक्षण तथा प्रबन्ध करने का विचार है, भारत सरकार उसके बारे में अनभिज्ञ है।

'आर्गन क्रोमेटोग्राफ'[1]

†२१९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आर्गन क्रोमेटोग्राफ' नामक नई इलैक्ट्रानिक यन्त्र का आविष्कार ब्रिटेन में किया गया है जिससे २० मिनटमें गर्भवती स्त्री के शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्व रेलवे के कंकिनाड़ा और श्यामनगर स्टेशनों के बीच हाल्ट

†२१९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्व रेलवे के कंकिनाड़ा और श्यामनगर स्टेशनों के बीच एक हाल्ट बनाने की कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विचार किस स्थिति में किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) और (ख). कंकिनाड़ा और श्यामनगर स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी हाल्ट बनाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु पर्याप्त कारण न होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी।

फिर भी सेक्शन का विद्युतीकरण होने के बाद जो कि आजकल हो रहा है, इस मामले की पुनः जांच की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Argn Chromatograph.

बीकानेर रेलवे वर्कशाप श्रमिकों के लिये रेलगाड़ी

२२००. **श्री प० ला० बारुपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों को ले जाने और लाने वाली वर्कमैन ट्रेन में प्रति दिन कितने व्यक्ति सफर करते हैं;

(ख) उक्त वर्कमैन ट्रेन का प्रति दिन का खर्चा कितना पड़ता है;

(ग) क्या यह सच है कि काम के घंटों के समय बीकानेर स्टेशन पर जोधपुर, रतनगढ़ तथा भटिण्डा की ओर से गाड़ियां आने के कारण कर्मचारियों को वर्कशाप ले जाने वाली वर्कमैन ट्रेन लाइन साफ न होने के कारण कई बार लेट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रेलवे वर्कशाप में काम का नुकसान होता है; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) लगभग ५०० कर्मचारी ।

(ख) ४७ रुपये ८४ नये पैसे ।

(ग) और (घ). पिछले तीन महीनों में यह गाड़ी बीकानेर से ठीक समय पर चली और कारखाने में पहुंचने में कोई देर नहीं हुई । इसलिए गाड़ी के देर से पहुंचने के कारण काम के घंटों के नुकसान का सवाल नहीं उठता ।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों का स्थानांन्तरण

२२०१. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे वर्कशाप, बीकानेर में कितने ऐसे अधिकारी व क्लर्क हैं जो गत १० या १५ वर्षों से उसी वर्कशाप में स्थायी रूप से पदासीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से कई व्यक्तियों के कई बार स्थानान्तरण के आदेश हुए, पर उन्होंने किसी प्रकार स्थगित करवा लिये या वापस कर दिये गये; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को एक ही स्थान पर रखने का कारण क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

	अफसर	क्लर्क
१० वर्ष .	कोई नहीं	२७
१५ वर्ष .	कोई नहीं	१२

(ख) जी नहीं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

लेखा विभाग में क्लर्क

†२२०२. **श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खण्ड रेलों के लेखा विभागों में क्लर्कों की बड़ी संख्या को "परिशिष्ट २-क" परीक्षा पास करने पर न तो पदोन्नति मिली है और न ही ऊंचे वेतन-क्रम दिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन क्लर्कों को भविष्य में "परिशिष्ट २-क और ३-क" परीक्षायें पास करने के लिए अन्य क्या प्रोत्साहन दिये जायेंगे; और

(ग) क्या किसी अन्य विभाग को उनकी सेवायें देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) हां, "परिशिष्ट २-क" केवल अर्हकर परीक्षा है और इस अर्हकर परीक्षा के आधार पर उच्चतर पदों के लिए पदोन्नति पद रिक्त होने पर निर्भर करती है ।

(ख) "परिशिष्ट २-क परीक्षा" पास करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है परन्तु पदोन्नति होने पर वेतन के उच्च-निर्धारण का लाभ अग्रिम वार्षिक वेतन-वृद्धि देकर दिया जाता है । "परिशिष्ट ३-क परीक्षा" पास करने पर प्रोत्साहन के रूप में वेतन-क्रम में वार्षिक वेतन-वृद्धि बढ़ी हुई दर पर दी जाती है ।

(ग) नहीं । परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के ऋण के अन्य विभागों की प्रार्थनाओं पर रेलवे प्रशासन की आवश्यकतानुसार विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली में पानी का संभरण

†२२०३. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए राम गंगा परियोजना से पानी प्राप्त करने का कुछ प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). दिल्ली में पीने के पानी की उपलब्धि सुस्थिर करने तथा बढ़ाने सम्बन्धी टेक्निकल समिति की एक सिफारिश यह है कि दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र के लिए राम गंगा परियोजना से १०० से २०० क्यूसेक जल प्राप्त किया जाये । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे परियोजना के पूरे होने तक कोई वचन नहीं दे सकते । इस विषय पर उस सरकार के साथ आगे वार्ता की जा रही है ।

वन उत्पाद

†२२०४. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इस वर्ष त्रिपुरा के सोनामुरा सब-डिविज़न में स्थित 'आशाबाड़ी फारेस्ट बीट आफिस' से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों में वन उत्पादों को एकत्रित करने के लिए निःशुल्क परमिट बड़ी संख्या में बांटे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को कोई परमिट नहीं दिया गया है। परमिट त्रिपुरा के वास्तविक निवासियों को ही दिये गये हैं जैसा कि नियमों में उपबन्धित है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विजयवाड़ा और मद्रास के बीच रेलवे लाइन

†२२०५. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विजयवाड़ा और मद्रास के बीच दोहरी लाइन का कार्य कब समाप्त होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा के पास दूसरी पुल के निर्माण को छोड़ कर, जिसके लिए आशा है कि वर्ष १९६४ के अन्त तक पूरा हो जायेगा, कार्य वर्ष १९६३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

चीनी के कारखाने

†२२०६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लिमिटेड कम्पनियों ने चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए कई वर्ष पहिले लाइसेन्स लिये थे परन्तु उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों में से कुछ कम्पनियों को ऋणकं रूप में काफी बड़ी सरकारी धन राशि दी गई है परन्तु फिर भी वे कारखाने नहीं बना सके हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी के कारखाने स्थापित करने या ऋण वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्। ऐसी चार कम्पनियां हैं। इन में से दो कम्पनियों के कार्य में काफी प्रगति हुई है और शेष दो कम्पनियों के लाइसेंस रद्द करने की बात विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इन में से दो उपक्रमों को ऋण-सहायता दी गई है। इन में से एक अपेक्षित संयंत्र व मशीनरी का प्रबन्ध कर लिया है और कारखाने की इमारत, आदि भी बना ली है। इस के उपक्रम ने बहुत थोड़ी प्रगति की है और ऋण की वसूली के लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

मदुरै शहर में मंगलम्मल चतराम का सुधार

†२२०७. { **श्री बाल कृष्णन्** :
श्री व० क० रामस्वामी

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै शहर में 'मंगम्मल चतराम' की उन्नति के लिये सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). तीसरी योजना अवधि के लिये पर्यटन की योजना में मदुरै में रानी मंगम्मल चतराम" के सुधार के लिये १,२५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। सुधार कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को व्यय का ५० प्रतिशत सहायता के रूप में देगी। मद्रास सरकार ने बताया है कि १९६१-६२ में उन के द्वारा सुधार कार्य पर १००० रुपये खर्च किये जाने की संभावना है। इसलिये उन को ५०० रुपये की सहायता दी गई थी। तथापि दर-अनुसूची तैयार न किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रविधिक मंजूरी न दिये जाने के कारण, वास्तव में व्यय नहीं किया गया। केन्द्र ने जो सहायता दी है वह राशि १९६२-६३ के व्यय में केन्द्रीय सरकार के हिस्से में समायोजित कर दी जायेगी।

मूंगफली खाद्य संयंत्र

†२२०८. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर में खाये जाने वाले मूंगफली खाद्य का संयंत्र स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या संयंत्र गैरसरकारी क्षेत्र में है ; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने दिया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** (क) खाने योग्य मूंगफली का आटा बनाने के लिये प्रति दिन १० टन की क्षमता का एक संयंत्र कोयम्बटूर में स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ख) संयंत्र सम्पूर्णतया गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं, अपितु वह भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनीकेफ) और एक गैर-सरकारी तेल मिल के संयुक्त सहयोग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

(ग) मुख्य शर्तें हैं कि गैर सरकारी सहयोगी को अपनी निजी कच्चे माल और कार्यवहन व्यय, भूमि और इमारत, देशी उपकरण आदि में लगानी चाहिये तथा पहले से तय विशिष्ट ब्यौरे के अनुसार खाने योग्य मूंगफली का आटा तैयार करना चाहिये और ७० प्रतिशत उत्पादन परस्पर तय हुए मूल्य पर सरकार को देना चाहिये। उद्योग को सरकार तथा यूनीकेफ से प्रविधिक सहायता मिलेगी और उसे यूनीकेफ द्वारा दी गई मशीनरी को परस्पर तय हुई शर्तों पर निश्चित समय के पश्चात् हस्तान्तरित करने का हक होगा।

किराये की इमारतों में डाकघर

२२०९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के तहसील हैडक्वार्टरों में कितने ऐसे डाकघर हैं जिन के कार्यालय अभी तक किराये पर लिये हुए मकानों में हैं ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का कितना किराया मय बिजली पानी और मकान के देना पड़ता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार अपने निजी कार्यालय के भवन कब तक बनायेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्तमान योजना क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) २८ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) तथा (घ). हाल ही में श्रीगंगानगर में एक विभागीय इमारत बनाई गई है और चुरू, पालमपुर, श्रीकर्णपुर, रायसिंहनगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ, नौहार, बहादरा, सादुलपुर, तारानगर तथा नोखा में इमारतें बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । विभागीय इमारतें तभी बनाई जाती हैं जबकि उपयुक्त किराये की इमारतें उपलब्ध न हों या उन्हें बनाने में अधिक बचत होती हो ।

घग्गर में बाढ़

२२१०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के ओटो बांध से घग्गर नदी में जो पानी छोडा जाता है उस की बाढ़ से राजस्थान के जिला गंगानगर के किसानों की हजारों रुपयों की फसल नष्ट हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी संकलित की जा रही है और यह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में विस्थापित लोगों को ऋण

†**२२११. श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के पुनर्वास निदेशालय ने, नवम्बर और दिसम्बर १९६१ में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा लिये गये सीढी खेती ऋण के लिये कितने बंध पत्र जारी किये हैं ;

(ख) कितने विस्थापित व्यक्तियों को वास्तव में ऋण दिये गये हैं ; और

(ग) बंध पत्र जारी किये जाने के पश्चात् भी कितने विस्थापित व्यक्तियों को अभी ऋण मिलना है ; और

(घ) ऋण देने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). कुछ नहीं ।

(घ) सीढी खेती का काम त्रिपुरा प्रशासन द्वारा विभागीय तौर पर किया जाता है । जहां तक सम्भव होता है, उन विस्थापित लोगों को जिन की भूमि पर सीढ़ी खेती की जाती है, काम पर लगाया जाता है और उनको प्रति एकड़ २५० रुपये की दर पर की गई प्रगति के अनुसार किश्तों पप राशि दी जाती है । काम पूरा हो जाने पर, किया गया व्यय उन की भूमि के क्षेत्र के अनुपात में संबद्ध स्थापित व्यक्तियों को दिया गया ऋण माना जाता हैं । उस स्तर पर उन को ऋण बंध भरने पड़ते है अतः राशि देने में विलम्ब का सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली जल संभरण

†२२१२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगम ने दिल्ली के लिये लगातार जल संभरण को एक व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो क्या इस ने उस के लिये अतिरिक्त धन की मंजूरी के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार दिल्ली नगरपालिका निगम को उन की आवश्यकताओं के अनुसार जल संभरण योजनाओं के लिये ऋण देती है । ऋण के रूप में विधि निधियां जो तीसरी योजना अवधि में दिल्ली निगम को दी गई हैं, अभी पूरी तरह खर्च नहीं की गई हैं । अतः, अतिरिक्त धन मंजूर करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

रेलवे क्वार्टरों का किराया

†२२१३. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रेलवे क्वार्टरों के किराये में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस वृद्धि का कारण यह है कि वर्तमान मकानों की मरम्मत और सुधार किया गया है ; और

(घ) किराये को पुराने स्तर तक घटाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (घ). आंकित किराया निकालने का पहला आधार यह था कि यह इस प्रकार निश्चित किया जाता था कि प्रत्येक श्रेणी में सभी क्वार्टरों को इकट्ठे लेकर वसूल किये गये किराये से, प्रत्येक ऐसी श्रेणी की मूल लागत पर, जहां तक संभव हो सके, लाभ प्राप्त हो, किन्तु वह ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिये । इस लाभ को प्राप्त करने के लिये किरायों का अनुमान लगाने में, इस बात का ध्यान रखा गया कि जो किराया लिया जाय वह वेतन का १० प्रतिशत तक होना चाहिये, और इस बात का ध्यान भी रखा गया कि क्वार्टर कितनी अवधि तक खाली रहने की संभावना है ।

आंकित किराया निकालने के उपरोक्त आधार में, समारोह समिति और लोक लेखा सिमित के विचारों तथा दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संशोधन किया गया है । अब सब क्वार्टरों का औसत आंकित किराया प्रत्येक श्रेणी में क्वार्टरों की पूंजी लागत के ६ प्रतिशत के आधार पर श्रेणीवार निकाला जाता है । परिवर्तन दो प्रक्रमों में अर्थात् निम्न तरीके से किया गया है :

(१) प्रत्येक क्वार्टर का किराया १–१०–६० से तदर्थ आधार पर उन क्वार्टरों के बारे में २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जिनके किराये पूंजी लागत के ५ प्रतिशत से कम आधार पर आंके गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) ३० सितम्बर १९६० को पूंजी लागत के ६ प्रतिशत पर सब क्वार्टरों का किराया पुनरांकित किया गया और वह १-१०-६१ से किराया लिया गया ।

तथापि किराया की वसूली वेतन आदि के १०% तक सीमित है और प्राधिकृत वेतन क्रम के १५० रुपये मासिक स कम पाने वाले कर्मचारियों के मामले में यह घटा कर वेतन का ७½ प्रतिशत कर दिया गया है ।

सिंचाई परियोजनाएं

†२२१४. **श्री क० ल० राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पर एक लाख से दस लाख रुपये तक के व्यय वाली सिंचाई परियोजनाओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक सूची तथा उसके लाभ और अनुमानित लागत का ब्योरा सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(ग) पहली तथा दूसरी योजनाओं में इन परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है और तीसरी योजनाओं के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि कटाव

†२२१५. **श्री रविन्द्र बर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि १२ और १३ अप्रैल, को समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण क्विलोन और अल्लप्पी के बीच के राजमार्ग टूट गया है और केरल में राष्ट्रीय राजपथ को बहुत हानि पहुंची है और हजारों मछुवे बेघर हो गये हैं, जो इस प्रदेश में समुद्र तट पर रहते थे ;

(ख) क्या वह सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे जिस में यह बताया गया हो कि राजमार्ग को कितनी और किस प्रकार की हानि हुई है तथा कितने लोग बेघर हो गये हैं ;

(ग) इस आपदा के शिकार जो लोग हुये हैं उन को सहायता पहुंचाने के लिये क्या उपाय किये गये है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रदेश में समुद्र द्वारा होने वाले अग्रतर भूमि कटाव और प्रदेश को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

थोट्टापल्ली और पुराक्काड क्षेत्र (अल्लप्पी जिला) में समुद्र तट १२-४-६२ और १३-४-६२ को भूमि कटाव द्वारा बहुत प्रभावित हो गया था । लहरों की गति असाधारण रूप से बहुत तेज और अप्रत्याशित थी । थोट्टापल्ली स्पिलवे मुहाने के उत्तर में लगभग ३ मील की लम्बाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग के ४१/४ तक समुद्र द्वारा कटाव से प्रभावित हुआ था । समुद्र, ग्रोइनज द्वारा रक्षित भाग को छोड़कर लगभग ५० फुट से १०० फुट तक भूमि में घुस आया । ३८/८ से ४१/२ मील तक भी समुद्र का जल चढ़ आया और गहरे से गहरे क्षेत्र में पानी लगभग १ १/२ फुट चल रहा

†मूल अंग्रेजी में

था, अर्थात् ३८/८ से ३९/२ मील पर। पुराक्काड में पहले से बनाये गये सात ग्रोइनज और चालू निर्माणाधीन ग्रोइनज भूमितया जलमग्न हो गई। भूराक्काड के ७ पुराने ग्रोइनज में से १ पूर्णतया जल में बह गया और अन्य बुरी तरह प्रभावित हुये। तुरन्त ग्रोइनज को ठीक करने का काम किया गया। थोट्टापल्ली और थूराक्काड में भूमि कटाव होने के पश्चात, ३७ मकान जलमग्न हो गये और दो देशी किश्तियां नष्ट हो गईं। ४४ नारियल वृक्ष भी जड़ से उखड़ गये। इस कारण कुल ५,१६० रुपये की अनुमानित हानि बताई जाती है।

२. राज्य सरकार ने सहायता के लिये आवश्यक व्यवस्था की है। चावल और तेपियो का समुद्र द्वारा भूमि कटाव से प्रभावित मछुओं को वितरित किये गये थे। राज्य सरकार व समुद्रतटीय क्षेत्रों में मछुओं को अपने मकानों को ठीक करने और मरम्मत करने के लिये धन बांटने के लिए भी शीघ्र कार्रवाई की है।

रेलों में भोजन-यानों और स्टेशनों के उपाहारगृहों में भोजन के मूल्य

†२२१६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भोजनयानों और स्टेशनों के उपाहारगृहों में एक ही प्रकार के भोजन के लिये प्रत्येक मंडल में भिन्न भिन्न दाम लिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के भेद को दूर करने का इरादा रखती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). भारतीय किस्म के भोजन की दरें (सामिश और निरामिश) कर निश्चित दी गई हैं और दक्षिण के अतिरिक्त सभी रेलों पर एक ही दाम लिये जाते हैं। दक्षिण रेलवे के लिये, चूंकि भोजन सामग्री भिन्न होती है, भिन्न और कम दर रखी गई है। ये दाम अल्पाहार गृहों / स्टेशनों के रेस्टोरां में लिये जाते हैं। इस समय निश्चित दरें ये हैं।

	दक्षिण रेलवे	अन्य रेलवे
निरामिश	०.७५ नये पैसे	०.८७ नये पैसे
सामिश	१.०० ,,	१.१२ ,,

जब भोजन स्टेशनों के उपहारगृहों/अल्पाहारगृहों से गाड़ी के डिब्बों में परोसा जाता है, निश्चित दर में १५ नये पैसे अधिक लिये जाते हैं। भोजन-यानों में या उन से गाड़ियों में भोजने परोसने के लिये निश्चित दर से २५ नये पैसे अधिक लिये जाते हैं !।

दिल्ली में वनस्पति का निषेध

†२२१७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका में इसके क्षेत्राधिकार में वनस्पति के विक्रय पर निषेध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार लोगों की फैली हुई मांग की दृष्टि से इस सुझाव को मानने का विचार करती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अमरपुर त्रिपुरा के विस्थापित लोग

†२२१८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अमरपुर सब डिवीजन के विस्थापित लोगों के तीसरे आम चुनावों के पश्चात् खेती में सीढियां बनाने के लिये कोई धन बांटा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बांटी गई थी तथा कुल कितने परिवारों को धन मिला था ;

(ग) बांटी गई राशि में से कितनी राशि उक्त सब डिवीजन के आदिम जाति शरणार्थियों को दी गई थी ;

(घ) क्या सीढियां बनाने के लिये कोई ऋण राय भद्र, बेगुन छेरा और कोचन चेरा आदि बस्तियों के आदिम जातीय शरणार्थियों को दिया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में चेचक

†२२१९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली में चेचक का रोग सर्वाधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने का विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां । भारत में विश्व में सब से अधिक चेचक फैलती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, एक राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम तीसरी योजना अवधि में क्रियान्वित किये जाने के लिये आरम्भ किया गया है ।

रायचूर के लिये अधिक माल डिब्बों का संभरण

†२२२०. **श्री चन्द्रिकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर के निवासियों ने माल डिब्बों का संभरण बैठाने के लिये उनसे कोई अभ्यावेदन किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को पता है कि रायचूर में व्यापार के सौदों में १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है और व्यापारी समाज की आवश्यकतायें दुगनी हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में माल डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) व्यापारी संस्था रायचूर के प्रतिनिधियों ने रेलवे मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था, जब वह उस स्थान पर गये थे और उन से मांग की गई थी कि यातो यातायात की निःशुल्क बुकिंग की जाये या स्टेशन पर निश्चित इंडेंटों पंजीयन की उपरि सीमा बढ़ाई जाये ।

(ख) जो नहीं ।

(ग) रायचूर में माल लादने के बारे में उन्नति करने के लिये कार्यवाई की जा चुकी है । जनवरी से मई (१० तक) १९६२ की अवधि में १३४३ माल डिब्बे (जिसमें १०५ बनस्पति तेल टैंक बैगन शामिल हैं) रायचूर में लादे गये थे जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में १०९६ डिब्बे (जिनमें १०२ वनस्पति टैंक वैगन शामिल थे) लादे गये थे । अतः इस स्टेशन पर माल की लदाई संतोषजनक होती है । बकाया पंजीयन एक महीने से पुराने नहीं, जो उस सैक्शन के अन्य स्थानों के बराबर है ।

कृषि उत्पादों की प्रति एकड़ उपज

†२२२१. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी अभिकरण में पिछले पांच वर्षों में मुख्य कृषि उत्पादकों की प्रति एकड़ उपज की वृद्धि या गिरावट को जानने का कोई प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण ने ; और

(ग) सर्वेक्षण का परिणाम क्या निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राज्य सरकारों से देश की प्रमुख फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और प्रति एकड़ उपज सम्बन्धी सांख्यिकी लगातार एकत्र करता रहता है । ये संख्यिकी वार्षिक प्रकाशन "भारत में प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान" में प्रकाशित की जाती है, जिस में १० वर्षों के अखिल भारतीय आंकड़े और ५ वर्षों के राज्य वार आंकड़े होते हैं । एक तदर्थप्रकाशन ("पूर्वानुमान फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और प्रतिएकड़ उपज" भी हाल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें १९४९–५० से १९५९–६० तक के वर्षों के लिये आंकड़े दिये हैं । ये अनुमान भी उस निदेशालय के मासिक पत्रिका 'भारत की कृषि संबंधी स्थिति' में लगातार प्रकाशित किये जाते हैं । ये सब प्रकाशन संसद पुस्तकालय को लगातार भेजे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५५–५६ से १९६०–६१ तक वर्षों के लिये भारत की प्रमुख फसलों की औसत प्रति एकड़ उपज दी गई र। **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में आकस्मिक मजदूर

†२२२२. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में नियमित पदों पर काम करने वाले आकस्मिक मजदूरों को छः महीने की नौकरी के बाद भी केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन क्रम नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५८, १ अप्रैल, १९५९, १ अप्रैल, १९६० और १ अप्रैल, १९६१ को रेलवे में कितने आकस्मिक मजदूर काम कर रहे थे और वे रेलवे में कितने साल से काम कर रहे हैं; और

(ग) इन आकस्मिक मजदूरों के वेतन को दरें किस प्रकार निर्धारित की जातो हैं और किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

पोर्ट ब्लेअर में सरकारी बिजली घर के लिये ईंधन

†२२२३. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर का वन विभाग पोर्ट ब्लेयर के सरकारी बिजली घर को उसकी पूरी जरूरत भर चीरी हुई ईंधन सप्लाई नहीं कर सकता और वह अधिकतर सस्ते दाम पर सरकारी अफसरों को दे दिया जाता है जब कि बिजली घर को बहुत ऊंचे दाम पर गैर-सरकारी जरियों से दूसरी लकड़ी खरीदनी पड़ती है; और

(ख) सरकार के मुकाबले में दूसरों को चीरे हुए ईंधन की सप्लाई के कारण सरकार क्यों नुक्सान बर्दाश्त करे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) और (ख). यह ठीक है कि अन्दमान वन विभाग अपनी जरूरी आवश्यकतायें और मिल मजदूरों की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद पोर्ट ब्लेअर में सरकारी बिजली घर को उसकी पूरी जरूरत भर चीरी हुई ईंधन सप्लाई करने में असमर्थ है। १९६१–६२ के लिए उत्पादन और निबटान के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

उत्पादन की मात्रा		टनों में माहवार औसत
चीरा हुआ ईंधन	बुरादा	कुल
१,०९३.३८	४७८.२५	१,५७१.६३

†मूल अंग्रेजी में

निबटान

	सप्लाई किये गये ईंधन की मात्रा	सप्लाई किये गये बुरादे की मात्रा	कुल	प्रतिशत
	(टनों में)			
१. ए० सी० बिजली घर	३८६.५०	२७८.२०	६६४.७०	४२
२. वन विभाग .	५५०.७५	२००.००	७५०.७५	४८
३. दूसरे सरकारी विभाग . .	०.१३		०.१३	
४. अन्नपूर्णा कैफेटेरिया सहित मिल मजदूर	१२५.७५	०.०५	१२५.८०	८
५. जनता . .	११.७५		११.७५	०.७
६. सरकारी पदाधिकारी	१८.५०	..	१८.५०	१.३
	१,०९३.३८	४७८.२५	१,५७१.६३	१००

विभाग द्वारा तैयार किये गये चीरे हुए ईंधन पर पहला हक वन विभाग का, अपने बायलर्स और वाटर-क्राफ्ट्स के लिए आवश्यक सप्लाई के लिए होता है। दूसरा हक मिल मजदूरों का होता है जिन्हें विभाग की स्थापना के समय से रियायती दर पर माहवार एक बंडल मिलता रहा है और उसके बाद वह अन्नपूर्ण कैफेटेरिया को दिया जाता है जो कारखाना अधिनियम के अधीन उन्हीं के लाभ के लिए चलाया जाता है। बाकी सारा का सारा प्रायः पोर्ट ब्लेअर के बिजली घर को बेच दिया जाता है लेकिन वह थोड़ी सी मात्रा छोड़कर जो जनता और सरकारी पदाधिकारियों के हाथ सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बेच दी जाती है। बिजली घर की आवश्यकता १२८० टन प्रति मास है और इसलिए यह सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करना वन विभाग के लिए सम्भव नहीं है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पदोन्नति

†२२२४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने सुपरिन्टेन्डेन्ट, गोडाउन सुपरिन्टेन्डेन्ट और टेक्निकल अफसरों को सहायक संचालकों (असिस्टैन्ट डायरेक्टर्स) के पद पर पदोन्नत किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने सहायक संचालकों और उप-संचालकों (डिप्टी डायरेक्टर्स) को क्रमशः उपसंचालकों और संयुक्त संचालकों के पद पर पदोन्नत किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कई सहायक संचालक जिन्हें करीब दो साल पहले संघ लोक सेवा आयोग ने मंजूर नहीं किया था, अब भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी जगह दूसरे आदमियों को रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). ३० अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में इन श्रेणियों में पदोन्नति के आंकड़े बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो १८ सहायक संचालक स्वीकृत नहीं किये गये थे व अब भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नियमित उम्मीदवार और विभागीय पदोन्नति समिति को सिफारिशें अभी तक नहीं मिली हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभाग मे राजपत्र घोषित पदों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गयी है और संघ लोक सेवा आयोग ने अब तक जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है उन में से अधिकांश को नवनिर्मित पदों पर काम करना पड़ा। इसलिए अब तक केवल ५ अस्वीकृत सहायक संचालकों को प्रत्यावर्तित करना सम्भव हो सका।

(ङ) सहायक संचालकों की पदालि भरती कुछ तो सीधी भरती द्वारा, कुछ निचली श्रेणियों से पदोन्नति द्वारा और कुछ डेप्यूटेशन द्वारा की जाती है। सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध मे जिन पर अभी अस्वीकृत पदाधिकारी काम कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग को फिर मांग भेजी गयी है। सहायक संचालक की श्रेणी में विभागीय पदोन्नति से सम्बन्धित कुछ प्रश्न अभी हाल संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निबटाये गये हैं और उस पदोन्नति कोटे के अधीन पदों पर काम करने वाले अस्वीकृत पदाधिकारियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नति समिति की अगली बैठक में उस समिति द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार रखे जायेंगे। डेप्यूटेशन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए डेप्यूटेशन पर पदाधिकारी प्राप्त करने के लिए कार्यवाही भी की गयी है।

बड़ौदा डिविजन में भोजन व्यवस्था

†२२२५. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री बड़े :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में भोजन वितरण के ठेकेदारों के कर्मचारियों और खोमचे लगाने वालों की सहकारी समिति ने बड़ौदा डिविजन में रेलवे स्टेशनों पर भोजन वितरण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या इस समिति की यह मांग अस्वीकार कर दी गयी है और गैर-सरकारी भोजन वितरकों को जो धनी लोगों बेनामीदार हैं, प्राथमिकता दी गयी है; और

(ग) क्या ये लाइसेंस मंजूर करने के मामले में सरकार अपनी ठीक ठीक नीति घोषित करेगी?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). पहले के आदेशों के अनुसार रेलवे को एक या दो स्टेशनों पर, प्रयोग के तौर पर सहकारी समितियों को जिन में पूरी तौर से खोमचे लगाने वाले या भोजन बनाने वाले आदि लोग होते हैं, भोजन वितरण करने/खोमचे लगाने के ठेके देना जरूरी होता है। पश्चिम रेलवे में फुलेरा और मारवाड़ स्टेशनों पर दो ऐसी समितियां ठेके चला रही हैं।

बड़ौदा स्टेशन पर एक अतिरिक्त ट्राली चलाने के लिए पश्चिम रेलवे की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिन में एक आवेदन पत्र रेलवे वेन्डर्स एण्ड वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, जिसके ३० सदस्य बनाये जाते हैं, था। रेलवे ने यह लाइसेंस उसी स्टेशन पर एक दूसरे मौजूदा ठेकेदार को दे दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहलगाम में अवकाश गृह

†२२२६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पहलगाम, काश्मीर में अवकाश गृह (हॉलिडे होम) के लिए जमीन खरीदी है ;

(ख) यदि हां, तो किस कीमत पर ; और

(ग) यह जमीन किस आदमी से खरीदी गयी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह (हॉलिडे होम) के लिए पहलगाम, काश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीदी गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर सरकार ने १ रुपये की मामूली सालाना अदायगी पर ९९ साल के पट्टे पर एक जमीन जो क्षेत्रफल में ५ एकड़ से कुछ अधिक थी, मुफ्त दे दी थी इस जमीन पर बनायी जाने वाली इमारत की वास्तविक लागत रेलवे को खर्च करनी थी। यह सभी बातें रेलवे मन्त्री ने १८ फरवरी, १९५९ को संसद् में १९५९–६० का रेलवे बजट पेश करते समय अपने भाषण में बता दी थीं।

आगे, गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिये अवकाश गृह के निर्माण कहीं अधिक कम क्षेत्रफल वाली और उस पर इमारत के साथ एक दूसरी जमीन गैर सरकारी मालिक से खरीदीनी पड़ी। इस जमीन का क्षेत्रफल लगभग २५ कनाल है (८ कनाल बराबर है १ एकड़ के) जिसमें से १६ कनाल जमीन गैर सरकारी मिलकियत की थी और ९ कनाल जमीन राज्य सरकार से पट्टे पर प्राप्त हुई थी जो इस बीच रेलवे प्रशासन को दे दी गयी है। १६ कनाल जमीन की कीमत १,५०० रु० फी कनाल के हिसाब से गैर-सरकारी मालिक को दे दी गयी है और बाकी ९ कनाल जमीन पट्टे की कीमत सालाना लगभग २ रुपये फी कनाल के हिसाब से राज्य सरकार को दी जानी है।

गैर-सरकारी सम्पत्ति का मालिक जिससे यह सम्पत्ति खरीदी गयी है, बख्शी अब्दुल मजीद है।

बिजली का उत्पादन

†२२२७. **श्री कोल्ला वेंकैय्या** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पहली और तीसरी योजना के आरम्भ में तापीयबिजलीघरों और पन बिजली परियोजनाओंरेंसे अलग अलग कितनी बिजली पैदा की गयी ;

(ख) प्रत्येक राज्य में तीसरी योजना के अन्त तक तापीय बिजली घरों और पन बिजली परियोजनाओं से अलग अलग कितनी बिजली तैयार की जायगी ;

(ग) तीसरी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में आरम्भ की जाने वाली प्रत्येक बिजली परियोजना की क्या लागत है ; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की आर्थिक आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी की जायेंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ), एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी–१६३/६२।]

---

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंसशुदा औषधि निर्माता

†२२२८ **श्री कोल्ला वेंकैय्या** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि नियन्त्रण अधिनियम के अधीन फिलहाल भारतीय औषधि उद्योग में कितने लाइसेंस शुदा निर्माता हैं ;

(ख) ऐसे कितने लाइसेंस शुदा निर्माता हैं जिनके पास औषधियां तैयार करने के लिए कोई कारखाना या उपकरण नहीं है ;

(ग) विदेशों के कितने लाइसेंस शुदा निर्माता हैं और हमारे देश में उन्होंने इस उद्योग में कितनी पूंजी लगायी है ;

(घ) हमारे देश के निर्माताओं ने कितनी पूंजी लगायी है ;

(ङ) १९६१–६२ में भारत में कितनी प्रकार की औषधियां तैयार की गयीं ; और

(च) औषधि नियन्त्रण अधिनियम के अधीन १९६१–६२ में औषधियों के कितने नमूने लिये गये और उनका परीक्षण किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) २३६४ ।

(ख) ३८५ ।

(ग) और (घ). ३२ औद्योगिक एकक हैं जिनमें अभी तक विदेशी पूंजी लगायी गयी है। विदेशी फर्मों ने अब तक जितनी पूंजी वास्तव में लगायी है उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन अनुमान है कि लगभग ८० करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से करीब २१ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी अभी तक इस देश में लगायी जा चुकी हैं।

(ङ) भारत में जिस प्रकार की औषधियां तैयार की गयी हैं वे 'जीव विज्ञान सम्बन्धी तथा विशेष उत्पाद' हैं जैसे सेरा इंजैक्शन के लिये सेरम प्रोटीन्स का सोल्यूशन, पेरेन्टरल इंजैक्शनों के लिए टीके, टोक्सिन्स, ऐन्टीजेन्स, ऐन्टी टोक्सिन्स, नियो-आर्सफेनामिन और छूत के रोगों के खास इलाज के लिए काम में लाये जाने वाले इसी प्रकार के पदार्थ, इन्सुलिन, पिशुटरी (पोस्टेरियर लोब) एक्सट्रैक्ट, आद्रेनैलाइन और आद्रेनैलाइन के क्षारों का सोल्यूशन और निम्नलिखित औषधियां तथा उनसे तैयार की गयी दवाइयां—(१) पेनिसिलीन (२) स्ट्रप्टोमाइसिन (३) क्लोरटट्रासाइक्सीन (४) ऑक्सी-टेट्रासाइक्सीन (५) क्लोरामफेनीकोल (६) वायोमाइसीन (७) निओमाइसीन (८) बैसी-ट्रासीन (९) टेट्रासाइक्सीन (१०) कार्बोमाइसीन (११)एरिथ्रोमाइसीन (१२) वैन्कोमाइसीन (१३) प्लेमैनि बी, अन्य कोई दवाइयां जो या तो उसी रूप में देनी होती हैं जिस रूप में बेची जाती है या किसी उपयुक्त सॉल्वेन्ट के साथ मिलाने के बाद देनी होती हैं और जिन्हें या तो रैफ्री जरेटर में रखने की जरूरत होती है या रेफ्रीजरेटर में रखने की जरूरत नहीं होती, स्टेरिलाइज्ड सर्जि-कल लिगेचर और स्टेरिलाइज्ड सर्जिकल सुचर, बैक्टेरियोफैजेस और दूसरी विशिष्ट दवाइयां अर्थात्

१. ऐसी औषधियां जो डिजिटैलिस ग्रुप की होती हैं और उस प्रकार की औषधियों से बनने वाली दवाइयां ।

२. एरगॉट और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

३. आद्रेनैलाइन और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

४. फिश लीवर ऑयल और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. विटामिन्स और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

६. लीवर एक्स्ट्रैक्ट और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

७. हार्मोन्स और उससे तैयार की जाने वाली औषधियां ।

८. वैक्सीन ।

९. निम्नलिखित औषधियां और उनसे तैयार की जाने वाली औषधियां :

१. पेनिसिलीन

२. स्टेप्टोमाइसीन

३. क्लोरटेट्रासाइक्लीन

४. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन

५. क्लोरामफेनीकोल

६. नीओमाइसीन

७. कारबोमाइसीन

८. एरिथ्रोमाइसीन

९. बेसीट्रासीन

१०. टेट्रासाइक्लीन

११. ग्रामीसीडीन

१२. टाइरोथ्रीसीन

१३. वायोमीसीन

१४. फ्रैमीसीटीन

१५. ग्रीसीओफलसीन

१६. नोवोबायोसीन

१७. निस्टाटीन

१८. ओलियोन्डोमाइसीन

१९. पोलीमिक्सीन बी

२०. स्पीरामाइसीन

२१. कैन्कोमाइसीन

सल्फाड्रग्ज, पैरामीनो सैलीसाइक्मीक एसिड, सल्फोन ड्रग्ज और पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन ।

(च) ६,७९९ (राजस्थान और बिहार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन की सरकारों द्वारा लिये गये नमूनों की संख्या को छोड़ कर) इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में कुष्ठ

†२२२९. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ की वृद्धि रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की कोई योजना सरकार ने मंजूर की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना त्रिपुरा में लागू की जाने वाली है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह सम्भवत: कब तक लागू की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) से (ङ). भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे कुष्ट से पीड़ित हों या न हों, स्वेच्छा से बन्ध्यीकरण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । ये सुविधायें त्रिपुरा में भी उपलब्ध हैं ।

त्रिपुरा में पीने के पानी की कमी

†२२३०. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में कुरती क्षेत्र (धर्मनगर सब-डिवीजन) में पीने के पानी की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) त्रिपुरा में कुरती क्षेत्र (धर्मनगर सब-डिवीजन) में पीने के पानी की कोई अधिक कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैस टर्बाइन जेनरेटिंग यूनिटों आदि के लिये आयात लाइसेंस

†२२३१. **श्री राज गोपाल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस टर्बाइन जैनरेटिंग यूनिटों और जल विद्युत् और ताप यूनिटों के आयात लाइसेंस के लिये कितने आवदन-पत्र सरकार के पास विचारार्थ लम्बित पड़े हैं ;

(ख) प्रत्येक यूनिट की कितनी क्षमता है ;

(ग) यदि कोई विदेशी सहायता है तो उसकी श्रेणी और स्वरूप क्या हैं और उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश से कोई आवेदन-पत्र विचारार्थ लम्बित हैं , और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश को, वहां पर बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए, शीघ्रता से लाइसेंस देना आवश्यक समझती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) छ :

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(घ) जी, नहीं । तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोठागुदम और रामागुन्डम में अपने तापीय विद्युत् केन्द्रों के लिये शीघ्र विदेशी मुद्रा देने को कहा है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

से १५००० किलोवाट का गैस टर्बाइन यूनिट के आयात के लिय भी कहा है। विदेशी मुद्रा के देने के बारे में अभी तक औपचारिक आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) उपरोक्त मामलों के बारे में स्थिति निम्न है :

(१) कोठागुदम तापीय विद्युत् केन्द्र (२ × ६० मिलोवाट)

इस योजना को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक / अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता के लिये रख दिया है। संयंत्र और उपकरणों के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित करने और विशिष्ट विदेशी मुद्रा देने और आयात लाइसेंस देने के बारे में सिफारिशें भेजने को कहा गया है। इस परियोजना के लिये परामर्शदाता इंजीनियर नियुक्त कर लिये गये हैं। संयंत्र और उपकरणों के आयात पर ७.६ करोड़ रुपये के व्यय की संभावना है। विद्युत् केन्द्र के वर्ष १९६५ में चालू हो जाने की आशा है।

(२) रामागुन्डम तापीय विद्युत् केन्द्र का विस्तार

रामागुन्डम तापीय विद्युत् केन्द्र में, जिस की अधिष्ठापित क्षमता ३७.५ मिलोवाट (३ × १२.५ मिलोवाट) है, विस्तार के तौर पर एक ५०/६२.५ मिलोवाट तापीय संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (अमरीका) से सहायता के लिये रखी गयी है। परामर्श-दाता इंजीनियरों की नियुक्ति के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है। टर्बो-जेनरेटर संयंत्र और सहायक मशीनों के लिये भी टेंडर प्राप्त हो गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से धन मिलने पर क्रयादेश दिये जायेंगे। इस योजना में ४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी। इस केन्द्र के वर्ष १९६४--६५ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

(३) प्रत्येक १५ मिलोवाट के २ गैस टर्बाइन यूनिट स्थापित करने के लिये अर्जन

यह योजना मूलतः तृतीय योजना में शामिल नहीं की गयी थी। आन्ध्र में बिजली की अधिक कमी के कारण भारत सरकार इस प्रार्थना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस समय १० से १२ मिलोवाट क्षमता के ४ गैस टर्बाइन पैकेज प्रकार के संयंत्र (ढके हुए) के आयात के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और यदि मूल्य और संभरण उपयुक्त रहा और अपेक्षित विदेशी मुद्रा मिल गई तो आन्ध्र प्रदेश को दो सेट देना संभव हो सकेगा। ये यूनिट ९ से १२ महीनों में चालू हो सकते हैं। प्रत्येक यूनिट के लिये ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिये।

ए० आर० टी० कम्पनी के कोयला खान श्रमिकों को चावल का संभरण

†२२३२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्ग बेरिता, आसाम में ए. आर. टी. कम्पनी के कोयला खान श्रमिकों, को राशन में चावल की मात्रा बढ़ाई जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है;

(ग) चावल की सुधरी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आसाम सरकार यह वृद्धि करने से सहमत हो गयी है; और

(घ) क्या सरकार ७५ प्रतिशत चावल और २५ प्रतिशत आटे के पुराने अनुपात को पुनः लागू करने को राजी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (घ). आसाम में चावल के संभरण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुल राशन के चावल के अनुपात को ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ७५ प्रतिशत न करने का फैसला किया है ।

बिजली की दरें

†२२३. { **डा० रानेन सेन** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ के पुराने उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंसधारी के लिये सरकार द्वारा मंजूरशुदा दरों में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था;

(ख) क्या सम्बन्धित उपबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के विरोध पर वर्ष १९५६ में [बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ की छठी अनुसूची के अनुच्छेद **१ के द्वारा**] संशोधन किया गया;

(ग) क्या संशोधित उपबन्ध के अन्तर्गत लाइसेन्सधारी के लिये दरों में वृद्धि करने या कमी करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है; और

(घ) वर्ष १९५६ में बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ की छठी अनुसूची के अनुच्छेद १ में संशोधन करने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). पश्चिमी बंगाल समेत कुछ राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया था कि लाइसेंसधारी को बिजली की दरें बढ़ाने से पूर्व दो महीने का नोटिस दे कर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये । वर्ष १९५६ में बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ की छठी अनुसूची की प्रथम कंडिका में संशोधन किया गया कि लाइसेंसधारी बिजली के संभरण की दर बढ़ाने से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड को दो महीने का नोटिस दे । पूर्व अनुमति के बारे में कुछ आवश्यक नहीं समझा गया । अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि दरों में वृद्धि करने में लाइसेन्सधारी ने छठी अनुसूची के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह शुल्क का परीक्षण करने के लिये दर-निर्धारण समिति नियुक्त कर सकती है । यदि दर-निर्धारण समिति लाइसेन्सधारी द्वारा लागू दर से कम दर की सिफारिश करती है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को उन से लिया गया अधिक शुल्क, वापस करेंगे ।

फल उगाने वालों को ऋण

†२२३४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों के विकास के लिये उत्पादकों को ऋण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना को कब अन्तिम रूप दिये जाने और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार द्वारा फल उत्पादन के विकास के लिये उत्पादकों को ऋण देने की योजना राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दिल्ली में मंजूर की गई। यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों में लागू ह ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिस में योजना का ब्यौरा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]** ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में डाक घर

†२२३५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० और १९६१ में मध्य प्रदेश में नये डाक घर खोलने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, नहीं, वास्तव में वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में लक्ष्य से अधिक काम हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २६१ ।

दक्षिण–पूर्व रेलवे पर नये हाल्ट और स्टेशन

†२२३६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में दक्षिण पूर्व रेलवे पर कितने नये हाल्ट और स्टेशन बनाये गये हैं; और

(ख) अगले पांच वर्षों में उसी रेलवे पर कितने और नये हाल्ट और स्टेशन बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ४० ।

(ख) १२७ ।

कहराकूल में रेलवे स्टेशन

†२२३७. **श्री जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन पर हल्दीपदा और बलसार रेलवे स्टेशनों के बीच कहराकूल में एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की प्राथमिक जांच पड़ताल कर ली गई है ;

(ग) यह मामला अब किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). हल्दीपदा और बलसार के बीच कहराफूल में रेलवे स्टेशन बनाने के प्रस्ताव की जांच की गयी परन्तु पर्याप्त औचित्य न होने से इस को मंजूर नहीं किया गया ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्री शेड

†२२३८. **श्री जेना** :
श्री मलिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों, जहां वर्षा अधिक होती है, पर बने यात्री शैड छोटे होने के कारण यात्रियों का उचित रूप से बचाव नहीं हो पाता;

(ख) क्या सरकार उन को चौड़ा करके उन का नव-निर्माण करेगी;

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर जिलावार उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां इस समय यात्री शैड और तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षा-कक्ष नहीं हैं; और

(घ) यात्रियों के लिये इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था किस तिथि तक कर दी जावेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । दक्षिण-पूर्व रेलवे पर लगभग १३७ स्टेशनों पर उस समय इस्पात की कमी के कारण और यथा संभव शीघ्र कुछ शैल्टर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैर-स्टैण्डर्ड किस्म के प्लेटफार्म शैल्टर बनाये गये जो स्टैण्डर्ड किस्म के शैल्टरों से छोटे हैं ।

(ख) निधि उपलब्ध होने पर कार्यक्रमानुसार आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं ।

(ग) सभी स्टेशनों पर वहां पर यात्री यातायात की आवश्यकता के साइज के तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षाकक्ष बनाये गये हैं । एक सूची संलग्न है जिस में बिना यात्री शैडों (प्लेटफार्मों शैल्टर) के स्टेशनों के नाम दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६०]**

(घ) प्लेटफार्म शेल्टरों को बुनियादी सुविधाओं में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिये प्रतीक्षा-कक्ष हैं । निधि उपलब्ध होने पर सभी प्रमुख स्टेशनों पर कार्यक्रमानुसार ऐसे शेल्टर बनाये जायेंगे । इस कार्य के लिये कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंक निधि और सामान के संसाधन बहुत सीमित हैं ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भद्रक में प्राथमिक स्कूल

†२२३९. **श्री जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये दक्षिण-पूर्व रेलवे में भद्रक में रेलवे बस्ती में प्राथमिक स्कूल हैं ; और

(ख) वहां पर प्रत्येक स्कल में कौन सी भाषायें सिखाई जाती हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । भद्रक में रेलवे बस्ती में दो रेलवे —एक अध्यापकीय प्राथमिक स्कूल है और एक गैर-सरकारी तौर पर प्रशासित प्राथमिक स्कूल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दो एक अध्यापकीय प्राथमिक स्कूलों में बंगाली और तेलुगु के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और गैर-सरकारी रूप से प्रशासित प्राथमिक स्कूल में उड़िया के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ।

दूर-संचार सेवा का बंद रहना

†२२४०. **श्री जेना** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेतार सेवा कटक और मद्रास के बीच १५ अप्रैल, १९६२ को और कलकत्ता और बम्बई के बीच १८ अप्रैल, १९६२ को बंद रही ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं । कुछ समय के लिये थोड़ी-सी गड़बड़ रही और कार्य सामान्यतः ठीक चलता रहा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश से कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†२२४१. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में काम कर रहे अन्य राज्यों से आये कर्मचारियों को निकट भविष्य में उन के अपने राज्यों में स्थानांतरित किया जायेगा ;

(ख) क्या इस स्थानांतरण को क्रियान्वित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश में काम करने के लिये आन्ध्र प्रदेश उद्भव के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों को जो आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्र से अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, उन को स्थानान्तरण की अनुमति देने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). रेलवे कर्मचारियों के आंकड़े न तो राज्य-वार रखे जाते हैं और न ही उन्हें राज्यों के आधार पर भर्ती किया जाता है। अपनी इच्छा के स्थानों को भेजने के लिये गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और जहां तक संभव होता है, माना जाता है ।

कोट्टयम में डाक-घर की इमारत

†२२४२. **श्री मणियंगाडन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कोट्टयम में वर्तमान इमारत, जहां मुख्य डाक घर है, बहुत पुरानी है और वर्तमान संख्या में कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त है ;

(ख) क्या वहां डाकघर के लिये नई इमारत बनाने का एक प्रस्ताव था ;

(ग) क्या उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो यह अब किस प्रावस्था में है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) स्थान प्रतीक्षित है जिस के बाद प्राथमिक नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार भवन

†२२४३. **श्री मणियंगाडन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि केरल के उच्च रेंज प्रदेश में अधिकांश इमारतें, जहां डाक घर हैं, पुरानी हैं और भग्न दशा में हैं ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में डाक तथा तार घरों के लिये नई इमारतें बनाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : (क) पहाड़ी क्षेत्रीय प्रदेश में २० डाकघरों में से चार की इमारतें पुरानी हैं परन्तु भग्न अवस्था में नहीं हैं । उन में से तीन विभागीय हैं और एक किराये की है ।

(ख) और (ग). तीन विभागीय इमारतों के पुनर्निर्माण के लिये कदम उठाये गये हैं। किराये वाली इमारत के मालिक से मरम्मत-कार्य पूरा कराने को कहा गया है ।

विजयवाडा के समीप रेलवे पुल

†२२४४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाडा के समीप कृष्णा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण-कार्य लक्ष्य के अनुसार चल रहा है ;

(ख) मार्च, १९६२ के अन्त तक कितना रुपया व्यय किया गया है ; और

(ग) इस के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४·२० लाख रुपये ।

(ग) वर्ष १९६४ के अन्त तक ।

बाढ़ के पानी को निकालना

†२२४५. **श्री गो० महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले वर्ष उड़ीसा के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बाढ़ समस्या का सर्वोत्तम समाधान इकट्ठा हुए बाढ़ के पानी को निकालना है ;

(ख) क्या इकट्ठा हुए बाढ़ के पानी को बाहर निकालने की कोई योजना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बाढ़ समस्या के लिये प्रधान मंत्री द्वारा सुझाये गये समाधान को किसी विशेषज्ञ निकाय को विचारार्थ भेजने की संभावना पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा की बाढ़ समस्या का उड़ीसा बाढ़ जांच समिति द्वारा व्यापक रूप से परीक्षण किया जा रहा है। समिति, निस्संदेह, उड़ीसा की बाढ़ समस्या के समाधान के लिये अपनी सिफारिशें देते समय बाढ़ के पानी को निकालने पर भी विचार करेगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नये डाक घर

†२२४६. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में सभी राज्यों में (राज्य-वार) कितने नये डाक-घर खोले गये हैं ; और

(ख) ऐसे डाक-घर खोलने के लिये राज्यों से (राज्य-वार) कितनी प्रार्थनायें प्राप्त हुईं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

†२२४७. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में प्रत्येक राज्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये ; और

(ख) उन के लिये प्रत्येक राज्य से कितनी प्रार्थनाएं प्राप्त हुईं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]

भारत में रक्षित बैंक द्वारा किसानों को ऋण

†२२४८. **श्री द० ब० राजू** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक द्वारा किसानों को राज्य सहकारी बैंकों के जरिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिये जाने के बारे में क्या तरीका अपनाया गया है ; और

(ख) किसानों से उस ऋण की वसूली के लिये भारत के रक्षित बैंक व राज्य सहकारी बैंकों को क्या निदेश दिये हैं ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]

(ख) भारत के रक्षित बैंक व कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किये हैं। किसानों से ऋण की वसूली राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के उपबन्धों, उन के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और सहकारी संस्थाओं के उपनियमों के आधार पर की जाती है। मूल ऋणी के रूप में राज्य सहकारी बैंक रक्षित बैंक को नियत तिथि पर या उस से पहले ऋण वापस कर देगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि एक राज्य सहकारी बैंक प्राप्त वसूली रक्षित बैंक को देगा, रक्षित बैंक समझता है कि राज्य सहकारी बैंक को इस के केन्द्रीय बैंकों से कृषि ऋण की बकाया रकम किसी भी समय

†मूल अंग्रेजी में

रक्षित बैंक को देय राशि से कम नहीं होगी। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक को प्राथमिक समितियों की बकाया रकम केन्द्रीय बैंक के राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेने की रकम से कम नहीं होगी ।

रक्षित वन क्षेत्र, त्रिपुरा

†२२४९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूरी रक्षित वन क्षेत्र, त्रिपुरा में नये सीमांकन में वह भूमि भी शामिल है जो त्रिपुरा के झूमिया पुनर्वास विभाग द्वारा धर्मटीला क्षेत्र में आदिमजाति झूमियों को आवंटित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने पुनर्वासित परिवारों पर इस का असर पड़ने जा रहा है ; और

(ग) रक्षित वन क्षेत्र में भूमि के शामिल हो जाने से झूमियां परिवारों को बेदखली से बचाने के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) ग्यारह ।

(ग) इन परिवारों को वन ग्रामीणों के रूप में वहां पर रखने का प्रबंध किया जा रहा है ।।

जोगिन्दर नगर-बरोत सड़क

†२२५०. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोगिन्दरनगर बरोत सड़क का निर्माण किस क्रम पर पहुंच गया है ;

(ख) १९६१–६२ में इस पर कितना धन व्यय किया गया और १९६२–६३ में कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मोटर चलने वाली सड़क के द्वारा घटसानी और तुई होकर जोगिन्दर नगर तथा बरोत को मिलाने का प्रस्ताव है। इसमें से जोगिन्दर-नगर-घटसनी भाग, (९ मील) जो पठानकोट-कुलु सड़क का अंग है, पर अभी मोटरें चलने योग्य हैं। घटसनी-झाटीनगरी-तुई-बोरात मार्ग १९ मील लम्बा है। इसमें से पहले पांच मील में जीप चल सकती है तथा शेष १४ मील की चौड़ाई जीप चलाने योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश प्रशासन की तीसरी पंचवर्षीय योजना में घटसनी से बरोत तक का समस्त मार्ग चौड़ा किया जा रहा है।

(ख) १९६१–६२ में व्यय की गई राशि: ५,४६० रुपये १९६२–६३ में खर्च की जाने वाली राशि : १,२०,००० रुपये ।

(ग) आशा है कि मार्च १९६६ के अन्त तक पूरी सड़क पर मोटरें चलने लगेंगी।

देहाड़—तत्ता पानी सड़क

†२२५१. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहाड़-तत्तापानी–रामपुर–बुशहर सड़क का निर्माण किस क्रम पर पहुंच गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक इस पर कितना धन व्यय किया गया तथा १९६२-६३ में कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्री(श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४**]

मद्रास में भेड़ों की नस्ल बढ़ाना तथा ऊन अनुसंधान केन्द्र

†२२५२. **श्री मलाइ छामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कोडाई कनाल में भेड़ की नस्ल बढ़ाना तथा ऊन अनुसन्धान केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र को आरम्भ करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां । कोडाई कनाल के निकट केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्था का एक उपकेन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) उपकेन्द्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण, स्वीकृति तथा स्थान पर विचार किया जा रहा है ।

गोबर

†२२५३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष बहुत सा गोबर खाना बनाने के लिए किसान जला डालते हैं जब कि इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कृषि भूमि की उपज बढ़ाने वाली खाद का अपव्यय रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के कहने पर राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों व गोबर समेत स्थानीय रूप से उपलब्ध स्थानीय खाद साधनों का अधिकतम उपयोग करने के निम्न कार्य किये हैं :—

(१) राज्य सरकारों आदि ने अपनी राज्य की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से खाद बनाने समेत स्थानीय खाद साधनों का अधिक तथा अच्छा उपयोग करने की योजना शामिल कर ली है । इस योजना के अधीन किसानों को गोबर समेत स्थानीय खाद साधनों का उपयोग करने की टेक्नीक का प्रशिक्षण दिया गया है ।

(२) गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग रोकने के लिए गोबर गैस संयंत्र की स्थापना का प्रचार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । सौ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में से प्रत्येक में एक गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं जिससे किसानों को उसके लाभ बताये जा सकें ।

(३) गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग कम करने के लिए तथा जलाने वाली लकड़ी की कमी पूरा करने के लिए तीसरी योजना में फार्म वन विभाग की योजना शामिल की गई है । इस योजना के अधीन सामुदायिक विकास संगठन तथा राज्य कृषि विभाग

---

†मूल अंग्रेजी में

की सक्रिय सहायता से गांवों की श्यामलाती तथा बंजर जमीन में शीघ्र उगने वाली लकड़ी के पौदे उगाये जा रहे हैं । गांव वासियों के ऐच्छिक श्रम के द्वारा यह पेड़ उगाने का विचार है । राज्य वन विभाग प्रविधिक परामर्श देने के लिए तथा बाग बनाने के लिए बाग की आवश्यक सामग्री देगा ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

२२५४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी अनुभव की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बिजल की अधिकता लाने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां । उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली की कमी है ।

(ख) उत्तर प्रदेश को तृतीय पंचवर्षीय योजना में कई विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं । इन स्कीमों के लिए १०८.३५ करोड़ रुपये की योजना व्यवस्था की गई है ।

दिल्ली के किसान

२२५५. **श्री सूरज मल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगान न देने के कारण दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में १९६०–६१ में कितने किसान गिरफ्तार किये गये ;

(ख) इनमें से कितने किसानों को दंडित किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अनेक किसानों के पास अलाभकर जमीनें हैं ; और

(घ) क्या जो किसान जेल भेजे गये थे उनके परिवारों के भरणपोषण के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभ सिंह) : (क) एक ।

(ख) कोई नहीं, ज्योंकि गिरफ्तारी के पश्चात् शीघ्र ही अदायगी कर दी गई ।

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के पास अलाभकर जमीन थी ।

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार प्रश्न ही नहीं होता ।

आंगोल नस्ल के सांड

†२२५६. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से देश अंगोल नस्ल के सांडों का आयात करते हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों में इस व्यापार से कितनी रकम मिली ; और

(ग) इसी अवधि में कितने पशुओं का निर्यात किया गया ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ख). गत पांच वर्षों में ब्राजील ने ही केवल अ गोल नस्व के सांडों का आयात किया है । २६,००० रुपये पर पांच सांडों का आयात किया गया था । भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन कम्बोडिया को ४,२४० रुपये के

†मूल अंग्रेजी में

चार सांड उपहार में दिए थे। हाल में ही ब्राज़ील ने १२,२०० रुपये की लागत में नौ और ओंगोल नस्ल के सांड खरीदे हैं और अब वह जहाज़ पर लादे जाने वाले हैं।

(ग) १३१३ पशु, १००१ पशु और ३१२ भैंस।

केरल में 'पैकेज' योजना

†२२५७. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाद्यान्नों के विस्तृत उत्पादन के लिए "पैकेज" योजना आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) राज्य में योजना के अन्तर्गत कौन कौन से क्षेत्र लाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभ सिंह)** : (क) जी हां। केरल राज्य में गहन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) की क्रियान्विति के लिए चुने गये पालघाट तथा आल्लप्पि के दो ज़िलों में आरम्भिक कार्य हो रहा है। जब योजना खेतों में लागू होगी उस समय खरीफ की फसल, १९६२ के विभिन्न निम्न आरम्भिक कार्य पूरे करने की आशा है :—

१. पहले तथा बाद के अन्य वर्षों में कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए ज़िले में क्षेत्र का चुनाव;

२. योजना के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सहकारी संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना ;

३. किसानों तथा गैर सरकारी ऐजेन्सियों जैसे पंचायत, सहकारी समितियों में योजना में भाग लेने के लिए जागृति उत्पन्न करना ;

४. अतिरिक्त कर्मचारियों का चुनाव, नियुक्ति, तथा पोस्टिंग ;

५. कर्मचारियों का प्रशिक्षण ;

६. साधन तथा उत्पादन चिह्न सर्वेक्षण का गठन ;

७. संभरण की आवश्यकता का निर्धारण ; और

८. भाण्डार गोदामों का निर्माण तथा किराये पर लेना ।

(ख) प्रथम वर्ष अर्थात् १९६२–६३ में कार्यक्रम के अधीन पालघाट के १५ ब्लाकों में से ५ के तथा आल्लप्पि में १७ ब्लाकों में से ५ में इसके लागू करने का विचार है।

ऊना–हमीरपुर सीधी ट्रंक लाइन

†२२५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के दूरस्थ पहाड़ी पिछड़े क्षेत्र के ऊना और हमीरपुर में सीधी ट्रंक टेलीफोन लाइन नहीं है जब कि इन में तीन खण्ड मुख्यालय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) यातायात इतना नहीं है कि इतना धन व्यय किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में आयुर्वेदिक संस्थायें

†२२५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न आयुर्वेदिक संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में पजाब की किसी आयुर्वेदिक संस्था को सीधे तौर पर अनुदान नहीं दिया था। चिकित्सा की देशी पद्धति के विकास के लिए १९५९–६० तथा १९६०–६१ के प्रत्येक वर्ष के लिए १.७४ लाख रुपये का आवंटन पंजाब सरकार के लिए किया गया था।

'लक्जरी कोल सर्विस'

†२२६०. **श्री राम हरक यादव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और लखनऊ के बीच हाल में ही एक 'लग्जरी कोच बस सर्विस' लागू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस व्यय में कुछ अंशदान दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** (क) से (ग). परिवहन तथा संचार मंत्रालय को मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और लखनऊ के बीच कोई लक्जरी कोच बस सर्विस चालू की है और उस पर कितना धन व्यय हुआ है। केन्द्र इस प्रकार की सेवाओं के लिए अंशदान नहीं देता है।

बिहार में राष्ट्रीय राजपथ

†२२६१. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पूर्निया ज़िले में वर्तमान सड़क संख्या १ भाग २ को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण की परियोजना के लिए स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** (क) और (ख). संभवतया माननीय सदस्य बिहार के पूर्निया ज़िले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ के एक भाग के संबंध में पूछ रहे हैं। इस भाग में कुरसेला और फुलबेरिया के निकट कोसी. पुल बनने के स्थान से लगभग १७ मील तक सड़क नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ऋण कार्यक्रम के अधीन यह सड़क का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसके सितम्बर १९६४ तक पूरे हो जाने का निर्धारण किया गया है।

(ग) मिट्टी के प्रकार की जांच हो रही है। कुछ भाग पर मिट्टी का काम आरंभ कर दिया गया है।

बिहार मे पुल

†२२६२. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पूर्निया ज़िले में दिगराहा नदी पर पुल बनाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल तक पहुंचने वाली सड़कों के लिए कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार कब निर्माण कार्य करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां । महानन्द नदी पर डिगरा-धार में एक पुल पूरा होने का है।

(ख) सड़कें भी बन रहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

बिहार में विद्युत् संभरण

†२२६३. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई कर्यक्रम बनाने का निर्णय किया है जिसके द्वारा बिहार राज्य के पूर्निया ज़िले में उद्योग, कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योग के लिए विद्युत उपलब्ध की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में बरौनी थरमल स्टेशन तथा कोसी हाइडल परियोजना के चालू हो जाने पर उत्तर बिहार ग्रिड से पूर्निया ज़िले को बिजली का संभरण होगा ।

नंगल बांध म रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२२६४. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में नंगल बांध के रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाये गये थे ; और

(ख) १ अप्रैल, १९६२ को आवंटन के लिए कितने कर्मचारी प्रतिक्षा सूची में थें ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ५७ (ख) ३० ।

मद्रास राज्य में मैडिकल कालिज

†२२६५. **श्री इलयापेरुमाल** : (क)क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मद्रास राज्य में तीसरी योजना में नये मैडिकल कालिज स्थापित करने के लिए प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने मद्रास सरकार को क्या परामर्श दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) वित्तीय कठिनाइयों, अर्ह चिकित्सा अध्यापकों आदि के कारण मद्रास सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में कोई नया मैडिकल कालिज खोलने का नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

†२२६६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में डाक तथा तार के कितने कर्मचारियों को सरकारी मकान दिए गए हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : ९३४ ।

समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलना

†२२६७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान मद्रास नगर निगम के मेयर के समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलने के कथित प्रयत्नों और इस संबंध में अमरीकी सहायता हासिल करने के प्रयत्नों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी योजना की संभावनाओं का और संभावित लागत का पता लगाया है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से क्वार्टरों का किराया

†२२६८. **श्री गौरी शंकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पुराने 'के' टाइप रेलवे क्वार्टरों का किराया पहले ५ रुपये महीना था जिसको बढ़ा कर ६ रुपये २५ नये पैसे किया गया तथा बाद को १ अक्तूबर १९६१ को बढ़ाकर १८ रुपये २२ नये पैसे कर दिया गया ; और

(ख) किराये की गणना का क्या आधार है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). एक विवरण संबंद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]** ।

साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात

†२२६९. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यु और उसके आस पास के इलाके में बन्दर उत्पात करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या क़दम उठाने का है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका बन्दर पकड़ने के विशेषज्ञ, जिनके पास बन्दर पकड़ने के उपकरण हों, की खोज कर रही है ।

नागार्जुनसागर परियोजना स्थान पर मजदूर

†२२७०. **श्री लक्ष्मी दास** : क्य **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नागार्जुनसागर परियोजना स्थान पर मजदूरों को

---

†मूल अंग्रेजी में

सप्ताह में केवल ३ या ४ दिन कार्य मिलने की कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) मजदूरों को निरन्तर काम देने के लिए और राष्ट्रीय परियोजना को समय पर समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मजदूरों को निरन्तर काम दिया जा रहा है ।

नलागढ़ समिति

†२२७१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के ढंगों के बारे में नलागढ़ समिति की सिफारिशें स्वीकार हो गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: कृषि प्रशासन समिति (नलागढ़ समिति) ने कृषि-उत्पादन बढ़ाने के ढंगों की कोई सिफारिश नहीं की । समिति की सिफारिशें मुख्यकर राज्यों में कृषि विभागों के प्रशासन में सुधार करने, कृषि विभागों के कर्मचारियों के वेतन-क्रम बढ़ाने और सेवा की शर्तों में सुधार करने, अस्थायी पदों को स्थायी बनाने, वित्तीय प्रक्रिया को सरल बनाने, सभी स्तरों पर पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासी अधिकार देने, राज्यों में कृषि और अन्य विकास विभागों में प्रभावी ताल मेल कराने, आदि के बारे में थी । साधारणतया ये सिफारिशें भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्वीकार कर ली हैं ।

बन्देल (पश्चिम बंगाल) में विद्युत् संयंत्र

†२२७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्देल (पश्चिम बंगाल) में एक नये विद्युत यंत्र के लिए अमरीका से चार बड़े बायलरों का आयात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) यंत्र और पुर्जे आदि का आयात 'एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट यू० एस० ए०' से उनकी सामान्य प्रक्रियानुसार किया जा रहा है । भुगतान की शर्तें ये हैं कि जहाजरानी इन्वाइस देने पर ६५ प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, २५ प्रतिशत भुगतान बिल आफ लेडिंग देने पर किया जायेगा और शेष १० प्रतिशत भुगतान स्वीकृति प्रमाण पत्र देने पर किया जायेगा । यह भुगतान प्रव्यय पत्र द्वारा होगा ।

असम में बिजली

†२२७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में बिजली की तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए असम सरकार को डीज़ल इंजनों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने इंजनों का आयात होगा और उनका कितना मूल्य होने का अनुमान है; और

(ग) उनका आयात किस देश से होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). लगभग ३६ लाख रु० के मूल्य के बिजली बनाने के सतरह डीज़ल इंजन चैकोस्लोवाकिया से और ११ लाख रु० के अनुमानित मूल्य पर तीन इंजनों का आयात जर्मनी से होगा । इन मशीनों की कुल क्षमता लगभग ११·४ मेगावाट होगी ।

'बॉक्स' प्रकार के वैगनों का निर्माण

†२२७४. **श्री प्र० के० देव :**
श्री यो० ना० सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में आइओ को वर्कशाप ने बॉक्स जैसे वैगन बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कब आरम्भ होगा ;

(ग) देश में बॉक्स जैसे वैगनों की कितनी वार्षिक आवश्यकता है; और

(घ) आजकल देश में कितने वैगन बनते हैं और कहां बनते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां ।

(ख) उत्पादन अभी आरम्भ हुआ है ।

(ग) तीसरी योजना के अनुसार योजना के अन्त तक अतिरिक्त यातायात के लिए बॉक्स जैसे १८,०२५ वैगनों की आवश्यकता होगी जिनमें से १४,६८ इस्पात कारखानों की आवश्यकता के लिए होंगे और १६,५५७ इस्पात उद्योग अतिरिक्त अन्य यातायात के लिये होंगे ।

(घ) लगभग ४५० वैगन प्रति मास बनते हैं । बॉक्स जैसे वैगन बनाने वाले गैर-सरकारी कारखानों और रेलवे वर्कशापों के नाम निम्न विवरण में दिये हैं ।

विवरण

गैर-सरकारी वैगन निर्माता

१. मैसर्स बर्न एण्ड को०, कलकत्ता ।
२. मैसर्स आई० एस० डब्ल्यू०, कलकत्ता ।
३. मैसर्स जैसपस् एण्ड को०, कलकत्ता ।
४. मैसर्स ब्रेथवाइट्स, कलकत्ता ।
५. मैसर्स टेक्समेको कलकत्ता ।
६. मैसर्स बालमेर लौरी, कलकत्ता ।
७. मैसर्स के० टी० स्टील, बम्बई ।
८. मैसर्स सदर्न स्ट्रक्चरल, मद्रास ।
९. मैसर्स मेकन्जीज़, बम्बई ।

रेलवे वर्कशाप

१. मध्य रेलवे, लल्लागुडा ।
२. पश्चिम रेलवे, महालक्ष्मी ।
३. दक्षिण रेलवे, गोल्डन एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. पूर्व रेलवे, कंचरापाड़ा ।
५. उत्तर रेलवे, अमृतसर ।

उड़ीसा में इन्द्रावती जल-विद्युत् परियोजना

†२२७५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहन्डी जिले में इन्द्रावती जल विद्युत् परियोजना की प्रारम्भिक जांच पड़ताल आरम्भ हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी विद्युत् क्षमता होगी और उस पर लगभग कितना व्यय होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) परियोजना को विद्युत्-क्षमता ६० प्रतिशत भार पर १०० मेगाबाट होने का अनुमान है । परियोजना पर होने वाला व्यय लगभग केवल जांच पड़ताल पूरी होने और परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर मालूम होगा ।

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

†२२७६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति और नारियल समिति की कार्यवाही मिलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष १९५६ में एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने, जिसके सभापति भारत सरकार के तात्कालिक कृषि आयुक्त, डा० वी० एन० उप्पल थे, इस प्रश्न पर विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां ।

(घ) उपसमिति ने इन दो समितियों को पूर्व स्थिति को बनाये रखने की और इस बात को सिफारिश की थी कि जहां कहीं सम्भव हो दोनों समितियों को वैज्ञानिक कार्य में प्रभावी तालमेल लाने का प्रयास करना चाहिये ।

कलोल से मेहसाना तक दोहरी लाइन

†२२७७. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में पश्चिम रेलवे पर कलोल से मेहसाना तक लाइन दोहरी करने के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले वर्ष इस राशि में से कितना धन व्यय हुआ;

(ग) वर्ष १९६२–६३ में इसी कार्य के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस कार्य के कब पूरा होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १२ हजार रु० ।

(ख) १२ हजार रु० ।

(ग) १८ लाख रु० ।

(घ) मार्च, १९६४ तक ।

बसों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं को रोकने का यंत्र

†२२७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूआं छोड़ने वाली बसें रोकने के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम ने एक इलैक्ट्रानिक यंत्र प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो बहुत अधिक धूआं देने वाली कितनी बसें अब तक रोकी गई हैं; और

(ग) सड़क पर चलने वाली ऐसी सारी बसों को रोकने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) से (ग). दिल्ली परिवहन उपक्रम ने एक डीजल की बस पर इलैक्ट्रानिक यंत्र की परीक्षा की थी । बस से धूआं निकलना रोकने में यंत्र के सफल न रहने पर इस का प्रयोग छोड़ दिया गया ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२२८०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा (दिल्ली) मे रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ उन्हें भी दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली

२२८०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा (दिल्ली) स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से लाभान्वित किये जाने की मांग करते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शेर के बच्चे

†२२८१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के चिड़ियाघर की एक शेरनी के बच्चों को कुतिया से दूध पिलाना पड़ा, लेकिन फिर भी वे बचाये न जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नत्थी है ।

विवरण

दिल्ली चिड़ियाघर की "अशरफी" नामक एक शेरनी ने ७ मई, १९६२ को उपेक्षित समय से १५ दिन पहले ३ बच्चों को जन्म दिया । उसने अपने नवजात शिशु में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उससे माता की जिम्मेदारियों को सम्भालने के लिये किये गये सभी प्रयास असफल रहे । इस बात का डर था कि कभी बच्चे भूखे न मर जायें या शेरनी द्वारा ही न मारे जायें । अतः बच्चों को उनकी माता से अलग कर दिया गया और इसके पश्चात् एक धात्री माता के लिये तलाश शुरू की गई । इस कार्य के लिये एक "लेब्राडोर" कुतिया जिसने एक दिन पहले ही एस० पी० सी० ए० हस्पताल में बच्चों को जन्म दिया था, को उपयुक्त समझा गया । कुतिया ने भी शीघ्र ही तीनों बच्चों को ग्रहण कर लिया । इन में से दो बच्चे जो बहुत कमज़ोर थे हस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरतने के बावजूद भी अपनी शारीरिक गर्मी को खो बैठे और ९ मई, १९६२ को प्रातःकाल ही मर गये । इसके पश्चात् जब कुतिया का दूध भी सूख गया तब बोतल द्वारा उपचार शुरू किया गया । तीसरे बच्चे पर उपचार और यथासमय देखभाल का अच्छा असर हुआ और वज़न में कुछ सुधार दिखाई दिया परन्तु बाद में १६ मई, १९६२ को प्रातःकाल यह बच्चा भी मर गया । ऐसा समझा गया कि यह बच्चा भी शारीरिक गर्मी खो बैठा था ।

यह समय पूर्व जनन का मामला था अतः शुरू में भी उनके बचने की कोई आशा नहीं थी फिर भी बच्चों को बचाने के लिये भरसक यत्न किये गये ।

असम में जल संभरण योजनाएं

†२२८२. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के जिला दारवींग में के एक नलकूप तगंला में और दूसरा आडलवी में, जो पूरे और गहरे हैं, एवं भारत सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत बने हैं, बेकार पड़े हैं, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने पानी के नलों को रेलवे लाइन के पार ले जाने की अनुमति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को लागू करने और व्यक्तियों को कुंओं के उपलब्ध पानी का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर राष्ट्रीय राजपथ

†२२८३. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर असम में राष्ट्रीय राजपथ के पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने राजपथ का कार्य कब आरम्भ किया था और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि जनता के विरोध करने पर भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जिला कामरूप में राजपथ के लिये एक ऐसी जमीन प्राप्त करने का विचार कर रहा है जिस पर हावली में नाम कर (पवित्र स्थान) है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) शायद प्रश्न उत्तर सामरा में ब्रह्मपुत्र पुल को राष्ट्रीय राजपथ ३१ से मिलाने वाली सड़क के बारे में है। इस सड़क के बनाने में लगभग पांच वर्ष लगेंगे ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नहीं अपितु असम लोक निर्माण विभाग परियोजनाओं का प्रभारी विभाग हैं। पुल के लिये स्थान के सर्वेक्षण और जांच पड़ताल वर्ष १९६१ में आरम्भ हुई थी। सड़क का निर्माण अभी तक ब्रह्मपुत्र पुल के पास पहिले कुछ मीलों को छोड़ कर, आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा और निवेदन किया जायेगा कि यदि संभव हो तो नामगढ़ को प्राप्त न किया जाये ।

ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर डिब्रूगढ़ तक रेल मार्ग

†२२८४. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में ब्रह्मपुत्र की दक्षिण की ओर विद्यमान रेलवे लाइन पर विद्रोही नागाओं के छापों के कारण होने वाली निरन्तर रुकावट को ध्यान में रख कर ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर डिब्रूगढ़ तक वैकल्पिक रेलवे मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

†२२८५. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और असम के बीच जहाजरानी करने वाली 'रिवर एण्ड स्टीम नेवीगेशन कंपनी' में कुल कितने चालक कार्य करते हैं;

(ख) वे किस देश के नागरिक हैं ;

(ग) जहाजों पर कितने भारतीय काम कर रहे हैं; और

(घ) जहाजों को पाकिस्तान-क्षेत्र में कितनी दूरी पार करनी होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ३३३९ ।

(ख) ३३४ भारतीय और ३००५ पाकिस्तानी ।

(ग) ३३४ ।

(घ) ८३६ मील ।

खम्भात की खाड़ी

†२२८६. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल संबंधी समिति ने खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण करने का लगभग ८ वर्ष पहिले निश्चिय किया था;

(ख) क्या वर्ष १९५६ में खाड़ी का सर्वेक्षण करने और उसे लगभग दो वर्ष में समाप्त करने का निश्चय पुनः किया गया था ;

(ग) क्या सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) से (ङ). जल संबंधी समिति ने वर्ष १९५६ में पहिली बार सिफारिश की थी कि खम्भात की खाड़ी का प्रगति सर्वेक्षण कार्य के लिये सर्वेक्षण पोत उपलब्ध होते ही आरम्भ किया जा सकता है। समिति ने सर्वेक्षण के पूरे होने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। समिति इस सर्वेक्षण को बाद में किसी सर्वेक्षण मौसम के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने इसकार्य को अन्य कार्यों की अपेक्षा निम्न प्राथमिकता का कार्य समझा। अगस्त, ६१ में समिति की पिछली बैठक में समिति ने खम्भात की खाड़ी के सर्वेक्षण के प्रश्न पर पुनः विशेष रूप से विचार किया और उन्होंने इसे वर्ष १९६१–६२ के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने जो समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि था, विचार विमर्श में भाग लिया। राज्य सरकार ने पुनः प्रार्थना की है कि वर्ष १९६२–६३ के सर्वेक्षण मौसम में सर्वेक्षण किया जाये। उन्हें सूचित किया गया है कि यह मामला जल संबंधी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। आशा है कि आगामी बैठक निकट भविष्य में होगी।

ग्रामीण डाक सेवा

†२२८७. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में डाकखाने खोलने की योजना से कुशल सेवा में कितनी सहायता मिली है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण डाक सेवा में सुधार करने के मार्गोपाय निकाले हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि जोरहाट में डाक खाने की इमारत फिर से बनाने का कोई प्रस्ताव है तो उसमें कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डाकखाने खुल जाने से गांवों में डाक के वितरण की बारमबारता काफी बढ़ गई है और एक डाकखाने में आने वाला क्षेत्र तथा जनसंख्या बहुत कम हो गई है। बिना डाकखाने के गांवों की संख्या मिटाने में काफी प्रगति हुई है और ग्रामवासियों को सरलतापूर्वक मिलने वाली डाक सुविधायें दी गई हैं।

(ख) हां, अनेक उपाय अपनाये गये हैं, जैसे केन्द्र रूप में स्थित ब्रांच डाकखानों को सब पोस्ट आफिस बनाना। इनका उद्देश्य ग्रामीण डाकखानों के लिये डाक तथा वित्तीय प्रबन्ध में सुधार करना, डाक को तेजी से ले जाने के लिये मोटर मार्गों का उपयोग करना गांवों में डाक के वितरण की बारम-बारता का कुछ स्तर निर्धारित करना और अतिरिक्त विभागीय ब्रांच पोस्ट मास्टरों को प्रशिक्षण देना है।

(ग) मामला पहिले से ही विचाराधीन है, और काम के करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि ड्राइंग, प्राक्कलन, आदि तैयार करने की कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही अभी पूरी होनी है।

पेड़ों के रोग

†२२८८. **श्री वारियर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उद्देश्य से कोयम्बटूर में एक अनुसन्धान संस्था की स्थापना करने का विचार है कि पेड़ों के, विशेषकर चन्दन की लकड़ी के रोगों का अध्ययन किया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) दूसरी योजना काल में एक क्षेत्रीय वन अनुसन्धान केन्द्र पहिले ही बनाया जा चुका है। कोयम्बटूर में इस का एक बाइलाजीकल विंग है जिस में रेशम-कीट पालन, भूविज्ञान, वन-बनस्पति, वनशरीविज्ञान और वन-मैथालाजी संबंधी अनुसन्धान कार्य होगा। इस में चन्दन की लकड़ी के रोग भी शामिल हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[illegible]

†२२८९. **श्री वारियर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम में प्रशिक्षण स्कूल में कुशल कारीगरों में से कुछ को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें बाद-कोचीन में बनने वाले प्रस्तावित शिपयार्ड में रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो चुनाव करने का क्या तरीका है; और

(ग) अब तक कितने व्यक्ति चुने गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम के परामर्श से एक योजना बनाई जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में दूध की कमी

†२२९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्मियों में दिल्ली में दूध की बहुत कमी हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गर्मियों में दूध के दाम बहुत बढ़ जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां। यह सच है कि गर्मियों के महीनों में कुल संभरण में कमी हो जाती है।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये भाव में वृद्धि नहीं की जाती ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ·

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के 'स्काईमास्टर' विमान

†२२९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के ५ 'स्काईमास्टर' विमानों के बेड़ों में से तीन सेवा में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन 'स्काईमास्टर' विमानों के स्थान पर अन्य विमान लगाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो 'स्काईमास्टर' विमानों को, जो बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गये हैं, बदलने का प्रश्न इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विचाराधीन है ।

गवेषणा, प्रारूप और मानक संगठन, शिमला में अनुसूचित जाति के पदाधिकारी

†२२९२. **श्री ज्योतिस्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवेषणा, प्रारूप और मानक संगठन (आर० डी० एस० औ०), शिमला में १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों के अनुसार टैक्निकल तथा नान-टैक्निकल एवं असिस्टेंट ग्रेड (क्लर्कस) स्थानों पर कितने अनुसूचित जातियों के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि एक भी नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अफसरों या सहायकों के किसी पद पर अनुसूचित जातियों का कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। लेकिन तकनीकी या क्लर्क ग्रेड की कुछ अराजपत्रित जगहों पर अनुसूचित जातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं जो उनके लिये आरक्षित कोटे के अनुसार भर्ती किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तकनीकी और गैर-तकनीकी अफसरों और सहायकों की सभी जगहें या तो अनुसंधान, खाका और मानक संगठन के निचले ग्रेड के कर्मचारियों को तरक्की देकर भरी जाती हैं या अन्य रेलों से बदल कर उन पर ऐसे प्रवर रेल-कर्मचारी लगाये जाते हैं जो इस संगठन के विशेष प्रकार के काम के लिये उपयुक्त समझे जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

†२२९३. **श्री ज्योतिस्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के गवेषणा कार्य में अनुसूचित जातियों के लिये पर्याप्त संरक्षण है ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थान संरक्षित हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) से (ग). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् समस्त भारत में कृषि तथा पशुचिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, मार्गदर्शन तथा समन्वय करने का कार्य करती है। परिषद् के मुख्य कार्यालय में नियुक्त तकनीकी स्टाफ अनुसंधान योजनाओं की देख भाल करता है। यह राज्य सरकारें, केन्द्रीय संस्थायें आदि जो कि कृषि पशुपालन अनुसंधान सम्बन्धी कार्य का सफलतापूर्वक परिचालन करने, परिणामों को एकत्रित करने तथा उनका समन्वय करने का कार्य करती हैं, उनका मार्गदर्शन भी करता है। परिषद् के अधीन अनुसंधान संस्थायें नहीं हैं और न ही वास्तविक अनुसंधान कार्य करने के लिये यह अपने स्टाफ की नियुक्ति करती हैं। वास्तविक अनुसंधान कार्य राज्यों के कृषि पशुपालन विभाग, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थायें, विश्वविद्यालय और कुछ गैर-सरकारी संस्थायें करती हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वित्तीय सहायता देती है। यह राज्य सरकारों आदि का कार्य है, जोकि वास्तविक अनुसंधान कार्य कर रही हैं तथा जिन के अधीन अनुसंधान कार्यकर्ता कार्य करते हैं कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व का उचित अनुपात कायम रखें।

फाइलेरिया का उन्मूलन

†२२९४. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री महेश्वर नायकज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये क्या प्रमुख कदम उठाये जायेंगे ;

(ख) इसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितना धन खर्च किया गया है ; और

(घ) फाइलेरिया से मुख्यत: कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तकनीकी कारणों से फाइलेरिया का इस

---

†मूल अंग्रेजी में

समय उन्मूलन करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, रोग को रोकने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उठाये जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(१) केवल नगरीय क्षेत्रों में कीड़ों के अंडे नष्ट करने वाला तेल छिड़क कर फाइलेरिया पर नियंत्रण किया जायेगा :

(२) जनसंख्या के आधार पर नियंत्रण यूनिटों का पुनर्गठन।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान करने और फाइलेरिया को रोकने के लिये उपयुक्त तरीके निकालने के लिये प्रत्येक राज्य में अनुसंधान-एवं-प्रशिक्षण यूनिटों की स्थापना।

(४) राज्य स्वास्थ्य निदेशालय में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना।

(५) कोझिकोड, केरल की तरह के केन्द्र के आधार पर तीन और प्रक्षिण-एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना।

(६) अस्पतालों में छ : फाइलेरिया रुजालय स्थापित करना।

(७) केरल राज्य में मालायी फाइलेरिया पर नियंत्रण के लिये बृहत् योजना।

(८) स्वास्थ्य शिक्षा।

(९) दीर्घकालीन उपाय के रूप में उपयुक्त जल-निस्सारण व्यवस्था।

(ख) २३६.६१ लाख रुपये।

(ग) लगभग ४२ लाख रुपये।

(घ) फाइलेरिया से मुख्यतः प्रभावित क्षेत्र हैं :

आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, मध्य द्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्कदीव और मिनिकाय द्वीपसमूह और पांडिचेरी।

उरई से जालौन (उ० प्र०) तक रेलवे लाइन

२२९५. **श्री राम सेवक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :।

(क) क्या यह सच है कि जिला जालौन (उ० प्र०) में उरई से जालौन तक रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) जी नहीं।

(ख) उरई जालौन रेलवे लइन (१४ मील-बड़ी लाइन) की यातायात सर्वे रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि यह लाइन अलाभप्रद होगी। इसलिये इसके बनाने का विचार छोड़ दिया गया।

पोखरायां और कानपुर (मध्य रेलवे) के बीच रेल की जंजीर खींचना

२२९६. **श्री राम सेवक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोखरायां और कानपुर (मध्य रेलवे) के बीच लगातार कई वर्षों

से जगह जगह पर जंजीर खींच कर गाड़ी खड़ी किये जाने की घटनायें प्रतिदिन घटती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र के निवासी जंजीर खींचे जाने से मना करने पर सरकारी कर्मचारियों पर हिंसात्मक हमले भी करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी हां । इस खण्ड के पामां और भीमसेन स्टेशनों के बीच खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें अक्सर होती रही हैं ।

(ख) हाल में इस प्रकार की घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । लेकिन पहले इस तरह की कुछ घटनायें हुई थीं कि जब बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गयी, तो उन्होंने पत्थर मारने आदि की हरकतें कीं

(ग) पुलिस अधिकारियों और रेलवे मजिस्ट्रेटों से प्रार्थना की गयी है कि इस खण्ड पर जांच का काम तेज़ किया जाये । टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की सहायता से उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिये विशेष छापे मारे हैं । भविष्य में इस तरह के और छापे मारने का विचार है ।

माताटीला बांध बिजलीघर

२२९७. **श्री राम सेवक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माताटीला बांध से कब तक बिजली प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) उस बिजलीघर से प्रति वर्ष कितनी बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) उससे उत्तर प्रदेश को कितने किलोवाट बिजली प्राप्त होगी तथा कौन से जिले उससे लाभान्वित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) (क) माताटीला बांध बिजलीघर के १९६३–६४ में चालू होने की सम्भावना है ।

(ख) बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता ३०,००० किलोवाट और वास्तविक उत्पादन क्षमता ६० प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग १६,००० किलोवाट होगी ।

(ग) इस बिजलीघर से उत्पन्न होने वाली सारी बिजली उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की जायेगी । झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा और कानपुर के जिले इससे लाभान्वित होंगे ।

रतलाम और मंडल के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की रफ्तार पर प्रतिबन्ध

†२२९८. **श्री का० रा० गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर-खंडवा सेक्शन पर रतलाम और मण्डल के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की रफ्तार पर जनवरी, १९६२ से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यात्री और मालगाड़ियों की क्रमशः रफ्तार-सीमा क्या है ;

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध इस लाइन पर लकड़ी के स्लीपर पुराने पड़ जाने के कारण है ;

(घ) यदि हां, तो समय पर उनको न बदलने के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इन प्रतिबन्धों के कारण इन स्टेशनों के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों पर कोयला के कुल अतिरिक्त दैनिक खपत, भार में, और मूल्य में कितनी है ;

(च) इस प्रतिबन्ध के कारण कर्मचारियों के दैनिक कितने अतिरिक्त घंटे लगते हैं ;

(छ) इस प्रतिबन्ध के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ;

(ज) रतलाम और मंडल के बीच स्लीपरों के बदलने के लिये कितनी लागत आयेगी ; और

(झ) यह बदलने का कार्य कब किया जायेगा और कब पूरा होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** । (क) जी, हां ।

(ख) यात्री और मालगड़ियों की रफ्तार-सीमा २५ मील प्रति घंटा है (सेक्शन रफ्तार ३५ मील प्रति घंटा है), परन्तु मीटर गेज की माल गाड़ियों की सामान्य रफ्तार केवल लगभग २५ मील प्रति घंटा है ।

(ग) इस लाइन पर खराब स्लीपर अधिक होने से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(घ) वर्ष १९६१–६२ में मीटर गेज़ के लगड़ी के स्लीपरों की भारी कमी ।

(ङ) लगभग २५ रुपये मूल्य का ९०० पौंड कोयला ।

(च) सभी गाड़ियों पर कुल समय की हानि ७।। खण्टा प्रति दिन है ।

(छ) मण्डल और चित्तोरगढ़ के बीच की लाइन बदलने का कार्यक्रम इस वर्ष पूरा करने की योजना है । बाकी भाग के लिये जैसे ही सामान मिल जायेगा, लकड़ी के स्लीपरों को बदला जायेगा । यदि आशानुकूल सामान मिलता रहा तो प्रतिबन्ध १९६३ के शुरू में हटा दिये जायेंगे ।

(ज) लगभग २६ लाख रुपये ।

(झ) यह सम्भरण की प्राप्ति पर निर्भर है और कोई तिथि अभी नहीं बतायी जा सकती ।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों का संभरण

†२२९९. **श्री का० रा० गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का कमर्शियल स्टाफ, जैसे गुड्स क्लर्क, बुकिंग क्लर्क और कोचिंग क्लर्क को पूर्वोत्तर रेलवे पर नियमित रूप से वर्दियां मिलती हैं बल्कि देश में किसी अन्य रेलवे में उन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दियां नहीं दी जातीं ;

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य रेलवे के कर्मचारियों को पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के समान बनाने के लिये एक प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां । परन्तु कुछ अन्य रेलवे में भी इन कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कर्मचारियों को वर्दी देने के बारे में प्रत्येक रेलवे के अपने वर्दी नियम हैं और वे काफी समय से लागू हैं ।

(ग) और (घ). अखिल भारतीय आधार पर रेलवे कर्मचारियों को वर्दी देने के बारे में एक समान नीति निर्धारित करने के लिये रेलवे मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गयी रेलवे वर्दी समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

रविवार को और छुट्टी वाले दिन कोयले का लदान

†२३००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को एक पत्र में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के फैडरेशन ने इस आरोप का खण्डन किया है कि रविवार को और अन्य छुट्टी वाले दिनों में कोयला लादने के लिये उद्योगों द्वारा माल-डिब्बों का पूरा इस्तैमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उन दिनों में माल लादने में होने वाली कुछ कठिनाइयां बतायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो छुट्टी वाले दिनों में उपलब्ध वैगन लदान क्षमता कितनी है ; और

(ग) इसका किस हद तक इस्तैमाल नहीं किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे बोर्ड को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल फैडरेशन का एक पत्र प्राप्त हुआ है। फैडरेशन ने इस आरोप का खण्डन नहीं किया है कि रविवार को और छुट्टी वाले दिन कोयला लादने के लिये उद्योगों द्वारा वैगनों का इस्तैमाल न करने के कारण परिवहन क्षमता बेकार जाती है। फैडरेशन ने केवल इन दिनों लदान में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है । फैडरेशन ने यह भी बताया है कि बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में अप्रैल, ६२ के महीनों में रविवार को और छुट्टी वाले दिन पूरा लदान हुआ है, इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया कि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में रविवार को और छुट्टी वाले दिन उपलब्ध औसतन दैनिक लदान क्षमता ६१२७ रही ।

(ग) सब कोयला खानों को इकट्ठा मान कर, अप्रैल, १९६१ से मार्च, १९६२ के दौरान, प्रति छुट्टी वाले दिन लगभग ८०० माल डिब्बों का इस्तैमाल नहीं किया गया । उस वर्ष सभी रविवारों और छुट्टियों को मिला कर, यह लगभग प्रतिवर्ष १० लाख टन कोयला होता है ।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

†२३०१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की ऐसी कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनायें हैं जो परियोजना के ब्यौरों समेत केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिये लम्बित हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनाओं को स्वीकार तथा अस्वीकार कर दिया है :

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत सरकार के लिए निम्न १२ सिंचाई और २ विद्युत् योजनायें लम्बित हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई योजनायें

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत (रुपये लाखों में)
	द्वितीय परियोजना की योजनायें	
१.	वराह जलाराम	३४.७६
२.	ताण्डव जलाराम	११५.००
३.	कल्याणी जलाराम	५०.००
४.	नल्लावार	२५.००
५.	सुद्दावागू	५९.००
६.	स्वराभिखी वामतर नहर	२५:००
	तृतीय परियोजना की योजना	
७.	वंशधारा/तथा अथवा पोचमपाद	१३६०.००
८.	वोहिगेडा	१४८१.००
९.	लंकासागर	७७.२०
१०.	पंपा जलाराम	३०.९३
११.	वरराजस्वामी गुडी	३१.४२
१२.	कोट्टिपल्लिवानू	१८.००
	विद्युत् योजनायें	
१.	श्री सैलम -व- नागारजुनसागर	
२.	अपर सिलेरू क्रम २	

(ख) (१) सिंचाई योजनायें

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई २४ योजनाओं में से १२ योजनायें योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। अब तक एक भी योजना अस्वीकार नहीं की गई है।

(२) विद्युत् योजनायें

योजनायें स्वीकृत—छः। यह निम्न हैं :—

१. तुंगभद्रा—नैल्लोर जल-विद्युत् योजना
२. अपर सिलेरू क्रम १
३. तेलंगाना जल-विद्युत् योजना
४. रामागुदम तापीय केन्द्र विस्तार
५. कोठागुडम तापीय केन्द्र
६. पारेषण तथा वितरण योजना

योजनायें अस्वीकृत—कोई नहीं।

केरल में कुष्ठ

†२३०२. **श्री वारियर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुष्ठ तथा इससे सम्बद्ध रोगों की जांच के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) और (ख). जी हां । कुष्ठ की जांच के लिये केरल में सर्वेक्षण किया जा रहा है । अभी तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है । राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या उन्होंने कोई सर्वेक्षण तो नहीं किया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की गई है । जानकारी मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिटी रेलवे बुकिंग आफिस

†२३०३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिटी रेलवे बुकिंग आफिसों को बुकिंग के ५ दिन पूर्व रेलवे स्टेशनों को रिजर्वेशन चार्ट भेजने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जो लोग अपनी सीटें पांचवें दिन अन्यथा उससे पहले बुक करना चाहें वह इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरानी पद्धति को चालू करने का है जिससे सिटी बुकिंग आफिस नवें दिन अपनी सीटें बुक कर सके तथा रेलवे स्टेशन को नवें दिन भेज सकें ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२३०४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : पंजाब सरकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति के लिए २८१.२६ लाख रुपये की अनुमानित लागत की निम्न १८ बाढ़ नियन्त्रण योजनायें मिली हैं । इन योजनाओं के अग्रेतर ब्यौरे राज्य सरकार से मंगाये गये हैं और योजना आयोग की स्वीकृति लेने से पहले इनकी प्रतीक्षा की जा रही है :

योजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
१. पहाड़ की तलहटी से मोहन गांव तक जानौरी वर्ग के चोकी नहर बनाना .	२४.०५
२. सिरवां नदी के द्वारा पटियाला की रौ तथा जनता देवी की रौ को सतलज नदी से मिलाना	७८.९१

†मूल अंग्रेजी में

योजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
३. डायलपुरा ट्रेन आर० डी० ०—८५, ००० आउटफाल ड्रेन आर० डी० ०—५२, ०००	१०.४८
४. बहादुर सिंह बाला नाली पद्धति	९.४८
५. बल्लियान नाली	५.६७
६. उरनाला कलां नाली	०.१०
७. संगरूल नाली का निर्माण	३.७४
८. लेहरा गग्गा नाली	३२.६१
९. मोहलगवाड़ा नाली	१.५६
१०. पूर्वी बैंक के दाहिने किनारे पर बाढ़ संरक्षण बांध	४.१२
११. मरीनिमेधा नाली का निर्माण	४.०१
१२. कजपूरा बांध पर २ नम्बर के स्टारों का निर्माण	१.८७
१३. रेलवे पुल २१८ तथा २३१ के बीच लिस्सारा नाले की सफाई	७.५६
१४. डोडा नाली आ० डी० ०—७०, ००० का निर्माण	५.३३
१५. करनाल डिवीजन में नये नाले की खुदाई	५.३४
१६. जी० टी० रोड तक ढिकासू बांध का विस्तार	०.८०
१७. सहायकों समेत गौंची मुख्य नाली	७७.०१
१८. कमालपुर से मालकपुर तक अग्रिम बांध का निर्माण	८.६२
जोड़	२८१.२६

पंजाब में पशुधन

†२३०५. **श्री दलजीत सिंह** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कौनसे जिलों में सबसे अधिक पशुधन है ; और

(ख) पशुओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९६१ की पशुओं की जनगणना के अनुसार पंजाब के फिरोज़पुर जिले में सबसे अधिक पशु (११.४४ लाख) हैं। उसके बाद कांगड़ा, संगरूर, करनाल, हिसार, भटिंडा, रोहतक, अम्बाला, अमृतसर, गुड़गांव तथा पटियाला का नम्बर आता है। पशुओं की किस्म के बारे में निम्न जिलों को क्रमेबार अच्छा समझा जाता है :--

रोहतक, हिसार, करनाल, पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर तथा अमृतसर।

(ख) समस्त देश में पशुओं के विकास के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित

†मूल अंग्रेजी में

मुख्य योजनायें बनाई गई हैं:—

(१) अखिल भारतीय मुख्य गांव योजना ।
(२) चुनीदा गौशालाओं के विकास की योजना ।
(३) गौसदनों की स्थापना की योजना ।
(४) जंगली तथा बेकार पशुओं को घेर कर रखने की योजना ।
(५) बेकार सांडों को बधिया बनाना ।
(६) चारा तथा भूसा विकास योजना ।
(७) दूध उत्पादन प्रतियोगिता ।
(८) चारे की फस्लों के उत्पादन की प्रतियोगिता ।
(९) अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास योजना ।
(१०) अखिल भारतीय सूअर पालन विकास योजना ।
(११) सांड पैदा करने वाले फार्मों की स्थापना की योजना ।
(१२) पशु राज्य पशुधन फार्मों का विस्तार ।
(१३) पर्वतीय पशुओं के विकास की योजना ।
(१४) सांडों के पुंसत्व परीक्षण तथा ग्राम पशुओं का क्रमवार सुधार योजना ।
(१५) रिंडर पेंस्ट उन्मूलन योजना ।
(१६) भेड़ विकास योजना ।
(१७) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन गवेषणा संस्था के उप-केन्द्र की स्थापना ।
(१८) इधर उधर जाने वाली भेड़ों के लिये लदान शिविर
(१९) मिश्रित फार्मिंग योजना ।
(२०) गांवों में नस्ल समितियां तथा दल पंजीयन का गठन ।
(२१) नस्ल के लिये अच्छे किस्म की जनन सामग्रियों का संरक्षण ।
(२२) पशु-पालन के लिये राज्य विभाग में विपणन विभाग की स्थापना ।
(२३) जंगली पशुओं की नस्ल बनाने वालों का पुनर्वास ।

अन्तिम योजना को छोड़ कर शेष सभी योजनायें पंजाब में लागू हैं / लागू होंगी । सरकारी पशु फार्म, हिसार के प्रवर्तक की विस्तृत योजना हाल में ही बनाई गई है ।

टेलीफोन के कनैक्शन

†२३०६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ तक पंजाब में सरकारी कार्यालयों तथा जनता में कितने टेलीफोन हैं ;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) (१) सरकारी कार्यालय में टेलीफोनों की संख्या ४,३९६ ।

(२) जनता के टेलीफोनों की संख्या १२,७३५ ।

(ख) और (ग). ब्यौरा परिशिष्ट क और ख में दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में गोदाम

†२३०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९६१-६२ में कितने गोदाम खोले गये और वर्ष १९६२-६३ में कितने खोले जायेंगे ; और

(ख) ये भण्डार किसानों को क्या सुविधायें देते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) केन्द्रीय भण्डार निगम ने वर्ष १९६१-६२ में पंजाब में अबोर, करनाल, मनसा, अमृतसर और सोनीपत में पांच गोदाम खोले और १९६२-६३ में दो और गोदाम खोलने का विचार है ।

(ख) ये गोदाम कृषि-उत्पाद को वैज्ञानिक ढंग से रखने और उसका परिरक्षण करने की सुविधायें देत हैं और उद्देश्य यह होता है कि किसान उसका अच्छा मूल्य पा सकें । गोदाम रसीद पर बैंकों से ऋण भी मिल सकता है ।

चंडीगढ़ स्टेशन का नव निर्माण

†२३०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चंडीगढ़ स्टेशन को फिर से बनाने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) फिर से बनाने का काम कब पूर्ण होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि मा० सदस्य चंडीगढ़ में यात्री यार्ड सुविधाओं को फिर से बनाने का उल्लेख कर रहे हैं । यदि यह बात है, तो काम लगभग आधा पूरा हो चुका है ।

(ख) दिसम्बर १९६२ तक ।

पंजाब में पानी की कमी

†२३०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कांगड़ा जिले को हमीरपुर तहसील और होशियारपुर जिले की ऊना तहसील के अधिकांश गांवों में पीने के जल की कमी बड़े पैमाने पर फैली हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण और स्वच्छता योजनाओं का विस्तार करने के लिये, इस मामल में क्या करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फीरोजपुर और दिल्ली डिवीजनों में तीसरी और कौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२३१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर रेलवे के फीरोजपुर और दिल्ली डिवीजनों के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टर बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) क्वार्टरों की संख्या और स्थान का निश्चय प्रतिवर्ष उपलब्ध राशि के आधार पर किया जाता है और इस कारण समूची तीसरी योजना अवधि सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कोसी नहर

२३११. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी के पूर्वी तटबन्ध के समानान्तर कोसी बैरेज से निकाली गई नहर जो सहरसा और पूर्णियां जिलों से गुजरती है उस से नहर और बांध के बीच कोपरिया (जिला मुंगेर) की कुल जमीन की सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जमीन का क्षेत्रफल क्या है ; और

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरी जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जाने की योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

झाबुआ जिले को मिलाने वाली रेलवे लाइन

२३१२. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झाबुआ जिले के किसी भाग को रेलवे लाइन छूती तक नहीं ;

(ख) क्या सरकार के पास तीसरी योजना में कोई ऐसी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिसका लाभ झाबुआ जिले को मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेलवे लाइनों का निर्माण अलग-अलग जिलों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्र-हित को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

झाबुआ जिले में सिंचाई और बिजली योजनायें

२३१३. **श्रीमती जमुना देवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस से यह पता चले कि झाबुआ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा बिजली उत्पादन की कितनी तथा कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : सिंचाई—मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई भी सिंचाई की नई स्कीम सम्मिलित नहीं है। फिर भी, सिंचाई की एक ऐसी स्कीम है, जोकि दूसरी योजना से चली आ रही है; इसका नाम पम्पावती टैंक है और यह झाबुआ जिले में है। स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :—

"पम्पावती टैंक" में पम्पावती नदी के ऊपर मिट्टी के एक बांध का निर्माण तथा झाबुआ जिले में ३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए एक नहर प्रणाली का निर्माण परिकल्पित है। इस पर १७.५० लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है। इस स्कीम के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में १३.५० लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। १९६१-६२ में प्रत्याशित व्यय ३.२५ लाख रुपये का था। १९६२-६३ के लिए ७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। परियोजना पर प्राथमिक कार्य १९५९-६० में हाथ में लिये गये थे। भारत सरकार के पास अब तक हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा नहीं है।

विद्युत्—झाबुआ जिले को तृतीय योजना में धार सब-स्टेशन से ३३ के० वी० लाईन द्वारा चम्बल बिजली देने का विचार है।

रेलों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन

†२३१४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड से जनरल मैनेजरों और आगे नीचे तक अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है ;

(ख) प्रत्यायोजन की तिथि क्या है ; और

(ग) इस प्रत्यायोजन के प्रभाव का मूल्यांकन क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७।]**

नागार्जुन सागर परियोजना

†२३१५. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लगभग पचास हजार रुपये की लागत के भारी मशीनी पुर्जे नागार्जुन सागर परियोजना के कारखाने के स्टोर से चुरा लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और इस मामले में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी हां, किन्तु चोरी किये गये माल का मूल्य केवल १८१८ रुपये है।

(ख) केटरपिलर ट्रैक्टरों के लिये तीन फ्यूल इंजैक्टर पम्प और डम्परों के सात इन्जैक्टर चोरी हुए हैं। इस मामले में दो कार्यकर्ता अन्तर्ग्रस्त थे। एक क्षेत्रीय सहायक और एक पर्यवेक्षक पर भी सन्देह किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुलिस ने दो कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय सहायक तथा पर्यवेक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पर्यवेक्षक को जमानत पर छोड़ दिया गया है और उस को मुअत्तल कर दिया गया है। अन्य दो कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय सहायक को भी जो वर्कचार्ज कर्मचारी थे, जमानत पर छोड़ दिया गया है, किन्तु उन को काम पर नहीं रखा गया है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३४/६०—ट्रान्सपोर्ट।

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/५४/६१—ट्रान्सपोर्ट।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५५/६२]

भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति) नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा ३२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६९९ में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा परिषद् (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५६/६२]

उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५६ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५७/६२]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

समितियों के लिये चुनाव

भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत की क्षय रोग संस्था नियमों और विनियमों के खंड ३ (७) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत की क्षय रोग संस्था नियमों और विनियमों के खंड ३ (७) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि (अब खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के आज तक संशोधित दिनांक ८ नवम्बर, १९४८ के संकल्प संख्या एफ-१६-७२/४७—नीति के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष तक काम करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि (अब खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय के आज तक संशोधित दिनांक ८ नवम्बर, १९४८ के संकल्प संख्या एफ० १६-७२/४७—नीति के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष तक काम करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : मैं कल कह रहा था कि हमारी सेनाओं का साहस कायम है। हमें उन्हें हर प्रकार से सुसज्जित करना चाहिये। यह भी पता चला है कि हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

सरकार के पास विरोध पत्र आये हैं कि हम रूस से विमान खरीद रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में हम पूर्णरूप से स्वतन्त्र हैं और किसी भी राष्ट्र को हम पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिये। और एक बात यह भी है कि हम केवल एम० आई० जी० विमान खरीदना ही नहीं चाहते प्रत्युत यह भी चाहते हैं कि रूस के सहयोग से उनका उत्पादन भी स्वयं इस देश में आरंभ किया जाये। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि एम० आई० जी० विमान उन विमानों की अपेक्षा कहीं सस्ते हैं जिनका प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमरीका ने रखा है सामान्यतः मूल्यों में एक और चार का अन्तर है। इसके अतिरिक्त यदि हम एम० आई० जी विमान लेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा मे काफी बचत होगी। परन्तु अमरीका से सैनिक विमान खरीदने पर हमें उनका निरीक्षण करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञ भी बुलाने पड़ेंगे जिन पर ८००० रुपये प्रति मास का खर्च भी होगा।

अमेरिका को यह बात समझ लेनी चाहिये कि भारत सशर्त किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहता। हमें इस बात का खेद है कि उस देश ने अभी तक पाकिस्तान को काश्मीर का अधिकृत क्षेत्र खाली करने के लिए परामर्श नहीं दिया। वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि उसने पाकिस्तान को उसके इरादों के सम्बन्ध में बढ़ावा दिया है। भारत पर इसका बहुत कुप्रभाव हुआ है।

भारत इस बात का पूरा विरोध करेगा कि उसको दी जाने वाली सहायता का सम्बन्ध प्रतिरक्षा नीतियों से जोड़ा जाय। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भारत को चीन की ओर से कोई खतरा नहीं है। उसकी हाल की गतिविधियों से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी है कि उसके इरादे हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हैं। हमें आशा करनी चाहिये कि यदि उसने कोई आक्रमण किया तो हम आक्रमणकारियों को पराजित करने में सफल होंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में श्रम सम्बन्धी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, सभी दिशाओं से सम्बद्ध प्राधिकारी और कर्मचारी परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अच्छी बात यह की गई है कि मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है। मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के परिणाम-स्वरूप पर्यवेक्षक कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी बड़े हर्ष की बात है कि आयुध कारखानों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है १९५६-५७ में इन कारखानों में १४ करोड़ रुपये का माल बना परन्तु चालू वर्ष में ४० करोड़ का माल बना। आने वाले वर्ष में उस में १० करोड़ रुपये की वृद्धि और हो जायेगी। आन्तरिक साधनों से खरीद भी दो गुणी हो गयी है। एक अन्य बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेखा परीक्षण प्रति-वेदनों मे अनावश्यक व्यय के छोटे मोटे मामलों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को इसके ठीक रूप में लिया जाना चाहिये। अन्त में मैं पुनः अपनी सेनाओं को उनके साहस के लिए मुबारकबाद देता हूं।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : मैं न युद्ध का प्रचार ही करता हूं और न ही सरकार से यह ही कहना चाहता हूं कि वह युद्ध की घोषणा कर दे। मेरा निवेदन यह है कि आज यह प्रतीत हो रहा है कि हम अपने अतिक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात की जरूरत है कि हम अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित और सुसज्जित करें और इस दिशा में शीघ्रता से पग उठाया जाना चाहिये। हमें इस बात का पता होना चाहिये कि हमारे दो बड़े कट्टर शत्रु देश हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक पश्चिम की ओर है और एक उत्तर की ओर। यह तो स्पष्ट ही है कि हम उन से लड़ तब ही सकते हैं जब कि हमारे पास अच्छे उपकरण और शस्त्र हों। अतः इन सब चीजों के लिए प्रतिरक्षा के लिए अधिक धन आवण्टित किया जाना चाहिये ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके।

एक बात हमको स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि यदि हम अपनी सीमाओं के प्रति उदासीन हो जायेंगे और उनकी चौकसी करने में असफल रहेंगे तो देश के विकास पर व्यय किये करोड़ों रुपये व्यर्थ हो जायेंगे। अत : मेरा कहना है कि प्रतिरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बड़े खेद की बात है कि हमारी गलत विदेश नीति ने हमारे लिए अनेक प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं? यह बात भी सर्वविदित है कि चीन की जन शक्ति और सेना बहुत बड़ी है। और सेना सुसज्जित भी है? इसके अतिरिक्त उनके पास आण्विक शस्त्र भी हैं।

मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर हमारी सरकार क्यों आण्विक शस्त्र प्राप्त करने में संकोच कर रही है। हमें यह समझना चाहिये कि आण्विक शस्त्र होने से ही आक्रमण करने वाले पर निरोधक प्रभाव होगा। अतः हमें आण्विक शस्त्र प्राप्त करने चाहियें। जो हमारे पुराने शस्त्र हैं उनमें भी हमें अपेक्षित सुधार करना चाहिये। जवानों को ३०३ रायफलों के स्थान पर हल्की स्वचालित राइफलें दी जानी चाहियें। उनको इन्फैन्ट्री मार्टर्स भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात उपकरण 'इन्फ्रा-रे' उपकरण है जिससे रात को काम करने में सुविधा हो सकती है। हमें नेफा, आसाम तथा अन्य सीमान्त क्षेत्रों में उद्योगों के विकास करने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन राज्यों में समुचित सड़कों इत्यादि को बना कर संचार साधनों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह भी बड़े महत्व की बात है।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोडिया) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। उनके काल में हमारे प्रतिरक्षा बलों ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री की कड़ी से कड़ी आलोचना होती रहती है परन्तु वह जब भी बोलते हैं तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। वह किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करते।

कई लोग उन पर साम्यवादी होने का आरोप लगाते हैं वे गलत हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अनेक अच्छे कार्य किये हैं। प्रतिरक्षा मंत्री की आलोचना गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाती है, क्योंकि वे उनसे नाराज है। वह इस लिए कि प्रतिरक्षा संगठनों ने सस्ती चीज़ों का उत्पादन किया है।

जो माननीय सदस्य हमारे प्रतिरक्षा मंत्री की आलोचना करते हैं, उन में प्रधान मंत्री की आलोचना करने का साहस नहीं। वे सरकार की नीति की आलोचना नहीं करते हैं। वे हमारी नीति, सुरक्षा नीति इत्यादि को स्वीकार करते हैं। योजनाओं और सरकार के सब कामों को मानते हैं। परन्तु इस सरकार या प्रधान मंत्री को कमज़ोर बनाने के लिये इस मंत्री या उस मंत्री की आलोचना करते हैं। सुरक्षा मंत्री ने सुरक्षा मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशीय क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। गोलाबारूद के कारखानों की क्षमता बढ़ाने में भी अच्छा काम किया है। उन्होंने असैनिक और सैनिक महत्व का सामान बहुत सस्ता बनवाया है। इसीलिए गैर सरकारी क्षेत्र वाले उन से नाराज़ हैं। इस लिए हमें अपने सुरक्षा मंत्री को गलत नहीं समझना चाहिए।

आण्विक हथियारों के संबंध में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हम न आण्विक हथियार बनाएंगे और न रखेंगे। हम तो अन्य देशों को ये हथियार नाश कर देने के लिए कहते हैं इसलिए हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं के पास आण्विक हथियार नहीं होने चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, परन्तु सेना में 'सिख रैजीमैंट', 'मरहटा रैजीमैंट' या 'मोहार रैजीमैंट' इत्यादी नामों का प्रयोग होता है। इसे बन्द कर देना चाहिये। ये नाम तो अंग्रेजों ने बनाए थे। अब हम स्वतन्त्र हैं ? हमें इन नामों को बन्द कर देना चाहिए।

हमारे देश में राजनीतिज्ञों को प्रतिरक्षा सेनाओं में राजनीति नहीं लानी चाहिए। इन शब्दों से मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस समय जब सदन देश की सुरक्षा, प्रतिरक्षा और देश की एकता के संरक्षण के लिए तरीके बना रहा है, मैं यदि अपने कटौती प्रस्ताव संख्या २५, २८ और ५२ को प्रस्तुत करूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : कल कहा गया था कि जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे सभा पटल पर १५ मिनट में उनकी संख्या बता दें।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: उस समय मैं आप के साथ आप के कमरे में था।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो मैं उन्हें विशेष अवसर देता हूं ? वही श्री सरजू पाण्डेय को भी देना पड़ेगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताविक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८	५	श्री हरिविष्णु कामत	भारत की भूमि सीमाओं की अच्छी तरह से रक्षा और भारत की अनुल्लंघनीय प्रादेशिक अखणडता के संरक्षण में असफलता	राशि घटा कर १रु० कर दी जाये।
८	२८	श्री हरि विष्णु कामत	राष्ट्र को खतरे से अवगत और सुरक्षा के लिए त्यार करने में असफलता	१०० रुपये
११४	५२	श्री हरि विष्णु कामत	फजूल व्यय के नियंत्रण और उसे हटाने में असफलता	१,००,००,००० रुपये
८	६८	श्री सरजू पाण्डेय	जवान और पदाधिकारी के वेतनक्रम के बीच में वर्तमान महान अन्तर को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
८	६९	श्री सरजू पाण्डेय	भर्ती के समय पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रथा को हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७०	श्री सरजू पाण्डेय	योजना में दिए गए विकास कार्यक्रमों में सेना और वायुसेना के सहयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७१	श्री सरजू पाण्डेय	सैनिकों के वेतन में पांच वर्ष बाद वृद्धि के स्थान पर एक वर्ष बाद वृद्धि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७२	श्री सरजू पाण्डेय	सेना से युक्त होने के बाद असैनिक नौकरी देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७३	श्री सरजू पाण्डेय	गोला बारूद कारखानों में असैनिकों के प्रयोग के लिए वस्तुएं बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८	७४	श्री सरजू पाण्डेय	जवानों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सदन के समाने हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरा लक्ष्य गल्त नहीं समझना चाहिए। मैं मंत्री महोदय, मंत्रालय और सेना के हाथों को और दृढ़ करना चाहता हूं ताकि पाकिस्तान और चीन अतिक्रमकों को देश से निकाल दिया जाए। मैं प्रतिरक्षा मंत्री को आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी सहायता उन्हें उपलब्ध होगी यदि सरकार कमज़ोरी से काम न ले।

अमेरिका के साथ पाकिस्तान का सैनिक समझौता होने के कारण पाकिस्तान की वायुसेना शक्ति बढ़ गई है। हमें भी जहां से भी अच्छी शर्तों पर वैसे शक्तिशाली विमान मिल सकते हैं ले लेने चाहिएं। रूसी एम० आई० जी० जेट जहाज़ खरीदने के बारे में जो इतना प्रचार किया है वह मुझे पसन्द नहीं। कोई भी देश इस सम्बन्ध में हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे प्रतिरक्षा मंत्रालय के काम के ढंग का कुछ पता नहीं चलता। जब भी हमें कोई जानकारी की आवश्यकता होती है तो राष्ट्र हित या सुरक्षा की आड़ ली जाती है।

एम० आई० जी० के मामले में मंत्रालय में बहुत कुछ हो रहा है। क्या मंत्रालय में यह कार्य करने के लिए कोई व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्त में मामला प्रतिरक्षा उप समिति या मंत्रिमंडल की समिति को जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा उपसमिति काम कर रही है या नहीं ? यदि हां, तो उसके क्या उत्तरदायित्व और शक्तियां हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इन मामलों के लिये मंत्रिमडल की प्रतिरक्षा समिति मंत्रिमंडल ही है और हमारे संविधान के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुछ स्वीकृति आवश्यक होती है और हम वे हमेशा लेते हैं ।

मैं माननीय सदस्य को रोकना तो नहीं चाहता, परन्तु मैंने इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि यह ऐसा तथ्य है जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य सदन और संसार को अचेतनतया गल्त रास्ते पर न डाल दें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जो प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है, मैंने नहीं सुना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिरक्षा समिति मत्रिमंडल है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति की यह संवैधानिक स्थिति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्रिमंडल की कोई समिति थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसे मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति कहते हैं । मंत्रिमंडल को भेजे गये सब मामले मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति को जाते हैं । बहुत से देशों में साधारण तया ऐसी प्रथा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं, प्रतिरक्षा का सामान खरीदने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, यह जानना चाहता हूं । क्या इससे सम्बन्धित मामले समिति के पास जाते हैं या तीन इकट्ठे सेनापतियों के पास जाते हैं और अन्त में प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री या समिति निर्णय करती है ।

पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने की शक्ति हमारे में है, परन्तु जहां तक चीनी आक्रमणकारियों का सम्बन्ध है इस बारे में पूरे निश्चय से नहीं कहा जा सकता ।

जब चीनियों ने १९५० में तिब्बत पर आक्रमण किया था तो उनकी अधिकांश सेनाओं ने अकसाई चिन क्षेत्र में होकर प्रयाण किया था और उनके जनरलों को कलकत्ता से कालिम्पोंग और वहां से ल्हासा जाने दिया था । इस प्रकार चीनियों ने अपने इरादों को काफी पहले स्पष्ट कर दिया था । यह सुन कर आश्चर्य होता है कि चीन से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है ।

कालिम्पोंग में चीनी व्यापार अभिकरण के बन्द किये जाने का हम स्वागत करते हैं । वास्तव में यह जासूसी का अड्डा था । सरकार को यह अभिकरण बहुत पहले ही बन्द कर देना चाहिए था ।

चीनी अतिक्रमण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें युद्ध का प्रचार करने वाले कहा गया । हम में से कोई भी चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता है । सैनिक कार्यवाही भी कोई नहीं चाहता । परन्तु और कुछ कदम तो उठाये जाने चाहिएं ।

हमारे देश में चीन के अतिक्रमण के बारे में भारतीय भाषाओं में प्रचार नहीं होता है । चीन एक बड़ा देश है । उसकी बड़ी सेना है । परन्तु सब से बड़ा खतरा यह है कि चीनी नेता अपने देश में युद्ध न रोके जाने के सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं । हमारे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि चीन से कोई खतरा नहीं है ।

नौसेना में अभी जो तरक्की हुई है वह तरक्की के नियमों के विरुद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां पर उसका जिक्र नहीं करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने कोई नाम तो नहीं लिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु वे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में तो कह रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इन बातों पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । व्यक्ति विशेष के बारे में यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती और सम्बन्धित पदाधिकारियों के गुणों और अवगुणों का भी जिक्र नहीं हो सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो मैं माननीय मंत्री से केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या नौसेना में तरक्की के लिए निर्धारित नियमों का हाल के मामले में पालन किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम यहां इनकी चर्चा नहीं कर सकते ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)**: चूंकि यह बात मान ली है कि पदाधिकारियों के गुणों और अवगुणों पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए और चूंकि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एक रियर ऐडमीरल को तरक्की के मामले में छोड़ दिया गया। इसलिये उन्होंने व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, तो इसे वाद-विवाद में से हटा दिया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं साधारणतया किसी चीज को वादविवाद में से हटाने के हक में नहीं हूं । भविष्य के लोगों को पता लगना चाहिए कि ऐसी बात करना उचित नहीं था । अध्यक्ष ने जो कहा वह भी तो होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सदन को बताना चाहिए कि इस मामले में नियमों का पालन किया गया है । पिछले वर्ष भी एक ऐसा मामला उठाया गया था ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय सदस्यों ने नियमों के भागों का उल्लेख किया जो उनके लिये समय समय पर सुविधाजनक होते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : गेहूं की चोकर के सौदे का प्रश्न श्री द्विवेदी ने दो तीन सप्ताह पहले उठाया था, लेकिन उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था । सरकार आटा मिलों को १४ रु०प्रति मन के भाव पर चोकर का संभरण करती है, जब कि बाजार में आटा, जिससे चोकर निकलती है, ७ या ७ १/२ रुपये प्रति मन के भाव से मिलता हैं । खाद्य मंत्रालय का सेना क्रय संगठन योकर के लिए १२ से १३ १/२ रुपये प्रति मन तक देता है । इस प्रकार प्रति टन पर करदाता और राजकोष को १०० रुपये का नुकसान होता है । प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

मैंने उस दिन श्री विस्टन चर्चिल का नाम इसलिये नहीं लिया था कि मैं उनकी नीति से सहमत हूं, बल्कि इसलिये कि अंग्रेजी भाषा की गद्य शैली पर उनका बड़ा अधिकार है । सैनिक तौर पर हमारा देश कितना तैयार है, उसके लिये जनता को कितना तैयार किया गया है—इसके बारे में मैं आपका ध्यान महात्मा गांधी के विचारों की ओर आकर्षित करता हूं । महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चुनना पड़े, तो मैं हिंसा को ही चुनूंगा । डाकुओं और आक्रमणकारी देशों के प्रति हिंसा की नीति न अपनाने की वकालत उन्होंने नहीं की थी ।

हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीका में कहा था कि स्वतंत्रता पर आंच आने पर या आक्रमण होने पर हम तटस्थ नहीं रहेंगे । आशा है कि आक्रमण की परिभाषा में चीन के आक्रमणको भी शामिल किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

आशा है कि सरकार चीन और पाकिस्तान के भावी आक्रमणों का सामना करने के लिये सैनिक और राजनयिक कार्यवाही करेगी। उनको भी पुर्तगालियों की भांति भारत भूमि से निकाल दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले भी कह चुका हूं कि सभा में व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। नहीं तो बाहर के लोग अपने बारे में संसद् सदस्यों पर प्रभाव डालने की कोशिशें करने लगेंगे। सरकारी कर्मचारियों की इससे हानि ही होगी। इसलिये ऐसे उल्लेख नहीं किये जाने चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या हम पदोन्नतियों सम्बन्धी नियमों का हवाला भी नहीं दे सकते ? क्या यह नहीं पूछ सकते कि उनका पालन किया जा रहा है, या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों की बात दूसरी है।

†**श्री खाडिलकर**(खेड): देश की प्रतिरक्षा की सुदृढ़ता की दृष्टि से यह अनुचित है कि बार-बार प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में ऐसी बहसें की जायें। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री बड़ी संजीदगी और ईमानदारी से प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं।

श्री कामत ने प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में कुछ पदोन्नतियों का प्रश्न उठाया था, कल वही प्रश्न एक कम्युनिस्ट सदस्य ने उठाया था। श्री तिम्मय्या के त्यागपत्र का मामला भी इसी तरह सभा में उठाया गया था। व्यक्तिगत सेनाधिकारियों के बारे में ऐसे प्रश्न उठाने से देश में लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा हो जायेगा। प्रश्न उठाना दूसरी बात है और उसके सम्बन्ध में सूचना मांगना—बिल्कुल दूसरी। सूचना मांगी जा सकती है। प्रधान मंत्री को भी लिख कर पूछा जा सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने प्रतिरक्षा मंत्री को लिखा था, पर उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया।

†**श्री खाडिलकर** : आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बार-बार पदोन्नतियों के प्रश्न को लेकर प्रादेशिकता के आधार पर ऐसी आपत्तियां करना और चर्चायें शुरू करना देश की प्रतिरक्षा के हित में नहीं होगा।

यदि किसी के प्रति कोई थोड़ा-बहुत अन्याय भी हुआ हो, उस पर दूसरी तरह की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले को लेकर कुछ संसद्-सदस्य प्रधान मंत्री के पास संसद-सदस्यों के हस्ताक्षर से एक प्रतिनिधान भेजना चाहते थे। मैंने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। और अब यदि आप उस मामले का ब्योरा देखें तो 'अमृत बाजार पत्रिका' में उसके सम्बन्ध में जुटाई गई सारी जानकारी और कल जिस पत्र का उद्धरण दिया गया था, वह सभी नितान्त निराधार है।

मैं तो समझता हूं कि कांगो के मामले में पहलकदमी के लिये प्रतिरक्षा मंत्री हमारी बधाई के पात्र हैं। कांगो में दो शक्तिशाली राष्ट्रों की गुटबाजी के कारण संयुक्त राष्ट्र की कमान की प्रतिष्ठा

---

†मूल अंग्रेजी में

धूल में मिली जा रही थी। लेकिन प्रतिरक्षा मंत्री ने उसे बचा लिया है। कांगो ही नहीं, हमें विश्व-शान्ति और व्यवस्था की रक्षा में योग देने के लिये संसार भर में सम्मान मिला है, और मिलेगा।

अब अफ्रीकी कबीलों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कामीना में एक शिविर खोला जा रहा है। सुना है भारत से भी उसके लिये सहायता मांगी गई है। मेरा अनुरोध है कि भारत को अवश्य ही अपने अधिकारी वहां भेजने चाहियें।

'मिग' विमानों की खरीद के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि सोवियत संघ से 'मिग' विमानों की खरीद करके हम अपने देश को पश्चिमी देशों के गुट के प्रभाव से मुक्ति दिलाने की दिशा में पहला क़दम उठा रहे हैं। इसलिये कि अभी तक शास्त्रास्त्र के मामले में हम पश्चिमी देशों पर ही निर्भर करते हैं। इससे मुक्ति पा लेने पर ही हम वास्तविक अर्थों में तटस्थ और स्वतंत्र कहला सकेंगे।

शक्ति पर आधारित गुटों के इस संसार में, भारत को अपनी प्रतिरक्षा का पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। हम शस्त्रों को तभी तिलांजलि दे सकते हैं, जब दोनों गुटों के देश भारत की प्रादेशिक प्रभुता की गारंटी करने के लिये तैयार हो जायें। हमें विवश होकर 'मिग' विमान खरीदने ही पड़ेंगे।

हमें साथ ही अपने प्रतिरक्षा-उत्पादन का आधार अधिक व्यापक बनाना चाहिये। सेना और शस्त्रास्त्र के बारे में हमें आत्म-निर्भर बनना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सेना के उत्पादन और युद्ध में भाग लेने वाले विभागों को एक दूसरे से अलग रखा जाये। तब हमें ठीक-ठीक पता चलेगा कि वास्तव में युद्ध में भाग लेने वाले विभागों पर कितना व्यय होता है।

हमारे देश में होता यह है कि लेखा-परीक्षा करने वाली समितियों के सदस्यों के सामने विकास सम्बंधी बुनियादी नीतियों का पूरा महत्व नहीं रहता। इसीलिये वे अक्सर अनुसंधान-कार्य पर होने वाले व्यय को अनुत्पादक बता देते हैं। प्रतिरक्षात्मक उत्पादन के सम्बंध में ऐसी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है।

हमारे यहां हाल में कुछ सैनिक स्कूल चालू किये गये हैं। पाश्चात्य देशों की भांति, हमें अपनी सेना में उच्च-वर्ग से आये उम्मीदवारों का प्रधान्य स्थापित नहीं होने देना चाहिये। हमें सभी वर्गों, यहां तक कि आदिम जातियों से भी, उम्मीदवार लेने चाहियें। प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस दिशा में सतर्क रहना चाहिये।

अब गोआ स्वतंत्र हो गया है, और वहां एक बड़ा अच्छा बन्दरगाह भी है। इसलिये वहां के नौसैनिक संस्थान का काफी विस्तार किया जाना चाहिये। नौसेना को सुदृढ़ बनाने की हमारी आवश्यकता फौरी है।

संसद् में प्रतिरक्षा सम्बंधी मामलों पर अधिक विस्तृत और ब्यौरेवार चर्चा नहीं की जा सकती और अब हमारी प्रतिरक्षा का उत्पादन विभाग अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। इसलिये संसद् सदस्यों की स्थायी समिति बना देनी चाहिये, जो प्रतिरक्षा सम्बंधी मामलों पर गोपनीयता के साथ चर्चा कर सके। अन्य देशों में ऐसी प्रथा मौजूद है।

हमें प्रतिरक्षा मंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिये।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव) : पिछले १४-१५ वर्षों में इतनी उथलपुथल हुई, फिर भी हमारी सेना देश के प्रति वफ़ादार रही है। जब कि एशिया के कई देशों में सेना राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी है।

लेकिन बहुत अधिक वफादारी कभी-कभी उल्टी भी पड़ती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सेना में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के आधार पर कुछ विभाजन हैं। लेकिन व्यवहार में हमारी सेना में समस्त भारत के लोग पूर्ण सहयोग से काम कर रहे हैं। वहां भाषा की समस्या का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता।

हमें अब अपनी सेना की ओर देश के सर्वोत्तम टेकनीशियनों को आकृष्ट करने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिये कि अब समय बिल्कुल बदल चुका है। सेना में सेवा की शर्तें ऐसी होनी चाहिये कि टेकनीशियन लोग सेना की ओर आकर्षित हों। वेतन-क्रमों, इत्यादि के प्रश्नों पर सेना में असंतोष पैदा नहीं होने देना चाहिये। टेकनीशियनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

हमारे देश की सीमायें बहुत विस्तृत हैं, उनकी समुचित सुरक्षा होनी चाहिये। अमरीका और कुछ अन्य शक्तिशाली पाश्चात्य देशों ने पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्रों से बिलकुल लैस कर दिया है। चीन भी पूरी तरह लैस हो गया है। इससे हमारी प्रतिरक्षा के लिये एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है।

आज के जमाने में देश की वास्तविक प्रतिरक्षा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में निहित रहती है। दो ही मार्ग हैं, या तो कोई शक्तिशाली गुट हमारे देश की पीठ पर हाथ रखे या फिर हमारे देश के प्रति संसार के अन्य देशों की इतनी अधिक सद्भावना हो कि कोई हाथ न उठा सके। इसलिये बड़ी सावधानी की जरूरत है।

हम किसी भी गुट में मिलना नहीं चाहते। और पाकिस्तान को एक ओर जहां अमरीका का बल है, दूसरी ओर चीन की पीठ पर कम्युनिस्ट गुट के देशों का हाथ है। तब हमें किसका सहारा रह जाता है ?

सबसे बड़ी प्रतिरक्षा तो आत्मविश्वास है। हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को पूर्णतया प्रशिक्षित बनाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव है कि हमें कम्युनिस्ट देशों की तरफ झुकना चाहिये। लेकिन क्या चीन के साथ युद्ध ठनने पर भी वे कम्युनिस्ट देश हमारी सहायता करेंगे ? और क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध ठनने पर पाश्चात्य देश हमारी सहायता करेंगे ? उसके लिये हमें देश की जनता में प्रतिरक्षा की एक अदम्य इच्छा पैदा करनी चाहिये। वही सर्वोत्तम प्रतिरक्षा होगी।

लेकिन हम तो अपने आपको हिन्दुस्तानी कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। सब से पहली आवश्यकता तो यही है कि हम अपने आपको हिन्दुस्तानी महसूस करें और उस पर गर्व करें। आंतरिक इच्छा-शक्ति के बिना, अकेली सेना देश की रक्षा नहीं कर सकती। यदि हम अपने देश में उचित वातावरण पैदा कर सकें और देशवासियों में एक उत्साह पैदा कर सकें, तो हमारी सेना संसार में सर्वोत्तम सिद्ध हो सकती है। यही हमारा सबसे बड़ा और कारगर शस्त्र होगा।

हमारी सेना में जातियों या प्रदेशों के आधार पर कोई विभाजन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें अपनी सेना के उत्पादन-विभाग को और अधिक विकसित और विस्तृत बनाना चाहिये। उनको उच्च प्राविधिक शिक्षा के लिये विदेशों में भेजना चाहिये। उत्पादन बढ़ा कर वह जनता की भी सेवा करेगी।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सन्मुख ऋग्वेद के दो मंत्र रखना चाहता हूं, जो कि सामरिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं :—

मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ तनुध्वं नावमरित्रपरणीं कृणुध्वम् ।

इष्कृणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राइचं यज्ञं प्रणयता सखायः ।।

राष्ट्र के नेताओं को वेद का उपदेश है कि हमारे राष्ट्र-नायक मित्रता-युक्त, एक समान ज्ञान वाले हों। वे ओजस्वी सत्य और हितकर भाषण करें, ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करें, यातायात और युद्ध के लिए भी सुन्दर और मजबूत जल-पोत बनायें। वे शत्रु से राष्ट्र की रक्षा का पूरा प्रबन्ध रखें। प्रत्येक मनुष्य भी अपनी आत्मरक्षा के साधनों से युक्त रहे। दृढ़ शस्त्रास्त्र तैयार रखें, जिस से समयानुसार शत्रु से देश की रक्षा की जा सके एवं शासन की सुव्यवस्था रह सके। वे धन, बल, विद्या, विज्ञानादि द्वारा देश को आगे बढ़ायें, कृषि और वाणिज्य द्वारा अन्न की वृद्धि करें यज्ञ आदि सत्कर्मों से देश में वृद्धि करें एवं सब प्रकार से प्रजा का पालन करें।'

एक दूसरे मंत्र में इस भाव को और बलपूर्वक प्रकट किया गया है :—

स्थिरा वः सन्त्वायुधः पराणुदे वीलू उत प्रतिष्कमे ।

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ।।

वेद का देश के शासकों को उपदेश है कि तुम्हारे आग्नेय-अस्त्र-शस्त्र आक्रमण-कारी शत्रुओं को पराजित करने और उन से स्वराष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रशंसित और दृढ़ हों। सेना विशाल तथा प्रशंसनीय होवे, जिस से तुम सदा विजयी रहो। हम अन्यायी, दुराचारी शत्रु पुरुषों की शक्ति को कदापि न बढ़ने दें। इस प्रकार अन्यायकारियों के बल की हानि तथा न्याय-कारियों के बल की उन्नति में वृद्धि होवे।

इस मंत्रालय की मांग पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हुं कि जैसा कि हमारे वेद ने प्रकट किया है कि जो आक्रान्ता है, जो दूसरे देश हमारे राष्ट्र पर कुदृष्टि रखते हैं, उन से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए दृढ़तर कदम उठाए जाने चाहिए।

आज सारे संसार में यौद्धिक अशान्ति प्रतीत होती है और लड़ाई के बादल छाए हुए हैं। संसार में शान्ति कायम रखने के लिए हमारे देश ने जो प्रयत्न किये हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं और उन को सारा संसार जानता है। किसी विद्वान ने कहा है कि "पीस हैज़ मोर विक्टरी दैन वार"। भारत ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से ज़ाहिर कर दिया है कि उसका संसार की शान्ति में विश्वास है। यद्यपि हमारे चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, हमारे पड़ौसी देशों, चीन और पाकिस्तान, से हमें खतरा पैदा हो गया है, फिर भी हमारा देश संसार में शान्ति बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है।

आज हम देखते हैं कि आक्रांता चीन और भारत-विद्वेषी पाकिस्तान की आक्रमणकारी अनीतियों के कारण देश के सामने एक बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। यदि हम ने उस का सामना करना है, तो हमें अपनी रक्षा-नीति और रक्षा-व्यवस्था को बलशाली और दृढ़तर बनाना होगा

[श्री बाल्मीकी]

और उस में एक भारी परिवर्तन करना होगा। इस बीच में इस मंत्रालय के द्वारा देश की रक्षा के लिये जो भी कार्य किये गये हैं, वे प्रशंसनीय हैं। चीन तथा पाकिस्तान हर प्रकार से हमारे देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, इस बात को देश का जन-जन और सारा संसार जानता है। इसलिये देश की रक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत बनाने के लिये और बाह्य आक्रमण का हर तरह से मुकाबला करने के लिये हमें अपने सैन्य-बल को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना है। इस दिशा में जो प्रयत्न चल रहे हैं, लद्दाख, नागा क्षेत्र और काश्मीर तथा सीमाओं में जो सुरक्षात्मक कार्यवाही चल रही हैं और दृढ़तर सुरक्षात्मक कदम उठाये जा रहे हैं, उन की प्रशंसा करनी होगी। लेकिन हमारा देश और देश का एक एक जन यह चाहता है कि चीन ने या पाकिस्तान ने हमारी जिस भूमि पर कब्जा किया है, उस के एक एक इंच को उन से आज़ाद कराया जाये और यह भारी उत्तरदायित्व इस मंत्रालय पर आता है।

आज सारा संसार हिंसा की तरफ़ जा रहा है, लेकिन हम अब भी अपनी अहिंसा और सत्य की नीति को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उस का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश को कमजोर बनायें या उस को गुलाम बना दें। बापू जी और भगवान् बुद्ध ने कहा है कि यदि कोई अन्यायकारी, आक्रान्ता या अत्याचारी या आततायी आक्रमण करता है, तो उस का मुकाबला करने के लिये हम को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिये। इसलिये यह आवश्यक है कि देश की रक्षा के लिये हम उन आधुनिक आयुधों की व्यवस्था करें, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हों, चाहे वे किसी भी देश से खरीदे जायें। इस दिशा में हमें पीछे नहीं रहना है।

यद्यपि सरकार की नीतियों और इस मंत्रालय के द्वारा किये गये सुरक्षात्मक कदमों के लिये हमारे रक्षा मंत्री को क्रिटिसाइज किया जाता है—संसार के महानतम देश उन को क्रिटिसाइज करते हैं—लेकिन यू० एन० ओ० में कश्मीर के प्रश्न पर और अन्य प्रश्नों पर हुए वाद-विवाद का जवाब जिस तरह से उन्हों ने दिया है, वह भारी प्रशंसा की बात है। वहां पर उन्हों ने भारत की दृढ़ता और निर्भयता पर आधारित नीति को प्रकट किया है।

अमरीका जैसे संसार के महानतम देश अपने हित के लिये और अपने फ़ौजी गुट के हित के लिए दूसरे देशों को हथियार देते हैं—अमरीका ने पाकिस्तान और वियटनाम को शस्त्रास्त्र दिये हैं—,लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा के लिये लड़ाकू हवाई जहाज रूस से खरीदने का विचार करता है, तो वे देश उस की आलोचना करते हैं। इस देश की सामरिक स्थिति को देखते हुए और इस की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि हमें जिन लड़ाकू हवाई जहाजों या अन्य हथियारों की आवश्यकता हो, हम उन्हें रूस या और किसी देश से खरीदें। यह नीति सब प्रकार से उचित है और सारा देश उस के साथ है।

गोआ का भारत में विलय हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। गोआ विहान में हमारे जवानों ने तथा जल, थल और वायु सैन्य-बल ने जो प्रशंसनीय कार्य किया, वह किसी प्रकार से नहीं भुलाया जा सकता है। उन का कार्य हर प्रकार से प्रशंसनीय है।

जैसाकि मैं ने अभी कहा है, ससार में शान्ति बनाये रखने के लिये हमारा देश जो प्रयत्न कर रहा है, उस को सारा संसार जानता है। आज संसार की स्थिति सूखे घास के ढेर की सी है और अगर उस में कोई चिंगारी नहीं लगाने देता है, तो वह भारत का ही प्रयत्न है। कांगो और वियटनाम आदि जिन देशों की स्वतंत्रता खतरे में है, वहां पर हमारे फ़ौजी अधिकारियों और जवानों ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं सदन के सन्मुख यह बात रखना चाहता हूं कि १५ मई, १९६२ को जब हमारे जवान कांगो से वापस आ रहे थे, तो चीफ़ युनाइटिड नेशन्ज रिप्रेजेन्टेटिव, जोकि

कांगो में नियुक्त हैं, ने किस प्रकार उन की तारीफ़ की । अपने विदाई-सन्देश में उन्हों ने कहा कि जो घटनायें हुई हैं और जिन में यूनिटों ने महत्वपूर्ण योग दिया है, वे ऐतिहासिक घटनायें हैं और एक नये जन्मे, स्वतंत्र राष्ट्र की सम्पूर्ण प्रभुता की इज्जत बचाने के अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक प्रयास का उदाहरण समुपस्थित करती हैं । इस से साफ़ ज़ाहिर है कि हमारा देश किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, अपनी एक एक इंच ज़मीन की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, चाहे उस की सीमा का अतिक्रमण चीन की ओर से हो, या पाकिस्तान की ओर से हो ।

आज हमारे फ़ौजी नौजवान सारे देश की रक्षा के लिये चिलचिलाती धूप में, कड़े जाड़े में और बर्फ़ानी इलाकों में, काश्मीर और नागा प्रदेश में तथा हमारी सीमाओं पर राष्ट्र के प्रहरी बन कर खड़े हुए हैं । इस देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन पर है । हम समझते हैं कि देश की आज़ादी की रक्षा के लिये हमारे फ़ौजी नौजवान एक दीवार बन कर खड़े हैं । इस स्थिति मे उन लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें देना और संतुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है और इस के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें । यही नही, उन के वेतन-क्रम भी सही ढंग से निश्चित किये जाने चाहियें ।

जहां तक एक्स-सर्विसमैन का प्रश्न है, उन में से जो लोग टिरायर हो कर पेन्शन पर चले गये हैं, लेकिन जो अब भी बाडिली फ़िट हैं, शारीरिक दृष्टि से फिट हैं, उन को काम मिलना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन को नौकरी देने और रहने तथा खेती के लिए ज़मीन देने का काम ज़रा धीमी और मन्द गति से चल रहा है । मैं चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और उन के लिये जहां भी नौकरी उपलब्ध की जा सके, उस की व्यवस्था करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त नई तोड़ी गई ज़मीन पर भी उन को अधिकार मिलना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि डिसक्रिमिनेशन की बात को मैं किसी तरह से यहां कहूं । लेकिन इस को मैं बहुत महत्व की बात समझता हूं और गौरव की बात समझता हूं कि देश में अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं बरता जाता है तो वह सेना में नहीं बरता जाता है, फिर चाहे वह वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो । कहीं पर भी किसी प्रकार का डिसक्रिमिनेशन नहीं है । मैं पिछले दस बारह सालों से बराबर लोगों से मिलता रहा हूं । मैं ने कई यूनिट्स को देखा है, फौज की टुकड़ियों को देखा है । कहीं पर भी मैं मे इस तरह की बात को नही पाया है । कुछ वर्ष पूर्व मैं पानी का जहाज़ देखने के लिए गया था, नेवल एक्सरसाइज़िज़ को देखने के लिये गया था और गोदावरी जहाज़ के अन्दर मैं चार दिन रह कर आया हूं । वहां पर अपनी जात बिरादरी वालों से या जो उच्चवर्गीय जाति के लोग थे, उन से भी और जिन को मैं पिछले काफी सालों से जानता था, उन से भी मैं ने जब कोई इस तरह का जाति सम्बन्धी प्रश्न किया तो उन्हों ने एक ही जवाब मुझे दिया, 'डोंट डिसटर्ब सर, डोंट डिसटर्ब, सर ।' यहां पर भी अगर किसी माननीय सदस्य की, इस सदन में जात बिरादरी पूछी जाती है तो बड़े फख्र के साथ कहा जाता है कि मिश्र हूं, बाल्मीकी हूं, रस्तोगी हूं, यह हूं, वह हूं । वहां पर कोई भी इस तरह की बात कहने वाला नहीं था और उन्होंने एक ही बात कही 'डोंट डिसटर्ब सर ।' यह बड़े फख्र की बात है और इस की जितनी तारीफ की जाये थोड़ी है ।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं । वह यह है कि जो एक्स-सर्विसमैन हैं, जो हरिजन हैं, जो अपंग हैं, जो हैण्डीकैप्ड हैं, उन की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय । उन को आवास के लिये, ज़मीन देना और खेती करने के लिये ज़मीन देना बहुत आवश्यक है । इस का आप की ओर से जल्दी से जल्दी प्रयत्न किया जाना चाहिये । मैं कुछ केसिस को जानता हूं और ये उत्तर प्रदेश के और पंजाब के हैं । कुछ हरिजन एक्स-सर्विसमैनों को पांच पांच सौ रुपये दे कर के कुछ पहाड़ी इलाकों में जहां

[श्री बाल्मीकी]

नौतोड़ ज़मीन तैयार हुई है, या जो दूसरी जमीन है, वह दे कर बसाने का वादा किया गया था। लेकिन आज तक उन को यह जमीन प्राप्त नहीं हुई है। जो अधिकारी इस काम को करते हैं, उन के सामने इस बात को मैं ने रखा था। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

आज भी जब देश की सामरिक स्थिति भयंकर रूप धारण किये हुए है, संसार की स्थिति के लिहाज़ से और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, उन के लिहाज़ से, यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी फौजों को तैयार रखें और साथ ही साथ जो दूसरे एक्स-सर्विसमैन हैं, उन को भी चौबीसों घंटे तैयार रखें और उन को ही नहीं बल्कि सारे देश को तैयार रखें ताकि अगर कभी कोई खतरा उपस्थित हो तो उस का डटकर सामना किया जा सके। यदि कोई इस तरह की कटु घड़ी देश के सामने पैदा होती है, तो उस का मुकाबला करने के लिये हमें हमेशा प्राण-पण से तैयार रहना होगा। इस के लिये यह आवश्यक है कि जो हमारे एक्स-सर्विसमैन हैं, उन को हम संतुष्ट करें, उन को जो सुविधायें दी जानी चाहिये, वे उन को मिलें, उन के आवास के लिये, उन के पुनर्वास के लिये, उन को जीवन की अन्य सुविधायें उपलब्ध करने के लिये, हम प्रयत्नशील हों। इस दृष्टि से चाहे उन की नौकरी का प्रश्न हो या उन को ज़मीन देने का प्रश्न, उस को हल करने की ओर हमारा तत्काल ध्यान जाना चाहिये।

अब एक और छोटे से प्रश्न की ओर मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह प्रश्न कैंटोनमेंट्स में भंगियों की स्थिति का है जिसे मामूली लोग अपनी भाषा में कम्पू कहते हैं। मैं समझता हूं कि कैंटोनमेंट्स में सफाई पेशा लोगों की, भंगियों की हालत बहुत बेहतर नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भंगी म्युनिसिपैलिटीज़ में काम करते हैं या कारपोरेशन्ज़ में काम करते हैं, उन के मुकाबले में उन के लिए वहां कुछ काम हुआ है और उन के आवास के लिए, उन को रिहायश सुलभ करने के लिए और उन की नौकरी का एक ढंग तैयार करने के लिए कुछ काम हुआ है। लेकिन आप देखें कि हम ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात स्वीकार की है और हम ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में यह प्रकट भी किया है कि हम हर प्रकार की डिसपैरिटीज़ को दूर कर रहे हैं, इकोनोमिक डिसपैरिटीज़ को दूर कर रहे हैं, तनख्वाहों की डिसपैरिटीज़ को दूर कर रहे हैं लेकिन आज देखने में यह आता है कि जो समाज के हित की दृष्टि से सब से जरूरी काम करता है, उस को तो सब से कम तनख्वाह दी जाती है और जो सब से मंदा काम करता है, वह काम करता है जो किसी महत्ता का नहीं होता है, उस को सब से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। यह सही बात नहीं है और इस तरह असमानता की बात नहीं होनी चाहिये। जो स्वप्न गांधी जी देखा करते थे और जिस आदर्श समाज की स्थापना वह करना चाहते थे, क्या वह स्वप्न पूरा हुआ है और क्या वह आदर्श समाज हम स्थापित कर पाये हैं या स्थापित करने का प्रयत्न कर रह रहे हैं, यह विचारणीय है। हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और शासन को उसके अनुरूप ढालना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान कैंटोनमेंट्स में काम करने वाले स्कैवें जर्ज़ के पे स्केल्ज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां कितनी असमानता है मद्रास में उनका स्केल १८ रुपय से शुरू होता है, वैस्ट बंगाल में २० रुपय से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में२२ रुपये से, विहार में २३ रुपय से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और कम्पटी में २५ रुपये से, आंध्र प्रदेश, में २६ रुपये से, असम में २८ रुपये से, दिल्ली, पंजाब, बम्बई और महाराष्ट्र और केरल में ३० रुपये से शुरू होता है। ये जो वेतन-क्रम हैं, इनको नेशनल इडस्ट्रियल ट्रीब्यूनल ने रखा था। मैं इन वेतन-क्रमों को बहतर नहीं मानता हूं। जबकि ये कैंटोनमेंट्स भारत सरकार के उत्तरदायित्व में हैं, उसके अपने हाथ के अन्दर की

[श्री वाल्मीकी]

नौतोड़ ज़मीन तैयार हुई है, या जो दूसरी जमीन है, वह दे कर बसाने का वादा किया गया थ। लेकिन आज तक उन को यह जमीन प्राप्त नहीं हुई है। जो अधिकारी इस काम को करते हैं, उन के सामने इस बात को मैं ने रखा था। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

आज भी जब देश की सामरिक स्थिति भयंकर रूप धारण किये हुए है, संसार की स्थिति के लिहाज से और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, उन के लिहाज से, यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी फौजों को तैयार रखें और साथ ही साथ जो दूसरे एक्स-सर्विसमैन हैं, उन को भी चौबीसों घंटे तैयार रखें और उन को ही नहीं बल्कि सारे देश को तैयार रखें ताकि अगर कभी कोई खतरा उपस्थित हो तो उस का डटकर सामना किया जा सके। यदि कोई इस तरह की कटु घड़ी देश के सामने पैदा होती है, तो उस का मुकाबला करने के लिये हमें हमेशा प्राण-पण से तैयार रहना होगा। इस के लिये यह आवश्यक है कि जो हमारे एक्स-सर्विसमैन हैं, उन को हम संतुष्ट करें, उन को जो सुविधायें दी जानी चाहिये, वे उन को मिलें, उन के आवास के लिये, उन के पुनर्वास के लिये, उन को जीवन की अन्य सुविधायें उपलब्ध करने के लिये, हम प्रयत्नशील हों। इस दृष्टि से चाहे उन की नौकरी का प्रश्न हो या उन को जमीन देने का प्रश्न, उस को हल करने की ओर हमारा तत्काल ध्यान जाना चाहिये।

अब एक और छोटे से प्रश्न की ओर मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं और वह प्रश्न कैंटोनमेंट्स में भंगियों की स्थिति का है जिसे मामूली लोग अपनी भाषा में कम्पू कहते हैं। मैं समझता हूं कि कैंटोनमेंट्स में सफाई पेशा लोगों की, भंगियों की हालत बहुत बेहतर नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भंगी म्युनिसिपैलिटीज में काम करते हैं या कारपोरेशन्ज में काम करते हैं, उन के मुकाबले में उन के लिए वहां कुछ काम हुआ है और उन के आवास के लिए, उन को रिहायश सुलभ करने के लिए और उन की नौकरी का एक ढंग तैयार करने के लिए कुछ काम हुआ है। लेकिन आप देखें कि हम ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात स्वीकार की है और हम ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में यह प्रकट भी किया है कि हम हर प्रकार की डिसपैरिटीज को दूर कर रहे हैं, इकोनोमिक डिसपैरिटीज को दूर कर रहे हैं, तनख्वाहों की डिसपैरिटीज को दूर कर रहे हैं लेकिन आज देखने में यह आता है कि जो समाज के हित की दृष्टि से सब से जरूरी काम करता है, उस को तो सब से कम तनख्वाह दी जाती है और जो सब से मंदा काम करता है, वह काम करता है जो किसी महत्ता का नहीं होता है, उस को सब से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। यह सही बात नहीं है और इस तरह असमानता की बात नहीं होनी चाहिये। जो स्वप्न गांधी जी देखा करते थे और जिस आदर्श समाज की स्थापना वह करना चाहते थे, क्या वह स्वप्न पूरा हुआ है और क्या वह आदर्श समाज हम स्थापित कर पाये हैं या स्थापित करने का प्रयत्न कर रह रहे हैं, यह विचारणीय है। हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और शासन को उसके अनुरूप ढालना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान कैंटोनमेंट्स में काम करने वाले स्कैवें जर्ज के पे स्केल्ज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां कितनी असमानता है मद्रास में उनका स्केल १८ रुपय से शुरू होता है, वैस्ट बंगाल में २० रुपय से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में२२ रुपये से, बिहार में २३ रुपय से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और कम्पटी में २५ रुपये से, आंध्र प्रदेश, में २६ रुपये से, असम में २८ रुपये से, दिल्ली, पंजाब, बम्बई और महाराष्ट्र और केरल में ३० रुपये से शुरू होता है। ये जो वेतन-क्रम हैं, इनको नेशनल इडस्ट्रियल ट्रीब्यूनल ने रखा था। मैं इन वेतन-क्रमों को बहतर नहीं मानता हूं। जबकि ये कैंटोनमेंट्स भारत सरकार के उत्तरदायित्व में हैं, उसके अपने हाथ के अन्दर की

[श्री रघुनाथ सिंह]

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर हम नेवी की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, नेवी की तरक्की नहीं कर सकते हैं तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। मैं परसनेल के सवाल को लेता हूं। हिन्दुस्तान के पास १२ ०० आफिसर हैं और १२, ००० रेटिंग्ज़ हैं। पाकिस्तान के पास ७ ०० आफिसर हैं और ७, ०००रेटिंग्ज़ हैं। थाईलैण्ड जो कि एक छोटा सा देश है, उसके पास २, ०००आफिसर हैं और १६, ०००मेरेटिंग्ज़ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के पास हमारे मुकाबले में कुल जमा पूंजी पांच सौ अफसर और पांच हजार रेटिंग्ज़ ही कम हैं। पाकिस्तान का जो क़ोस्ट है वह ९९५ मील है और आपका कोस्ट ३५३५ मील है। ९९५ मील कोस्ट के वास्ते उन्होंने अपने पास २२ जहाज रक्खे हैं और जो आप का तीन गुना क़ोस्ट ३५३५ मील का है उसके लिये आपके पास ३६ जहाज हैं। पाकिस्तान की नेवी हिन्दुस्तान की नेवी से ६ ०परसेन्ट है और हिन्दुस्तान की नेवी जो चीन की नेवी है उस की २ ० परसेन्ट है।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : आप अपनी मिलिटरी सीक्रेट्स को दुनिया को बतला कर अपने को बदनाम करते हैं। आप चाहें तो कहें, लेकिन मुझे यह प्रापर नहीं मालूम होता। यह हमारी सीक्रेट्स हैं।

श्री गहमरी (गाजीपुर) : जब यह तमाम चीजें पुस्तकों में निकल आई हैं तो उनको छिपाने से क्या फायदा ?

श्री रघुनाथ सिंह : यह पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। आपको क्यों पिंच करता है जब मैं चाइना का नाम लेता हूं ?

जहां तक हिन्दुस्तान की नेवी का सवाल है, आप सन् १९५७–५८ के बजट को देखिये। हम पूरे बजट का ३५ परसेन्ट डिफेंस को देते थे। आज हम जो डिफेंस को दे रहे हैं वह सिर्फ २४ परसेंट है। आप देखिये सन् १९५६ और १९५७ को। चीन का ऐग्रेशन हुआ। चीन धीरे धीरे हमारी जमीन को लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे चीन हमारी जमीन को लेने लगा, हमारा डिफेंस बजट सिकुड़ता चला गया और सिकुड़ते सिकुड़ते वह ३५ परसेन्ट से २४ परसेन्ट हो गया और हमारा सिविल एक्स्पेन्डिचर ६५ परसेन्ट से ७६ परसेन्ट हो गया। मैं नहीं समझ पाता कि यह कैसी एकानमी है और यह कैसा डिफेंस बजट है। जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान एड लेने के बाद भी ८ ०परसेन्ट अपने डिफेन्स पर खर्च करता है। अब आप ब्रिटेन को देखिये। ब्रिटेन अपने बजट का २५ परसेन्ट डिफेन्स पर खर्च करता है और अगर अमरीका को आप देखें तो अमरीका अपने बजट का ५ ० परसेन्ट से ऊपर डिफेंन्स पर खर्च करता है। लेकिन हमारे बजट का जो परसेन्टेज डिफेन्स पर खर्च होता है वह केवल २४ परसेन्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा बजट है वह ठीक नहीं है और हमको अपने डिफेन्स पर ज्यादा खर्च करना चाहिये।

सुरक्षा विभाग की जो रिपोर्ट छपी है उसमें मैंने देखा कि न्यूक्लिअर वेपन्स और गाइडेड मिजाइल्स के वास्ते कुछ नहीं रक्खा गया है, जबकि इंग्लैण्ड अपने कुल बजट का १० परसेंट केवल न्यूक्लिअर वेपन्स पर खर्च करता है। लेकिन हमारे यहां एक पैसा भी उसके लिये नहीं रखा गया है। मैं कहूंगा कि आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी है वह यह है कि जिस प्रकार से न्यूक्लिअर वेपन्स के ऊपर अमरीका और इंग्लैण्ड खर्च कर रहे हैं उसी प्रकार से हम भी करें।

अब आप नेवी को लें। आप कहते हैं कि आप नेवी को बढ़ायेंगे। लेकिन नवी के ऊपर आप कुल डिफेन्स बजट का ७ या ६½ परसेन्ट खर्च करते हैं जबकि सन् १९६१–६२ में हमने कुल डिफेन्स बजट का ७·९ परसेंट नेवी के ऊपर खर्च किया था। आज हम उसे नीचे करते करते ६½ परसेन्ट पर लाये

हैं। हमने अपने बजट में दिखलाया है कि हम १९ करोड़ रुपये नेवी पर खर्च करने जा रहे हैं। आप १९ करोड़ रु० खर्च करने नहीं जा रहे हैं बल्कि नेवी का जो बजट है उसको आपने कम किया है। अगर हम अपने डिफेन्स बजट को देखें तो मालूम होता है कि हमारा बजट अनबैलेंस्ड है। आप इंग्लैण्ड के बजट को देखिये। इंग्लैण्ड में नेवी, आर्मी और एअरफोर्स में कुल ७ परसेंट का अंतर पड़ता है। इसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपके यहां क्या है? आपके यहां करीब २२४ करोड़ रु० आर्मी पर है और १९ करोड़ रु० नेवी पर है। अमरीका या चाइना या इंग्लैण्ड आदि के बजट को लीजिये तो वहां कहीं पर भी आर्मी, नेवी और एअरफोर्स में ७ परसेंट से ज्यादा मार्जिन नही है। हिन्दुस्तान में ७ परसेंट के अंतर की बात तो छोड़िये हम नेवी पर कुल डिफेंस बजट का ६·५ परसेंट खर्च करने जा रहे हैं। इतना आपका बजट अनबैलेन्स्ड है और आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की रक्षा करें। मैं समझता हूं कि इससे हिन्दुस्तान की रक्षा होनी कठिन है।

इसके बाद आप इक्विपमेंट को लीजिये। इक्विपमेंट में आपने रक्खा है १.७५ करोड़ रु०। मैं कहता हूं कि इतने में तो आप एक क्रूजर भी नहीं खरीद सकते। अगर आप को एक क्रूजर चाहिये, या एक बैटलशिप चाहिये या एक डिस्ट्रायर चाहिये और सोचिये कि उसको १ करोड़ ७५ लाख रु० में खरीद लें तो यह नामुमकिन है। आप इस साल नेवी में क्या एडीशन करने जा रहे हैं? कुछ नहीं। आप के पास दो डाकयार्ड हैं। इन डाकयार्डस में से जो मजगांव का डाकयार्ड है उसके लिये आपने ५० लाख रु० रक्खे हैं और गार्डन रीच का जो डाकयार्ड है उसके लिये आपने २५ लाख रु० रक्खे हैं। जब दुनिया में नेवी को इतनी तरक्की हो रही है और नेवल वारफेअर वहां से होने जा रहा है या होगा, उस समय आप नेवी पर सिर्फ इतना खर्च करने जा रहे हैं। इससे तो आप एक छोटा शिपयार्ड भी नहीं बना सकते एक शिपयार्ड के लिये ४ करोड़ से लेकर ८ करोड़ रु० तक की आवश्यकता होती है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप को हिन्दुस्तान को डिफेन्ड करना है तो जो इस देश के दो शिपयार्ड हैं वहां सबमैरीन बदनी चाहिये। हमें अपने घर में ही शिप्स बनाने चाहियें और देश को न्यूक्लिअर बार के लिये तैयार करना चाहिये। हम लोग पीसफुल हैं, शान्ति में हमको विश्वास है, पंचशील में हमें विश्वास है, लेकिन न्यूक्लिअर सबमैरीन्स हम बनायें तो कोई हर्ज नहीं। हम गाइडेड मिजाइल्स की सबमेरीन्स बनायें तो कोई नुकसान नहीं है। इस वास्ते जिन लोगों ने इसके समर्थन में कहा है मैं उनका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि हमको न्यूक्लिअर वेपन्स बनाने चाहियें।

सबमैरीन्स पर मैं क्यों जोर देता हूं? आप वर्ल्ड वार द्वितीय को देखिये। २१ मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज डुबा दिये गये। उनमें से १४ मिलियन टन के जहाज यू० बोट्स के द्वारा डुबाये गये पूर्वीय क्षेत्र में से ८·२ मिलियन टन के जहाजों में शामालियेन सबमैरीन्स के द्वारा डुबाये गये। इस तरह से आप देखेंगे कि जहां पर नेवल वारफेअर होता है उसमें ६० परसेन्ट से ज्यादा जहाज सबमैरीन्स रक्खे गये हैं। आज हिन्दुस्तान के पास एक भी सबमैरीन नहीं है। लिहाजा मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपके पास जो दोनों डाकयार्ड हैं उनको आप ऐसा बनायें कि वहां पर नैवल सबमैरीन तैयार हो सकें।

हमारे कुछ दोस्तों ने कामनवेल्थ एक्साइज के बारे में कहा। आपके सामने दो चीजें हैं। सेन्टो और सिआटो। दोनों का पाकिस्तान सदस्य है। कामनवेल्थ एक्साइज में आप जाते हैं। उसमें पाकिस्तान भी सदस्य है। कामनवेल्थ एक्साइज में आप जाते हैं। उसमें पाकिस्तान भी भाग लेता है और आप भी भाग लेते हैं। ऐसी हालत में हमारे यहां सीक्रेसी कैसे रहेगी। जब कामन्वेल्थ कंट्रीज की नेवी वहां जाती हैं और वहां पर एक्साइज में हिस्सा लेती हैं, उनमें पाकिस्तान भी हिस्सा लेता है और हिन्दुस्तान भी हिस्सा लेता है, तो उसमें सीक्रेसी कैसे रहेगी। आप अपने को वहां पर ओपन करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के सामने बल्कि जितनी कंट्रीज उसमें हिस्सा लेती हैं उनके सामने भी।

[श्री रघुनाथसिंह]

साथ ही साथ आप देखिये कि कुछ महीने हुए अमरीका ने पाकिस्तान में गाइडेड मिजाइल्स और न्यूक्लिअर वारफेअर की ट्रेनिंग दी है । एक तरफ तो अमरीका गाइडेड मिजाइल्स को और न्यूक्लिअर वारफेअर की ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं ? हाथ पर हाथ रक्खे हुए बैठे हैं । हमें इस बात से होशियार रहना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जितनी हमारी एनर्जी है सब जहां तक न्यूक्लिअर वारफेअर का सम्बन्ध है, उसकी तरफ लगायें । यू० के० की जो डिफेन्स रिपोर्ट सन् १९६१ की है उस में से मैं आप को एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"चीन की उगती हुई शक्ति कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता ।"

चाइना की शक्ति इतनी ज्यादा हो गयी है कि हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते ।

मैं जानता हुं कि पाकिस्तान की एअर फोर्स आज हम से ज्यादा सुपीरियर है निःसन्देह । इस बात को छिपाने से कोई फायदा नहीं है । इससे रक्षा का सम्बन्ध है इसलिए यह हमें स्पष्ट कहना चाहिए कि पाकिस्तान की एअर फोर्स हम से सुपीरियर है । पाकिस्तान को गाइडेड मिसाइल्स और न्यूकलियर वैपन्स की ट्रेनिंग दी गयी है । हम को वैसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी है ।

आज आप दुनिया के देशों के बजट देखें तो आप को मालूम होगा कि उन में आर्मी से ज्यादा एअर फोर्स पर खर्च किया जाता है इस वास्ते कि एअर फोर्स से हम बम्बार्डमेंट कर सकते हैं । मैं आप को केवल यू० के० का उदाहरण देना चाहता हुं । वहां आर्मी पर ५०६ मिलियन पाउंड खर्च किया जाता है तो एअर फोर्स पर ५२६ मिलियन पाउंड खर्च किया जाता है । दुनिया में, जैसा कि हमारे और भाइयों ने कहा, कनवन्शनल वार का समय गया, अब तो वैज्ञानिक लड़ाई का जमाना है । जो विज्ञान में तरक्की करेगा उसी के हाथ में युद्धस्थल होगा और वही विजय प्राप्त करेगा । इसी लिए मैं कहना चाहता हुं कि एअर फोसकीहम ज्यादा तरक्की करें अ.र रूस जो हमें एम० आई० जी० एअर क्राफ्ट दे रहा है उनको हमें लेना चाहिए । अमरीका की पालिसी क्या है ? एक तरफ तो वह पाकिस्तान को नये किस्म के हवाई जहाज़ मुफ्त देता है और दूसरी तरफ हम से कहता है कि तुम इनके लिए रुपया दो । एक तरफ पाकिस्तान को फ्री डिलीवरी दी जाती है और हम से रुपया मांगा जाता है । हम उसे कैसे रुपया दे सकते हैं ।

पाकिस्तान ने हमारी ३० हजार वर्ग मील भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान के हाथ हमारा सीज़ फायर है, पाकिस्तान के साथ हमारी अभी कोई सन्धि नहीं है । जब तक पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर है तब तक पाकिस्तान की फौजें काश्मीर में रहेंगी । जब तक अमरीका पाकिस्तान को सहायता देता है तो हम भी स्वतंत्र हैं कि अपनी रक्षा के लिए दुनिया में जहां से भी हथियार मिल सकें उनको लें ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय बहुत देर से डिफेंस के मुताल्लिक बहस सुन रहा हूं अ.र इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत में मुकाबला करने के लिए जिस एटमासफियर की जरूरत है वह तैयार नहीं हो सका है । एकछोटा सा मिलिटरी आरगेनाइजेशन इतनी बड़ी शक्ति से हमारी रक्षा नहीं कर सकता । जिस शत्रु के साथ हमारा मुकाबला है उसके पास १ करोड़ ६० लाख से ज्यादा फौज है । हमारी २५ लाख आर्मी उसके मुकाबले खड़ी नही रह सकती ।

दूसरे उसके साथ ऐसे मित्र हैं जो समय पड़ने पर उसे अच्छी से अच्छी इमदाद दे सकते हैं । आज हम इंटरनेशनल पालिटिक्स में मित्र विहीन खड़े हुए हैं । तटस्थता का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने हाथ कटवा लें या मित्र विहीन खड़े हो जावें । तटस्थ का अर्थ क्या है ? "तटस्थ" शब्द संस्कृत का है । तटस्थ का अर्थ है तट पर बैठा हुआ, तीर पर बैठा हुआ, उदासीन, जो लहरों से नहीं

टकराता है, जो मौजों से टक्कर नहीं लेता है । जो तटस्थ है उसे कोई भी आकर और धक्का देकर समुद्र में डाल देगा । आज हम मित्र विहीन हैं । अभी देश के अन्दर वह शक्ति नहीं पैदा हो सकी है । आवश्यकता इस बात की है कि देश के अरमान जाग जायें और देश फौजी रक्षा के लिए तैयार हो जाये ।

कोई यह ख्याल न करे कि रूस ने हमारे लिए जो दो शब्द हमदर्दी के कह दिये उससे कुछ बनता है । कोई भी सोशलिस्टिक देश वक्त पड़ने पर हमारी मदद नहीं करेगा । चाणक्य ने जो कि सब से बड़ा पालोटीशियन समझा जाता है कौटिल्य अर्थ शास्त्र कार ने लिखा है--

सुतप्तम् अपि पानीयम्, शमयत्येव पावकम् ।

पानी को चाहे जिस डिग्री तक गर्म कीजिये, ऊंची से ऊंची हीट पर गर्म कीजिये लेकिन वह हमेशा आग को बुझावेगा ही । अगर हमारे प्रधान मंत्री हवा में उड़ रहे हों और आसमान में किले बना रहे हों पर यह खयाल करते हैं कि किसी ने दो लफ्ज सिम्पथी के हमारे लिए कह दिये तो हमारी रक्षा हो जायेगी, यह असम्भव है। २५ लाख की आर्मी डेढ़ करोड़ की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती । आज प्रत्येक भारतवासी को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी होगी, सारे देश का सैनिकीकरण करना होगा । हर एक बालिग हथियार ले कर सीना निकाल कर जब चलेगा तब हम टक्कर ले सकते हैं । वरना हम लोग फेल हो जायेंगे ।

देश की रक्षा ये लोग नहीं कर सकते । इस को कौन मान लेगा । मैं बहुत निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा मोस्ट प्रेशस ज्वल गिलगित है वह पाकिस्तान के कब्ज में है, और मैं इस बात को भी छिपाता नहीं हूं कि कैलाश और मानसरोवर चीन के कब्जे में हैं । चूंकि मैं हमदर्द हूं, हितैषी हूं, इसलिए ऐसा कहता हूं । मैं विरोधी नहीं हूं । यह "विरोधी" या "अपोजीशन" शब्द तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, यह शब्द तो वैटर्स्न कल्चर से आया है । तो हम विरोधी नहीं हैं । हम तो हितैषी हैं । हमारे यहां कहा गया है :

पुरुषा वहवो राजन्, सततं प्रियवादिनः
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम् ।

हम हितैषी हैं । हम ने उन मूर्तियों से जो सामने बैठी हैं भारत भूमि के लिए ज्यादा कुर्बानियां की हैं । हमने भारत भूमि के लिए ज्यादा त्याग और तपस्या की है और ज्यादा कुर्बानियां दी हैं । हम को यह खयाल नहीं करना चाहिए कि जब मौका आयेगा तो कोई देश हम को सहायता देगा । दुनिया में उजड़े हुए का पिटे हुए का और कमजोर का कोई साथ नहीं देता । देश की रक्षा वह लोग करेंगे जिन्हें फौजी तालीम होगी, जिन्हें सैनिक शिक्षा होगी । आज देश का बच्चा-बच्चा रक्षा करना चाहता है, आज देश का बच्चा-बच्चा तैयार है । जनता चाहती है कि रक्षा हो । लेकिन हमारी लीडरशिप फेल हो गयी है । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिजो हमारी सेना के होते हुए भी निकल गया । मुझे फिजों का बयान पढ़ कर बड़ा अफसोस हुआ । उसका बयान बहुत लम्बा चौड़ा है मगर मैं उसकी कुछ सतरें आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । यह बयान नार्दन पत्रिका में इस प्रकार छपा है कि फिजों ने कहा कि पांचसौ मील का सफर कर के भारतीय सेना के बावजूद इतने बड़े डेलोगेशन का आना नागालैण्ड की शक्ति का परिचायक है । पांच सौ मील का सफर कर के डेढ़ सौ सिपाही हमारी चालीस हजार फौज की आंखों में धूल डाल कर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं :

जिसे है फिक्र मरहम की उसे दुश्मन समझते हैं,
इलाही खैर हो यह जख्म अच्छा हो नहीं सकता ।

[श्री यशपाल सिंह]

मैं कमजोर प्वाइंट सामने रखता हूं। विडो रूल भी सहन नहीं कर सकता था। अगर किसी बेवा का भी राज्य होता तो वह इसको बरदाश्त नहीं कर सकती थी कि हमारी ४० हजार फौज के सामने से डेढ़ सौ नागा होस्टाइल्स दूसरे मुल्क में पहुंच जायें और वहां उनका जलूस निकाला जाये।

देश की रक्षा चरित्र से होगी, जब इंडीवीजुअल कैरेक्टर बनेगा तब देश की रक्षा होगी, देश की रक्षा वह करेंगे जिनकी आंखों में देश भक्ति का तेज होगा जिनकी छाती में ब्रह्मचर्य का बल होगा, जिनके मन में भारत भूमि का अभिमान होगा। कौन मान लेगा कि आप देश की रक्षा करना चाहते हैं ? जिस देश की १४ हजार मुरब्बा मील भूमि दुश्मन के कब्जे में है उस देश के सिनेमा घर एक घंटे के लिए भी बन्द नहीं होते, उस देश की शराबें एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं होतीं, उस देश के कल्चरल प्रोग्राम एक दिन के लिए भी बन्द नहीं होते, उस देश का नाचना और गाना एकदिन के लिए भी बन्द नहीं किया गया। आप के दिल में कुछ है और जबान पर कुछ और है। क्यों नहीं सिनेमा बन्द किये जाते ? क्यों नहीं शराबें बन्द की जातीं ? यह जो दिल्ली में नृत्य कला भवन है और संगीत कला भवन है जिसमें लाखों की होली हो चुकी है, इनके दरवाजों को बन्द करके इन में मिलिटरी ट्रेनिंग स्कूल खोले जायें। तब देश की रक्षा होगी।

मैं बड़े अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिवालवर और बन्दूक के लाइसेंस देने के बारे में जो पार्टी बरसरे इक्तिदार है उसका यह रवैया है कि वह उसके बदले में वोट खरीदती है। इलेक्शन में सौदे किये जाते हैं कि तुम हम को पांच हजार वोट दिलवा दो तो मैं तुम्हें रिवालवर का लाइसेंस दिलवा दूंगा। यह एक आजाद मुल्क के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मैं भी बदस्किमती से या खुश किस्मती से उसी धड़े में था जिस में सामने की मूर्तियां हैं। हम ने बापू के चरणों में करांची में जेल कर यह कसम खायी थी कि हिन्दुस्तान जब आजाद हो जायेगा तो उसका हर एक सच्चरित्र नागरिक हथियार रख सकेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। एक एम० एल० ए० का लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया। मैं उस एम० एल० ए० से खुद मिला। वह हरदोई के हैं। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की खुशामद नहीं की। इसलिए उनकी बन्दूक की दरखास्त खारिज कर दी गयी और उनको बन्दूक नहीं दी गयी। आप देखें कि जो आदमी लाखों आदमियों का प्रतिनिधि है अगर वह सच्चरित्र नहीं होगा तो कौन सच्चरित्र होगा। यह चीज आज देखने की है। हम कहते हैं कि लाइसेंस फ्री किये जायें ताकि हर एक सच्चरित्र नागरिक हथियार रख सके, तभी देश की रक्षा होगी। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा डिबेट कर सकते हैं और अच्छी बहस कर सकते हैं और आज के इस सैट अप में भारत के प्रधान मंत्री को एक वकील की जरूरत भी थी। एक राजनीतिज्ञ की जरूरत थी लेकिन देश की रक्षा का मामला उनके बस का नहीं है। मिलेटरी जीनियस से भारत के प्रतिरक्षा मंत्री लाखों कोस दूर हैं। मिलेटरी जीनियस उनको छू तक नहीं गया है। इन पिछले १३ सालों में जितनी तबाही हुई है अगर किसी दूसरे मुल्क में ऐसी तबाही हुई होती तो वहां की जनता सरकार से इस्तीफा मांग लेती। आज हम कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं तो कब जाकर हम तैयार होंगे ? आजादी मिले १४ साल हो गये। इन चौदह सालों में हम तैयार नहीं हो सके हैं और जैसी रफ्तार हमारी है और आसार नजर आ रहे हैं उससे आगे भी जाकर तैयार नहीं होंगे। डिस्कशन और डिबेट से काम नहीं चल सकता है।

"कसीदे से न चलता है न यह दोहे से चलता है,
समझ लो खूब कारे सलतनत लोहे से चलता है।"

हमें बच्चे बच्चे के अंदर यह भावना पैदा करनी होगी कि वह इस देश का मालिक है और इस देश की रक्षा कर सकता है। कांग्रेस सरकार की इंटैग्रेटी का तकाजा है कि तमाम पार्टियों को

बुला कर, देश को तमाम पार्टियों की राउन्ड टेबुल कान्फ्रेंस कर के जिसमें सोशलिस्ट्स बुलाये जायें, कम्युनिस्ट्स बुलाये जायं, स्वतंत्र पार्टी बुलाई जाय, प्रजा सोशलिस्ट, राम राज्य परिषद्, हिन्दू महासभा आदि बुलाई जायें और जन संघ वाले बुलाये जायं। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह कहा जाय कि भारत की रक्षा का मामला, भारत माता की सीमाओं का मामला पार्टी पालिटिक्स से ऊपर है। लेकिन चीजों को छिपा कर रक्खा जाता है। श्री राजगोपालाचार्य से जब बापू जी मशविरा करते थे तो उन राजगोपालाचार्य जी से प्रधान मंत्री महोदय क्यों मशविरा नहीं करते हैं? जाहिर है कि उनका अनुभव ज्यादा है, उनका तजुर्बा ज्यादा है और वह ज्यादा देश का हित कर सकते हैं। आज देश को कोआपरेशन की जरूरत है। देश के अंदर एक ऐसी भावना पैदा करने की जरूरत है कि यह भारत भूमि ४० करोड़ नर नारियों की मां है और ४४ करोड़ देशवासियों को इस की हिफाजत करनी पड़ेगी। किसी देश के ऊपर जो आप यह ख्याल करते हों कि कोई देश आप का साथ देगा, आप मुगालते में हैं, कोई भी देश आप का साथ नहीं दे सकता है। वे आप से हमदर्दी कर सकते हैं, लिप सिम्पैथी कर सकते हैं लेकिन आपका साथ सक्रिय रूप मे कोई भी अन्य मुल्क नहीं दे सकता है।

मुझे आपसे अर्ज करना है कि आप भले ही गैलरीज को बंद कर दीजिये, कर्मचारियों को आने से रोक दीजिये और अफसरान को अंदर आने से रोक दीजिये लेकिन कम से कम हाउस के सामने यह जरूर रखिये कि आप क्या करने जा रहे हैं? किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? हिमालय का बौर्डर कोई मामूली बौर्डर नहीं है और उस हिमालयन बौर्डर का इंतजाम और हिफाजत करना दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और हमारे देश के लिए उसका बहुत महत्व है। लेकिन अब आप यह कहते हैं कि मैकमोहन लाइन को हम चीन और भारत की सीमा रेखा मानते हैं तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। यह मैकमोहन लाइन अंग्रेजों की बनाई हुई है। मैकमोहन लाइन उन अंग्रेज इम्पीरियलिस्ट्स की बनाई हुई जिन्होंने कि हमें सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रक्खा। हमारी लाइन तो कैलाश और मानसरोवर हैं। गौरीशंकर और ऐवरेस्ट की चोटी हमारी सीमा है। मैकमोहन लाइन को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन हमारी छाती के ऊपर खड़ा हुआ है, हमें नीचे गिरा सकता है और जब चाहे संगसार कर सकता है। पत्थरों से हमे नीचे दबा सकता है। इसलिए मैकमोहन लाइन हमारी लाइन नहीं है। भारत की भौगोलिक लाइन या सीमा हिमालय की चोटी है और अगर इस हिमालय की रक्षा नहीं होती है तो भारत की भी रक्षा नहीं हो सकती है।

"हितम् मनोहारी च दुर्लभम् वचः"।

मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि लगे तो मीठी लेकिन उससे भारत की जनता का अहित निहित हो। दवा मीठी भी हो और फायदा भी करने वाली हो यह जरा मुश्किल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि सारे राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण कीजिये, कोटोजम और डालडा को बन्द कीजिये। जिन रंगों में कोटोजम और डालडा बसा हुआ है उनमें देश भक्ति नहीं रह सकती। उन रंगों के अंदर देश के खातिर लड़ने का माद्दा नहीं रह सकता है। देश के अंदर एक पवित्रता आयेगी, इंडिविजुएल कैरक्टर से नेशनल कैरेक्टर बनेगा। अगर इनफरादी तौर से अखलाक ऊंचा नहीं होगा तो काम का एखलाक ऊंचा नहीं हो सकता है।

"अफराद से बनती हैं अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।"

हर एक आदमी में देशभक्ति देखनी होगी। आज देश के लिए सब से बड़ा घोर संकट है। यह

[श्री यशपाल सिंह]

इतना बड़ा संकट है कि इस से पहले भारत भूमि ने यह संकट नहीं देखा था। जो लोग यह कहते हैं कि बातों से मसला हल कर लिया जाय यह वह लोग हैं जो कि ऐयर कंडीशंड हाल में बैठे रहते हैं और चाहते हैं कि उनके हलुवे मांडे में और ऐशो आराम में कोई फर्क न आये। बातों से यह मसला हल नहीं हो सकता है। मसल मशहूर भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शक्ति से मसला हल होता है Not by parliamentary speeches nor majority votes are mighty questions of age solved, but it is through a policy of blood and iron. (संसदीय भाषणों या बहुमत के मतदान द्वारा नहीं।) यह बिस्मार्क ने लिखा है। हर एक इंसान को हथियार रखना सीखना होगा, हर एक को मिलेटरी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। आज धर्मी का एग्जिस्टैंस खतरे में है, और जब धर्म का अस्तित्व खतरे में है तो धर्म का पालन कौन करेगा? धर्म की एग्जिस्टैंस को बचाना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि देश के अन्दर जो धर्मी हैं उसकी रक्षा की जाय। उसके लिए देश माता की रक्षा को जाय। उसके बाद धर्म का पालन हो सकेगा और यह तभी हो सकेगा जब ४४ करोड़ इंसानों में हर एक आर्गेनाइजेशन में और हर एक हिन्दुस्तानी के मन में यह बात गूंज जायेगी कि देश हमारा है और इसकी रक्षा हमें करनी है। यह काम आज से और अभी से शुरू करना होगा। सारे देश का नेशनलाइजेशन हो और यदि देश के अन्दर एक इस तरह का ऐटमौसफियर पैदा हो जायगा तो देश का बच्चा-बच्चा अपने देश हितों की रक्षा के लिए कमर कस कर खड़ा हो जायगा। हम ने देखा कि स्पार्टा के ऊपर जब संकट था तो स्पार्टा की सरकार को यह कानून बनाना पड़ा कि जो बच्चा पैदा हो उसको २४ घंटे छत के ऊपर डाल दिया जाय और अगर वह २४ घंटे की सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर जाय तब तो उसे पाल लिया जाय वरना इतने कमजोर बच्चे का देश के लिए कोई उपयोग नहीं है। आज भी आप को इस तरीके का कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। यह जो आप आबादी का रोना रोते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है तो मेरा कहना है कि आबादो का इलाज धर्मयुद्ध है। आबादी का इलाज सैल्फ कंट्रोल है। आबादी का इलाज बर्थ कंट्रोल नहीं हो सकता है। यह भारत भूमि जो कि गांधी और गौतम की भूमि है वहां बर्थ कंट्रोल एकदम अनुचित है। महात्मा गांधी कहते थे कि बर्थ कंट्रोल सब से बड़ा पाप है। परिवार नियोजन सब से बड़ा पाप है। उस गांधी के चेले बैठ कर करोड़ों रुपये परिवार नियोजन पर खर्च करते हैं, मैं साफ लफ्जों में कहता हूं कि यह परिवार नियोजन नहीं बल्कि व्यभिचार नियोजन है। हमें तो वह शिक्षा देनी होगी जो कि महात्मा गांधी की शिक्षा थी। फौर दी सेक औफ ए चाइल्ड ओनली। सिर्फ औलाद पैदा करने के लिये गृहस्थ किया जाये। गौतम, विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द की केवल संतानोत्पत्ति के लिये "गृहस्थ" की शिक्षा देनी पड़ेगी। उस शिक्षा से हमारा भारत सुखी हो सकेगा। आज हमारे सामने यह मसला है। इस बढ़ती हुई पापुलेशन का इलाज धर्मयुद्ध है। अगर आज दो करोड़ आदमी इधर, उधर हिमालय की तरफ बढ़ जायं तो उन चीनी अफीमचियों को क्या हिम्मत है कि वह हमारे सामने ठहर सकें। हमारे एक एक शख्स ने जाकर इन पहाड़ों को फतह किया है। हमारा दादा हरीसिंह नलवा केवल थोड़े से घुड़सवार लेकर गया था और कबालियों की तमाम ताकत को खत्म कर के आया था। "आज तक भी रोते हैं जब बच्चे उन पठानों के, तो अम्मा कहती सोजा, सोजा आय गयो नलवा" आज तक हमारी यह धाक है। हम ने कुर्बानियां दी हैं कोई कारण नहीं है कि हम इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण न कर सकें। देश का बच्चा-बच्चा आज आजादी की रक्षा करने को तैयार है। हर एक की भुजा फड़क रही है। हर एक की छाती के अंदर जोश है। अगर कोई तैयार नहीं है तो दो मूर्तियां तैयार नहीं हैं। एक तो प्रतिरक्षा मंत्री और दूसरे उसके मोह में फंसे हुए प्रधान मंत्री इन दो मूर्त्तियों के अलवा सब भारतवासी तैयार हैं और चाहते हैं कि इस देश की रक्षा की जाय। यह काम तभी होगा जब सैनिकीकरण होगा, मिलेटिराइजेशन

होगा । यह काम तभी होगा जब भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का मोका दिया जायगा ।

आज जरूरत इस बात को है कि हथियारों पर से यह लाइसेंस की पाबन्दी हटा ली जाय । स्कूल और कालिजों में हर एक बच्चे को फौजी तालीम अनिवार्य रूप से दी जाय । हर एक बालिग आदमी के लिए फ़ौजी तालीम का इंतजाम हो । नाऊ और नैवर का सवाल है । इसे या तो आज किया जायगा वरना यह कभी नहीं हो सकता है । यह मोस्ट क्रिटिकल प्वाएंट है । इस से अधिक घोर संकट का काल कभी भारत भूमि के ऊपर नहीं आया है । इसे हम ऐयर कंडीशंड हाल में बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं । सर्दियां आजायगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि गर्मियों में हमरी फौज आगे बढ़ सकती है । गर्मियों मे हमारे रक्षा मंत्री जाकर देख सकते हैं और हम भी जाकर मोर्चे के ऊपर देख सकते हैं । जब सर्दियां आयेगी तो हमारे कोमल तनु और नाजुक मिजाज प्रतिरक्षा मंत्री के पैर और ज्यादा सूज जायेंगे, अभी उनके पैरों पर वरम है और लकड़ी लेकर चलना पड़ता है तब तो यह और भी ज्यादा सूज जायेंगे और उन पर और ज्यादा वरम आ जायेगा । दिस इज दो वैस्ट टाइम फौर डिफेंस । इस से बढ़ कर उपयुक्त समय दूसरा नहीं आ सकता है ।

मैं आप के द्वारा इस हाउस से यह कहना चाहता हूं कि धर्म, भारतीयता और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ४४ करोड़ इंसान मिल कर भारत माता की रक्षा करें । जिन लोगों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना खून दिया आज हम उनका नाम तक नहीं लेते हैं । बादशाह खां, सरहदी गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खां का आज हम नाम नहीं लेते हैं । नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को हम भुला बैठे हैं । जिस दिन इस संट्रल हाल में नेता जो की तस्वीर होगी, जिस दिन खान अब्दुल गफ्फार खां की सेंट्रल हाल मे तस्वीर होगो, उस दिन हमारा सेंट्रल हाल उचित तौर पर सजा हुआ माना जायगा । देश के अंदर इन देशभक्त की मूर्त्तियां स्थापित की जायं । अगर हम इन देशभक्तों को जिन्होंने कि आजादी की खातिर अपने प्राणों की कुर्बानी दी उनको भुला देंगे, उन शहीदों की याद हम नहीं करेंगे, जिन्होंने कि अपना खून दिया, तो हमारी संस्कृति जिन्दा नहीं रह सकतो है । आज धर्म का अस्तित्व खतरे में है । धर्म की कौन कहे? इसलिए सब से पहला कदम यह होना चाहिए कि सब मिल कर इस धर्म को रक्षा करें और भारतमाता को बचायें ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कचार) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों को इन मांगों का समर्थन करती हूं ।

इतने विशाल देश की प्रतिरक्षा के प्रति सरकार को पूर्णतया सतर्क रहना चाहिये ।

मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं, वह देश की पूर्वी सीमा पर स्थित है और वहां देश की सभी महत्वपूर्ण समस्यायें उग्ररूप में मौजूद हैं । नागाओं का उत्पात भी है ओंर पूर्वी पाकिस्तान की शरारतें भी । मेरे राज्य में पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या अधिकृत रूप से घूस पैठ कर रही है । प्रधान मंत्री ने इसके बारे में हमें आश्वस्त किया है कि सुरक्षात्मक कार्यवाही में कोई भी ढ़िलाई नहीं की जा रही है ।

स्वाभावकि है कि कचार होकर सशस्त्र नांगा टुकड़ियों का पहली मई को भाग निकलना बड़ा चिन्ताजनक है । मने कचार जाकर स्वयं परिस्थिति का अध्ययन किया है । मुझे बताया गया है कि ३० अप्रैल को आदिमजातियों के लोगों ने स्थानीय सैनिक अधिकारियों को सूचित किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती ज्योत्सना चन्दा]

था कि कुछ सशस्त्र नागा लुटेरे उनके क्षेत्र में छिपे हुये हैं और पाकिस्तान को निकल भागने की फिराक में हैं। लेकिन कलाइनचेरा शिविर के सैनकि अधिकारियों ने उसपर कोई कार्यवाही नहीं की थी। डिगोखेल शिविर के सैनिक अधिकारियों ने भी उस सूचना पर विश्वास नहीं किया था।

यदि सैनिक अधिकारियों ने सतर्कता दिखाई होती तो सशस्त्र नागा टुकड़ियां बचकर नहीं निकल सकती थीं। इससे यही निस्कर्ष निकलता है कि सैनिक अधिकारी पूर्णतया सतर्क नहीं हैं। यह भी कि केन्द्र और राज्य के गुप्तचर विभागों में सह-कार्य नहीं है।

प्रतिरक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरह बंगाल के नाम पर भी एक रेजीमेंट का नामकरण किया जाना चाहिये। मैं ऐसे नामों को बदलने के पक्ष में नहीं हूं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहानपुर) : आज से एक वर्ष पहले हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी देश से हथियार आदि खरीद सकते हैं। जब से पाकिस्तान को अमरीका एफ-१०४ वायुयान भेंट किया है तब से उनकी वायुसेना भारत की वायुसेना की अपेक्षा अधिक बलवती हो गई है इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। अगर भारत चाहता तो तभी से वह भी वायुयान की खरीद कर सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने यहां ही एच० एफ० २४ वायुयान बनाने का प्रयत्न किया। इसके लिये एक समवाय से संविदा भी किया लेकिन बाद में चलकर कुछ गड़बड़ हो जाने से यह योजना ठप्प हो गई।

लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। और हम भी अपनी वायु सेना को आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित करना चाहते हैं।

जहां तक इनको अपने यहां बनाने की बात है उसमें तो समय लगेगा। यह तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी जानता है कि भारत जैसे अनुन्नत देश में इन वायुयानों का निर्माण करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यह बात मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार ने यह डेढ़ वर्ष का समय क्यों बर्बाद किया।

अभी बताया गया है कि किस प्रकार हमारे सैनिक, जो कि सीमान्त की देखभाल कर रहे थे, सोते रहे और २०० नागालोग भारत की सीमाओं में घुस आये और फिर पाकिस्तान चले गये। क्या यही हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय का काम है।

पश्चिमी बंगाल के पास सीमा की सुरक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाती। पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र को लिखा है कि केन्द्र इस सम्बन्ध में वहां की सरकार की सहायता करे। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार वहां कुछ सेना भेजे ताकि वहां की सुरक्षा ठीक ढंग से हो सके।

यह ठीक है कि गोआ को मुक्त कर लिया गया है लेकिन गोआ में सैनिकों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। वहां कुछ अप्रिय घटनायें घटी हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी जांच की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होंगी।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिर खाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आज लगभग ३० वर्षों के उपरान्त पुनः इस माननीय सदन में आप ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। यह जो रक्षा का प्रश्न है उस पर अनेक प्रकार से अनेक प्रतिष्ठित महानुभाओं के

---

†गूल अंग्रेजी में

विचार सुनने को मिले। मुझे बहुत कुछ कहना था परन्तु मैं समझता हूं कि बहुत सी बातों कही जा चुकी हैं। फिर भी कुछ न कुछ निवेदन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

सेना के संबंध में अभी यहां बहुत सी बातें कही गई। मैं भी समझता हूं कि सेना के लिये जितना भी प्रोत्साहन दिया जाये देश के लिये हितकर होगा। सेना के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सैनिक सब से अधिक आदर के पात्र हैं क्यों कि वे अपने प्राणों को हथेली में ले कर देश की रक्षा के लिये देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाने के लिये तैयार रहते हैं और इस प्रकार भारत का गौरव बढ़ाते हैं। जहां पर अशांति होती है वे शांति की स्थापना करते हैं। हमारे देश के सैनिकों ने जो महान् कार्य इस बीच में किये हैं उन के लिये मैं समझता हूं कि यह विभाग बधाई का पात्र है, और मैं अपने माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने केवल गोआ में ही नहीं, और और स्थानों पर भी, विदेशों में भी, जहां जहां भारतीय सेना भेजने का प्रश्न आया, अपने सैनिकों को भेज कर शांति की रक्षा में सहायता की।

बहुत सज्जन इस में भी आक्षेप करते हैं कि हमारे सिपाही जो हैं वे तो हैं, लेकिन सेना की वृद्धि बहुत उत्तम वस्तु नहीं है। वे समझते हैं कि सेना की वृद्धि में हिंसा का भाव आता है। लेकिन हिंसा का प्रश्न या अहिंसा का प्रश्न सेना की वृद्धि में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि हम लोग अहिंसा को मानने वाले हैं। मुझे स्मरण है कि इसी स्थान पर, इस माननीय सदन में १५ फरवरी, सन् १९२९ को माननीय डा० मुंजे के प्रस्ताव का हमारे नेता पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा अन्य गणमान्य नेताओं ने समर्थन किया था कि यहां सैनिक शिक्षा, मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाये। यह प्रस्ताव तब के विरोधी दल का था। तत्कालीन सरकार ने उस का विरोध किया था। उस समय हम लोगों की यह चुटकी ली जाती थी कि यह लोग अहिंसात्मक बनते हैं और अपने आप को अहिंसावादी कह कर भी मिलिटरी ट्रेनिंग या सैनिक शिक्षा पर बल दे रहे हैं। जब वे लोग यह कहते हैं कि देश में सैनिक शिक्षा होनी चाहिये तो यह उनकी अहिंसा कैसे रही? ऐसी ऐसी बातें कही गई थीं। उस दिन अर्थात् १५ फरवरी को अपने भाषण में अहिंसा की परिभाषा करते हुये मैंने कहा था कि यदि अहिंसा धर्म की रक्षा के लिये हमें हथियार उठाने होते हैं तो वह हिंसा के लिये नहीं है, अहिंसा के लिये है। हम अहिंसा का प्रसार संसार भर में चाहते हैं। हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के सामने नान वायोलेन्स का प्रश्न उठाया था तो उन्होने कहा कि नाम वायोलेन्स होनी ही चाहिये। लेकिन इस से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा के सम्बन्ध में हम को सेना की बात नहीं उठानी चाहिये। यह बातें भ्रम पैदा करती हैं। यह बात सही है कि हमें सेना की आवश्यकता है। हमारे जैसा आध्यात्मिक देश की आशा, शांतिदूत और शांति के सर्वोपरि कर्णधार हमारे प्रधान मंत्री हैं, जो संसार में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। तो हमारे देश में ऐसी सेना की आवश्यकता है कि संसार के कोने कोने में जहां कहीं अशांति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ आदि की ओर से विचार किया जाये कि वहां शांति की स्थापना करना है और वहां सेना भेजनी है, वहां यहां से सेना जाया करे, वहां शांति की स्थापना करे और वहां से हिंसा के तांडव नृत्य को दूर कर के अहिंसा की रक्षा करे। इस प्रकार से अहिंसा की स्थापना के लिये हमें सेना की आवश्यकता है, हिंसा के लिये सेना की आवश्यकता नहीं है।

आज हमारे पड़ोस में या संसार में जहां कहीं भी हम देखें अधिकतर युद्ध की बातें होती हैं और अशांति हो रही है। आज जिन बड़े बड़े शस्त्रास्त्रों का निर्माण हो रहा है वह इस दृष्टि से नहीं हो रहा है कि संसार में शांति की स्थापना की जाय अपितु अन्य फौजों पर आधिपत्य जमाने के लिये संसार में भयंकर शस्त्रास्त्रों का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता है, जैसा कि कई हमारे माननीय मित्रों ने कहा और मैं उनका समर्थन करता हूं कि हमारे देश में

[श्री रणंजय सिंह]

जो हमारी सेना हो वह आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वह यह है कि हम अशांति के लिये नहीं, हम हिंसा के लिये नहीं अपितु अहिंसा के लिये, शांति के लिये अपनी सेना रखते हैं। हम अपनी सेना को इतना सुसज्जित रखें कि कोई भी हमारी सेना पर उंगली न उठा सके और ऐसी धृष्टता न कर सके कि हमारी सेना को निर्बल समझे, वह जहां चाहे बढ़ता चला आये और अधिकार जमाने का साहस करे। आज हमारे यहां जो कुछ हो रहा है वह शांति के लिये ही प्रयत्न हो रहा है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि हमारी सेनायें अभी चढ़ाई कर के बात की बात में काश्मीर को बिल्कुल मुक्त कर लें। और जो चीन वाले हैं उनसे भी हम लड़ाई छेड़ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारी सेना सुसज्जित है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि उसे और भी सुसज्जित किया जाये और उसकी और भी शक्ति बढ़ायी जाये। यह सेना केवल शत्रुओं से लड़ने के लिये ही नहीं है। शांति के समय भी यह हमारे यहां काम करती है जिस काम को अन्य विभाग नहीं कर सकते हैं। मैं अपने सैनिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने संसार में गौरव का स्थान प्राप्त किया है। देश में भी रोहतक में लखनऊ और दूसरी जगहों पर बाढ़ के समय सैनिकों ने बड़ा काम किया। वह इतने साधन सम्पन्न हैं कि वे इस तरह के काम कर सकते हैं जिनको और लोग नहीं कर सकते हमारे भाई ने कहा कि सेना का महत्व बहुत है। हम भी मानते हैं कि हमारे पास आधुनिकतम हथियार रहें लेकिन हमारी सेना किसी को दबाने के लिये नहीं है।

विद्या विवादाय धनम्मदाय, शक्तिः परेषाम परिपीड़िकाय,
खलस्य साधोःविपरीत मेतत्, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय।

दानी विद्या विवाद के लिये है, धन घमंड करने के लिये है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिये है यह उनके लिये सत्य है जिनके विचार खलों के होते हैं। लेकिन जिनके विचार अच्छे हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिये है, धन दान के लिये है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिये है। तो हमारे देश की यही परम्परा रही है। हमारे देश का इसी लिये संसार में गौरव रहा है कि हमारी यह परम्परा रही और इसी कारण आज हमारी सेना ने संसार में गौरव का स्थान स्थान प्राप्त किया है।

मेरा सुझाव है कि हमारे सैनिकों को शुद्ध भोजन मिलना चाहिये। आजकल शुद्ध घी नहीं मिलता। शुद्ध दूध नहीं मिलता। उनके लिये शुद्ध खाद्य पदार्थों का प्रबन्ध किया जाये। शुद्ध भोजन से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनके विचार भी अच्छे होंगे।

सेना में अनुशासन बहुत अच्छा है जो कि अन्य लोगों के लिये अनुकरणीय है। हमारी सेना हमारे लिये आदर्श है। उनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सोलजर्स बोर्ड के काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे सैनिक अपने काम से निवृत्त हो कर ग्रामों में जब जाते हैं तो बड़े लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारी सेना का काम केवल लड़ाई करना ही नहीं है बल्कि मुल्क की सेवा करना भी है। उन्होंने जो हमारे देश में स्थान स्थान पर सेवाएं की हैं वे और लोगों द्वारा नहीं हो सकतीं।

हमारी सेना के बारे में यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

युक्तियुक्त पुमादेयम्, वचनम् बालकादपि

यानी जो युक्तियुक्त बात हो वह बालक की भी मान लेनी चाहिए। इसके अनुसार जो भी भाषण हुए हैं उन पर विचार किया जाए और जो बातें ठीक हों उन पर पूरा ध्यान दिया जाए।

हमारी सेना के सम्बन्ध में जो डिमांड है उसका तो मैं समर्थन करता ही हूँ। मैं तो समझता हूं, जैसा कि श्री रघुनाथ सिंह जी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा हमें अपनी सेना की शक्ति और बढ़ानी

चाहिए और हवाई जहाज आदि सामान उसके लिए मंगाना चाहिए। मैं उनका समर्थक हूं। उन्होंने जो बातें बतलाई हैं वे आंकड़े देख कर ही बतलाई हैं। हमारी सेना की जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी ही संसार में शान्ति की स्थापना होगी। हमारी सेना रक्षा के लिए है और अहिंसा के सिद्धान्त पर चलने वाली है। हम किसी का राज्य नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते हैं कि संसार में आज जो गड़बड़ी है उसको दूर करने में हमारी सेना सहायक सिद्ध हो।

हमारी सेना बहुत अच्छी है और इसमें अनुशासन की भावना भी काफी है। यद्यपि मैं समझता हुं कि हमारी सेना इस प्रकार की बातों से दूर है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि सेना पर कम्युनलिज्म और कम्यूनिज्म का प्रभाव न पड़े। मैं चाहता हूं कि सेना की उन्नति के लिए जो कुछ किया जा सकता है किया जाए ताकि उसकी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो। हमारी सेना शक्तिशाली होगी तो देश की सेवा अधिक अच्छी तरह कर सकेगी और संसार में शान्ति स्थापना भी कर सकेगी। उस अवस्था में संसार समझेगा कि यह देश फिर अपने पुराने गौरव को प्राप्त हो गया है जब कि इसके लिये कहा जाता था :

एतद्देश प्रसूतस्य समाशादग्र जन्मनः,
स्वं स्वं चरित्रम् शिक्षेरन् पृथिव्याम् सर्वमानवाः।

यहां लोग बाहर से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार फिर देश का गौरव का स्थान प्राप्त होगा हमारी सेना आज भी संसार में शान्ति स्थापना का काम कर रही है और अधिक शक्तिशाली होगी तो और भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी। आज जो संसार में शस्त्रों की होड़ चल रही है उसका कारण लोगों की विचारधारा ठीक न होना है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सैनिकों की विचारधारा ठीक रहे। हमारे सैनिक अभी भी अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छी विचारधारा रखते हैं। इस दिशा में उनको और भी प्रगति करनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, अगर मैं उनका जवाब दूं तो उसमें बहुत समय लग जायेगा और अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अन्त में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया जाए और उनको उत्साहित किया जाए ताकि वे देश की और संसार की सेवा कर सकें।

अन्त में मैं रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह इतना काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि सैनिकों की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। ऐसा करने से लाभ ही होगा और यदि ऐसा होगा तो हमारी सेना दुनिया के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। आज हमारा देश पिछले १५ वर्षों से स्वतंत्र है। यह प्रसन्नता की बात है कि सेना में भर्ती के समय किसी जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि व्यक्ति की शारीरिक सुघड़ता और उनकी शिक्षा को ही महत्व दिया जाता है।

जम्मू तथा काश्मीर के भारत के विलय के समय सेना के नौजवानों एवं पदाधिकारियों ने जो बढ़िया कार्यवाही की है एवं उत्तम व्यवहार दिखाया है वह चिरस्मणीय है। साधारण जनता के साथ इन सैनिकों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और सहायताजनक था। इन सैनिकों ने अपना स्थान तक इन भूखे नागरिकों को दे दिया है। और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा की है।

शारीरिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देश ने जो उन्नति की है, वह सेना में भी दिखाई देती है और सराहना योग्य है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

इस समय ऐसा कोई क्षेत्र या समुदाय नहीं है जिसमें से सेना में भरती न होती हो। अब भारत का प्रत्येक नागरिक सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हो सकता है यदि उसमें आवश्यक योग्यतायें हों। इस समय भरती विशेष वर्गों या प्रदेशों तक सीमित नहीं है और जैसा कि पहले हुआ करता था। राष्ट्रीय एकता का भी सब से अच्छा नमूना हमें सेना में मिल सकता है। इसमें जाति और धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होता।

काश्मीर में ब्रिगेडियर उस्मान, कर्नल राय, मेजर शर्मा और कैप्टन जादू जैसे शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन के अतिरिक्त अनेक जवानों में भी अपने जीवन का बलिदान दिया था।

काश्मीर में हमारी सशस्त्र सेनाओं का कार्य बहुत अच्छा रहा है। वे देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं और उन्होंने यह दिखा दिया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वे ऊंचा से ऊंचा बलिदान करने में समर्थ हैं। उनके असैनिक आबादी के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।

हमारी सेना ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और उसने हमेशा शान्ति की रक्षा के लिए प्रयत्न किए हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री के इस वक्तव्य से कि यदि हमारे सीमान्तों पर कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो हमारी सशस्त्र सेनायें उसका पूरा मुकाबला करेंगी, सामान्य जनता और विशेषकर सशस्त्र सेनाओं में विश्वास की भावनायें उत्पन्न हुई हैं।

प्रतिरक्षा पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण की आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं होनी चाहियें। मुझे आशा है कि ऐसा किया जा रहा है। हमारी सशस्त्र सेना को अच्छे सामान से सुसज्जित किया जाना चाहिये। और हमें सेना को सामान स्वयं तैयार करने के लिए रुपया देना चाहिये। यह नौसेना और वायुसेना पर भी लागू होता है। आशा है प्रतिरक्षा मंत्रालय नौसेना को आधुनिक बनाने पर भी ध्यान देगा।

सीमान्त प्रदेशों में नियुक्त सैनिकों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। कई बार उनको ऊंचाई पर और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

छावनियों के प्रशासन को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहियें।

†श्री प्र० चं० बरूआ (शिवसागर) : भारत के ९००० मील के सीमान्त में से लगभग एक तिहाई केवल आसाम के हिस्से में आता है। इसलिए सीमा की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में, आसाम सब से आगे होना चाहिये और मंत्रालय का एक तिहाई व्यय और ध्यान आसाम को मिलना चाहिये। वहां एक मुख्यालय स्थापित करना चाहिये, जिसमें वायु सेना भी होनी चाहिये, ताकि वह बाहर से साज-सामग्री की प्रतीक्षा किये बिना हमारे सीमान्तों की तुरन्त देखभाल कर सके।

चीन के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में सतर्क रहते हुए सरकार को भारत चीन सम्बन्धों के प्रश्न पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिये और हमें अपनी तटस्थता की नीति पर कायम रहना चाहिये। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अल्पकालीन एवं दीर्घ-कालीन उपाय करने चाहिये। अल्पकालीन उपाय ये हैं कि हमें चीनियों से हर तरह से असहयोग करना चाहिये, तिब्बत के साथ व्यापार समझौता नया नहीं करना चाहिये और बुरे से बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। दीर्घकालीन उपायों के सम्बन्ध में यह पग उठाने आवश्यक हैं : सीमाओं में अच्छे संचार साधन कायम किये जायें, सड़कें और पुलें बनाई जायें, हवाई अड्डे और पट्टियां

†मूल अंग्रेजी में

बनाई जायें, सेना को आधुनिक शस्त्र दिये जायें, सीमान्त में रहने वाले लोगों की अर्थ व्यवस्था में सुधार किया जाये और उन लोगों को निकाल देना चाहिये जो देश के प्रति वफ़ादार नहीं हैं।

यद्यपि हम पंचशील के निर्माता हैं और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, फिर भी हमें पंचशील के नारे को इतना नहीं दुहराना चाहिये कि हमें कायर समझा जाने लगे।

पाकिस्तान के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम चीन की समस्या हल कर लें तो पाकिस्तान की भी हल हो सकती है। पाकिस्तन से आसाम में अनधिकृत प्रवेश में वृद्धि हो रही है जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। मेरा सुझाव है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले हमारे सीमान्तों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना को सौंप देना चाहिये। वहां असैनिक पुलिस नहीं होनी चाहिये। मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अचल सिंह (आगरा): उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्ज़ रक्षा मंत्री जी की तरफ से पेश की गई हैं, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं।

रक्षा मंत्रालय का महकमा बहुत आवश्यक महकमा है। हमारे देश को आज़ाद हुए मुश्किल से पन्द्रह वर्ष का अर्सा हुआ है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला बोल दिया। उस वक्त हालत बड़ी नाज़ुक थी। लेकिन हमारे तजुर्बेकार और पैट्रियोट कमांडर और मंत्रीगण थे उन्होंने फौरन हवाई जहाज़ों के ज़रिये से फौजों को काश्मीर में उतारा और पाकिस्तानी हमलावरों से देश की रक्षा की। जिस मुस्तैदी और बहादुरी के साथ वहां पर इन्होंने अपने करतब दिखाये, उनकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान की फौजों को पीछे हटना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सीज़ फायर उस वक्त न हुआ होता तो जो हमारा काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास आज है वह भी वापस ले लिया गया होता। लेकिन यू० एन० ओ० की वजह से वह चीज़ नहीं हो सकी और जो काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया था वह अब भी उसी के कब्ज़े में चला आ रहा है। वह हिस्सा हमारा है और हमें मिल कर रहेगा। पाकिस्तान यू० एन० ओ० में तरह तरह की बातें अपने नुमाइन्दे ज़फरुल्ला खां की मार्फत रख रहा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई थी उसमें जब यह मसला पेश हुआ तो बड़ी योग्यता और बड़ी समझदारी के साथ हमारे रक्षा मंत्री जी ने मामले को पेश किया जिसके फलस्वरूप श्री ज़फरुल्ला की सब दलीलें बेकार हो गईं। और उन्होंने बतला दिया कि पाकिस्तान वाले ज़फरुल्ला खां फुजल की बातें करते हैं, उसमें कोई सार नहीं है, जैसा कि हमारा क्लेम है, और वे "उल्टा चोर कोतवाल को डाटे" वाली कहावत पेश कर रहे हैं। हमारी जो फौजें हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम दिखाया। सिर्फ इसी मौके पर नहीं, इसके बाद हैदराबाद को चन्द घंटों में फतेह किया। उसी तरीके से गोआ, दमन और ड्यू, जो कि १२ या १४ वर्षों से काफी गड़बड़ी में पड़े हुए थे, उन को हमारी डिफेन्स फोर्सेज ने अपनी हिम्मत और मुस्तैदी के साथ चन्द घंटों में फतेह किया। हमारी फौजें न सिर्फ इस वक्त बल्कि पुराने समय से बड़ी बहादुर और दिलेर होती रही हैं। अंग्रेजों को ऊंचा उठाने में पहली लड़ाई में और दूसरी लड़ाई में, हमारी फौजों ने बहुत हिम्मत दिखाई और नाम पैदा किया। अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष की फौजों द्वारा अपने इंग्लैंड और योरप की रक्षा की। उस मे हमारे बहादुर जवानों ने जिस वीरता से काम किया, साहस से काम किया, उस से तमाम दुनिया में लोग हमारे जवानों की तारीफ करते हैं।

[श्री अचल सिंह]

इस के अलावा जब कभी देश पर कोई संकट आता है, बाढ़ें आती हैं, या कोई मुसीबत आती है, तो फौरन हमारे जवानों से रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है, और वे पहुंच कर संकट को दूर करते हैं। जब कभी सिविल लाइफ में बदउन्वानी होती है या गड़बड़ होती है तो फौरन मिलिटरी को बुलाया जाता है और वे बड़ी होशियारी से स्थिति को ठीक करते हैं ।

इस के अलावा हमारे रक्षा मंत्रालय ने और भी बड़े बड़े काम किये हैं। उन्होंने बहुत से कारखाने खोले हैं। हवाई जहाज, टेंकर, ट्रक्स और बिजली के सामान के लिये बंगलौर में जो कारखाने चल रहे हैं उन में बड़ी निर्भीकता, हिम्मत और बहुत ही अच्छी तरह से काम होता है। यह काम फैक्ट्रीज का है, लेकिन जिस ढंग से जिस चीज को रक्षा मंत्रालय ने अपने हाथ में लिया है वह प्रशंसा के योग्य है । आज कई प्रकार के हवाई जहाज बने हैं, ट्रैक्टर बने हैं, ट्रक्स बने हैं जिन से जो हमारा लाखों रुपया विदेशों को जाता था वह बच गया ।

इस वक्त जब कि देश के सामने चीन का और पाकिस्तान का हमला हो रहा है, याद उन को बदउन्वानियां हो रही हैं, उन का मुकाबला करने के लिये हमारी फौजों को मुस्तैदी और संगठित होना चाहिये। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने बतलाया, हम किसी सूरत से दूसरों से कम नहीं हैं, हम तैयार हैं कि हम किसी हमलावर को अपने देश की तरफ नजर उठा कर न देखने दें। अगर कोई देखेगा तो हम उस का जवाब देंगे। इसलिये हमारी फौजों को और भी मजबूत होना चाहिये।

एन० सी० सी० की जो ट्रेनिंग चल रही है हमारे कालेजों और स्कूलों में, उस के द्वारा हम लाखों नौजवानों, बालकों और बालिकाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन्होंने काफी उन्नति की है । जिन लोगों ने ट्रेनिंग पाई है उन की तादाद १४, १५ लाख तक है, लेकिन मैं कहूंगा कि डिफेंस और रक्षा की ट्रेनिंग, एन० सी० सी० की ट्रेनिंग तमाम स्कलों और कालेजों में कम्पलसरी होनी चाहिये। सिर्फ रक्षा के वास्ते ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के वास्ते भी यह जरूरी है । जिन युवकों और युवतियों को यह ट्रेनिंग मिलती है वे काफी डिसिप्लिड हो जाते हैं और उन में अपने देश के प्रति प्रेम व हमदर्दी हो जाती है । वे अपने कर्त्तव्य को समझते हैं और जानते हैं कि उस कर्त्तव्य को किस तरह से पूरा करना है । इस-लिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह ट्रेनिंग तमाम स्कूलों और कालेजों में कम्पल्सरी कर दी जाये ताकि अगर कभी कोई मौका आये तो हमारा देश तैयार रहे। हम लोग इस को सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस कहते हैं। अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाये तो उन में से हीहम लोगों को फौजों में भरती कर सकते हैं। उन को इस की ट्रेनिंग दी जाये और जब जरूरत पड़े तो वे तैयार मिलें और अपने देश के बचाव के लिये वे हमेशा मुस्तैद रहें।

यहां पर एक प्रश्न मैं रखना चाहता हूं केंटोनमेंट बोर्ड्स का। कैन्टोनमेंट बोर्ड्स में अभी तक मैजारिटी नामिनेटेड मेम्बर्स की है । एलेक्टेड मेम्बर्स की वहां पर माइनारिटी है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार किया जाये। दूसरे कैन्टोनमेंट्स में अभी तक बहुत सी जमीनें पड़ी हैं। उन के बारे में अब तक कोई निश्चय नहीं किया गया है । एक एक बंगले के पीछे १०, १२, १५ एकड़ जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। उन में काफी मकानात बन सकते हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट को उन से काफी आमदनी हो सकती है । साथ ही काफी लोग वहां पर बस भी सकते हैं। इस देश में जब आज ऐकोमोडेशन की इतनी कमी है,

तो इस तरह से वह किसी हद तक दूर हो सकती है । मैं चाहूंगा कि कैन्टोनमेंट्स में जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं उन के बारे में मंत्री जी कोई बात सोचें । पिछले समय में जब श्री महावीर त्यागी मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस विषय पर कुछ अपने विचार ज़ाहिर किये थे । लेकिन बाद में उन विचारों को स्थगित कर दिया गया । मैं चाहूंगा कि उन बातों पर फिर गौर किया जाये ।

हमारे रक्षा विभाग की तरफ से अक्सर नुमाइशें होती हैं । इन नुमाइशों का होना बहुत आवश्यक है ताकि देश की जनता को मालूम हो कि हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या क्या प्रगति की है और क्या कमियां हैं और वे किस तरह से पूरी हो सकती हैं । अभी दिल्ली में इंडस्ट्रीज फेअर हुआ था । हमारा रक्षा विभाग डैमेस्कस में भी शामिल हुआ नुमाइश में, सिंगापुर में भी शामिल हुआ और कलकत्ते में भी शामिल हुआ । इस तरह की नुमाइशें होने से डिफेंस के लोगों की बड़ी हिम्मत अफजाई होती है, और उस से उन का फायदा होता है ।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । सिर्फ यह कहूंगा कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उन की हिम्मत अफजाई करनी चाहिये और हर तरह से उन को सम्मानित करना चाहिये क्योंकि देश की रक्षा उन के ही हाथ में है । इस वक्त चाइना और पाकिस्तान का मामला हमारे सामने है । वह हर तरह से ऐग्रेसर होते जाते हैं और हमारे लिये काफी परेशानी पैदा करते जाते हैं । अगर हमारे हिन्दुस्तान की फौजें बिल्कुल मुकम्मिल हों, तैयार हों, तो कोई वजह नहीं है कि वे उन का मुकाबला न कर सकें । इस के लिये मैं कहूंगा कि उन को ज्यादा से ज्यादा तरबिअत दी जाये, हिम्मत अफजाई की जाये, जिस से वे अपने देश की रक्षा कर सकें, उसको सुरक्षित रख सकें ।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : मैं भारत की सशस्त्र सेनाओं को उन की उल्लेखनीय उन्नति पर बधाई देता हूं । उन्होंने देश के भीतर तथा बाहर प्रशंसनीय कार्य किया है ।

जहां तक हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का सम्बन्ध है, यदि हम भारतीय समुद्र पर गश्त की व्यवस्था कर सकें तथा इसे सुरक्षित रख सकें, तो हम तीन दिशाओं में अपनी सुरक्षा को पुनिश्चित कर सकते हैं । इसके लिए नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी नौसेना को सुदृढ़ तथा आधुनिक प्रकार की बनायें ।

उत्तरी सीमा को पर्याप्त रूप से चौकसी रखना होगा । वास्तविक खतरा चीन से है जिसके पास बहुत अधिक संसाधन तथा जनशक्ति ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उसने भारत को अपना निशाना बना लिया है तथा पहले ही उस देश ने हमारे क्षेत्र के एक बड़े भाग को हड़प कर रखा है । हमें इस बारे में आलस्य से काम नहीं लेना चाहिये और अपनी प्रतिरक्षा नीति निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये । चीन को पाकिस्तान, बर्मा और नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों की चिन्ता नहीं है । जब तक उसका मुकाबला भारत से है, वह इन देशों को हाथ नहीं लगा सकता ।

जो लोग हमारे सीमान्त क्षेत्रों पर बसे हुए हैं, वे सिन्ध-गंगा मैदान के लोगों से भिन्न प्रकार के हैं । उनको अपनी भाषा और संस्कृति है । हमें उन्हें उचित रूप से समझना होगा । पिछले आठ सालों से नागालैंड और मनीपुर में लड़ाई जारी है । हमारे सशस्त्र बलों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रिशांग किशिंग]

वहां अच्छा काम नहीं किया और उनके व्यवहार की प्रशंसा नहीं की जा सकती। इस का कारण यह है कि उन्होंने उन की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के बारे जानकारी प्राप्त नहीं की। नेफा नागालड तथा अन्य पूर्वी क्षेत्रों में वे मित्र और शत्रु में भेदभाव करने में असमर्थ हैं। सैनिकों और असैनिक जनसंख्या में अधिक अच्छे सम्बन्धों के कायम करने की इस समय बहुत आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में नियुक्त सेना के कर्मचारियों को उन क्षेत्रों के लोगों के बारे में तथा उन के रिवाजों तथा धार्मिक भावनाओं आदि के बारे में अवगत कराया जाये। उनमें इस समय जो आशंकायें पाई जाती हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

हमें अपने सशस्त्र बलों को जंगलों में युद्ध के तरीकों में प्रशिक्षण देना चाहिये। "आसाम राइफल्स" जसी संस्थाओं को सुदढ़ किया जाये। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाये ताकि वे भी हमारे राष्ट्रीय सीमांत की सुरक्षा कर सकें।

सेना के पदाधिकारियों की भरती सामान्यतया धनिक वर्ग में से की जाती है जबकि सैनिकों की भरती जनसाधारण में से की जाती है। इस प्रकार को व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए अंग्रेजी का ज्ञान कसौटी नहीं माननी चाहिये।

विभागीय पदोन्नतियों के मामले में राजनीति को प्रवेश नहीं करने देना चाहिये। सेना में अनुशासन का कायम रखना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए सेना को राजनीति से अलग रहना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सेना में होने वाले अपव्यय का उल्लेख है। भूमि और मकानों के निपटारे में बिलम्ब से देश की १० लाख रुपये की हानि हुई है। ट्रैक्टरों के प्रयोग न किये जाने से १·२० करोड़ रुपये की हानि हुई है इत्यादि। इस प्रकार के अपव्यय को रोका जाना चाहिये।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : प्रतिरक्षा सेवाओं सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के शुरू में कहा गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अपव्यय के बारे में स्थिति इस वर्ष और भी बिगड़ गई है। यह नहीं हो सकता कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस प्रकार की आलोचना से प्रसन्नता होती है। उस मंत्रालय में सारे गैर-जिम्मेदार और अक्षम कर्मचारी नहीं हैं। किन्तु क्या लेखापरीक्षा प्राधिकारी ने सविस्तार इस मामले की छान-बीन की है और क्या मंत्रालय की कठिनाइयों को समझा है, क्योंकि प्रतिरक्षा आयोजन की स्थिति कई ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर होती है जो बदलती रहती हैं। मेरा सुझाव है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय, प्रतिरक्षा मुख्यालय, वित्त मंत्रालय और लेखापरीक्षा विभाग के पदाधिकारियों की एक समिति बनानी चाहिये, जिस से कुछ संसद् सदस्य भी सम्बद्ध हों। यह समिति प्रतिरक्षा आयोजन के सम्बन्ध में विचार करे और प्रतिरक्षा आयोजन तथा वित्तीय औचित्य दोनों दृष्टियों से उचित आधारभूत मानदंड निर्धारित कर सके। इससे लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली बहुत सी आपत्तियां हल हो जायेंगी।

सिद्धांत रूप से मैं समझता हूं कि रूस से विमान खरीदने में कोई हानि नहीं है यदि वे हमारे लिये उपयुक्त हैं और वे अमरीकी विमानों से सस्ते हैं। परन्तु हम इन्हें खरीदते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हमें ब्रिटेन तथा अमेरिका से जो गोपनीय उपकरण प्राप्त हुए हैं उन की सूची रूसियों को न दी जाये। दूसरे हमें यह भी देखना चाहिये कि जो

---

†मूल अंग्रेजी में

रूसी यहां आयें वे विध्वंशकारी कार्यवाहियों में भाग न लें और हमारे भेद चीनियों को न प्रकट करें और न ही रूसी हमारे रूपये से विध्वंशकारी कार्यवाहियां करें ।

जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें 'एवरों' विमानों के सम्बन्ध में केवल दो लाइनों का उल्लेख है । हमारी धारणा तो यह थी कि सरकार उनका निर्माण शुरू करेगी । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर प्रकाश डालें । लोक सहायक सेना तो एक बेकार सेना है उसे जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाय अच्छा है । उसके लिये जो धन रखा गया है उसे किसी अन्य उपयोगी काम पर खर्च कर लिया जाये ।

पंजाब सरकार मनाली में हिमालय पर्वतारोहण संस्था की स्थापना कर रही है । उत्तर-प्रदेश सरकार को भी इस प्रकार की संस्था स्थापित करने के लिये कहा जाये । हमारे भूतपूर्व रजवाड़ों की सेनाओं के सेवानिवृत्त हुए सैनिकों से मंहगाई भत्ता इत्यादि के मामले में बड़ा अनुचित व्यवहार हो रहा है । उनकी शिकायतों को दूर किया जाना चाहिये ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा भारी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

मैं रक्षा मंत्रालय की जो डिमांड्ज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री जी को उन बयानात के लिये बधाई देना चाहता हूं जिन में उन्होंने निहायत वाज़य तौर पर कह दिया है कि भारतवर्ष किसी सूरत में भी चीन या पाकिस्तान के पास जो इलाके उसके हैं उनको नहीं रहने देगा, उनको वापिस लेगा । हमारी फौज चाहे कम हो, चाहे हमारी जल और वायु सेना कम हो, लेकिन उनके जो कारनामें हैं, वे सुनहरे हरूफ में लिखे जायेंगे । इन तीनों शाखाओं में से जिस किसी शाखा को जहां कहीं भी भेजा गया है, उसने निहायत ही अच्छा काम किया है । चाहे उसको लड़ाई के लिये गोआ में भेजा गया हो या किसी दूसरे काम के लिये भेजा गया हो, जो कारनामे उसके रहे हैं, वे एक नुमायां हैसियत रखते हैं । हमारी सेना को पीस मिशन पर भी भेजा गया है, कांगो में और लाओस में, वहां पर भी उसने अपने आप को उन्हीं हालात के मुताबिक तबदील कर लिया और इस तरीके से वहां पर बरताव किया कि दुनिया वाह वाह करके रह गई । अगर गवर्नमेंट को सिविल साइड में फौज की जरूरत पड़ती है, सिविल आथोरिटी की मदद करने के लिये फौज की जरूरत महसूस होती है, तो उसमें भी वह अपने आप को एडाप्ट उन हालात के मुताबिक कर लेती है जो कि बहुत ही प्रशंसा की बात है ।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज महज़ हमारा काम फौज ही से नहीं चल सकता है । यह ठीक है कि हमारी फौज काफी है और कर्त्तव्य-परायण भी है । लेकिन अगर हम इसको बढ़ाना चाहें पैसा दे कर, तो सारे का सारा बजट भी अगर उस पर खर्च कर दिया जाए, तो भी वह काफी नहीं हो सकता है । मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं । मेरे से पहले गालिवन सहारनपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे और उनका भाषण सुन कर मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद वह गर्मी के दिनों में कहीं सैर करने के लिये पहाड़ों पर जा रहे हों या फिर कोई इलैक्शन स्पीच कर रहे हों । मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गर्मी के दिनों में सैर करने के लिये चले और तीन महीने में तिब्बत को और चीन को भी फतह करके वापिस आ गए । गालिबन उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या मुश्किलात हैं । अगर वह मेरे साथ १८,००० फुट की बुलन्दी पर चलें और उनको बरफ से हो कर गुज़रना पड़े तो शायद उनका दम फूल कर रह जायेगा । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहां से उठे, वहां पर पहुंच गए और फतह करके चले आए । उसके लिये तैयारी की जरूरत

[श्री हेम राज]

है और तैयारी भी सिर्फ फौज की ही नहीं बल्कि और कई चीज़ों की। चाहे उपज की जरूरत हो, चाहे सामान की जरूरत हो, चाहे और चीज़ों की जरूरत हो, इनका पूरा होना बहुत आवश्यक है और इनके पूरा हुए बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। सब से ज्यादा जरूरत अच्छी सड़कों की पड़ती है। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, हमारी हालत क्या है? आज हालत ऐसी नहीं है कि सड़कें बन कर तैयार हो गई हों। सड़कों की आज भी बड़ी कमी है। बिना सड़कों के कैसे हम कह सकते हैं कि एक दम हमला कर दिया जाए।

जहां तक बोर्डर रोड्ज़ का ताल्लुक है, मैं नहीं जानता हूं कि किस मंत्रालय को इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराऊं। बोर्डर विंग्ज़ की रोड्ज़ का जहां तक ताल्लुक है, एक बोर्ड है जिसके अध्यक्ष तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उपाध्यक्ष शायद हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उसका बजट चलता है ट्रांस्पोर्ट और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ की सड़कों का जहां तक ताल्लुक है, उनका काम शायद होम मिनिस्ट्री के तहत होता है। कौन इनके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह मैं नहीं जानता हूं। नार्थ की जो सरहद है और वहां पर जो सड़कें बननी हैं, उस काम को आज आपने पी० डब्ल्यू० डी० के हवाले किया हुआ है। जरूरत इस बात की है कि वहां की जो सड़कें हैं, उनको बनाने की जिम्मेदारी बोर्डर रोड विंग मिलिट्री के सुपुर्द कर दे और अगर ऐसा नहीं करना है और पी० डब्ल्यू० डी० से ही यह काम करवाना है तो वह तो उसी मद्धम रफ्तार से चलेगा, उसी बेढब तरीके से चलेगा, जिस तरह से चला करता है और आपका काम नहीं बन सकेगा।

मैंने अर्ज़ किया है महज़ फौज से ही आपका काम नहीं चल सकता है। हम चाहे जितनी शक्ति इस पर लगा दें, चाहे सारे का सारा बजट लगा दें, तो भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि सैकिंड लाइन आफ डिफेंस निहायत जरूरी है। जो इस दिशा में प्रगति हुई है, चाहे वह टैरीटोरियल आर्मी हो, चाहे नैशनल केडेट कोर हो, चाहे आग्ज़िलरी केडेट कोर हो और चाहे लोक सहायक सेना हो, बहुत कम हुई है। अभी मेरे टेहरी गढ़वाल के भाई बोल रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोक सहायक सेना के लिये ६६ लाख रुपया रखा है करोड़ नहीं। मैं तो समझता हूं कि यह जरूरी है। यह इसलिये जरूरी है कि वारडर एरिया में हर एक को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। वहां के लोगों की हम आपस में बातचीत नहीं समझ सकते। मेरे यहां जो इस्पिती का इलाका है वहां के लोगों की बातचीत मैं नहीं समझ सकता और वे लोग मेरी बात नहीं समझ सकते। तो जैसा हमारे भाई रिशांग किशिंग ने कहा, मैं भी कहता हूं कि जो जवान उन इलाकों में भेजे जाएं उनको वहां के लोगों की जबान सिखाई जाए और वहां के लोगों के रहन सहन के तरीकों की ट्रेनिंग दी जाए। हमारे भाई रिशांग किशिंग ईस्ट से आते हैं और मैं वेस्ट से आता हूं लेकिन दोनों तरफ हालत एक ही जैसी है। मेरा तो ख्याल है कि इन इलाकों के सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी वक्त जरूरत आ पड़े तो आप उनको इस्तैमाल कर सकें।

आपने कहा कि एन० सी० सी० में सात लाख कालिज के लड़के दाखिल हो सकते हैं लेकिन आपने इन्तिजाम ४ लाख के लिये ही किया है। इसी तरह से जो आपके जूनियर डिवीजन हैं उनके लिये ३० लाख एलिजिबिल विद्यार्थी हैं लेकिन आपने इन्तिजाम १४ लाख के लिये ही

किया है यानी ५० परसेंट के लिये। मैं समझता हूं कि इनमें ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को लेना चाहिये ताकि उनमें डिसिप्लिन आए। आप देखते हैं कि जिन कालिजों में एन०सी०सी० और आई०सी०सी० हो गई है उनमें डिसिप्लिन ज्यादा हो गया है और वहां हड़तालें नहीं होतीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा यंग मैन को इन में दाखिल होने दें। आप कहते हैं कि हम इसके लिये कांस्टीट्यूशन नहीं बदल सकते। तो मेरा कहना है कि जो यंग मैन खुद आना चाहते हैं उनको तो दाखिल किया जाए ताकि यह आपकी सैकिंड लाइन आफ डिफेंस बन सके।

यहां पर चर्चा चल रही थी कि फौज में जाति पांत की बात न रहे। जहां तक मुझे मालूम है, आपने एअरफोर्स में तो वह क्लाज निकाल दिया जिसमें क्लास बतलाया जाता था और जिसमें कास्ट आ जाती थी और गालिबन यह चीज नैवी में से भी निकाल दी गई है लेकिन फौज में अभी कायम है। आपके रेजीमेंटों के नाम जातियों पर पड़े हैं। आज आप जब नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं तब तो आपको इन रेजीमेंटों के नाम नेशनल हीरोज जैसे शिवाजी या राणा प्रताप आदि के नामों पर रखने चाहिये क्योंकि ऐसा करने से नेशनल इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरफ ध्यान दिया जाएगा।

आपका डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है और हड़तालें भी नहीं हो रही हैं और कम से कम दिन जाया हुए हैं। और जो स्पेयर मैशिनरी थी वह भी काम में आने लगी है। इस बारे में मैं यह अर्ज करना चहाता हूं कि आप गजटेड आफिसर्स को काम सीखने के लिए बाहर भेजते हैं। अगर उनके साथ साथ आप उन यगं मैन को भी बाहर भेजें जो कि एफ एस सी या बी एस सी पास करके आते हैं ताकि वे भी बाहर जाकर हुनर सीख सकें और यहां आकर बेहतरीन चीजें बना सकें।

आपका जो सोल्जर्स, सेलर्स एंड एअरमैन्स बोर्ड है उसके अन्दर जो एक्स सरविस मैन हैं और जो सिविलियन हैं उनकी सर्विस की परमानैनसी का सवाल बहुत देर से चल रहा है। परसों सवाल के जवाब में आपने कहा था कि उनकी सरविस को परमानेंट करने का मामला जेरे गौर है। मैं समझता हूं कि यह काम जल्दी होना चाहिए। मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी सरविस उस दिन से काउंट की जानी चाहिए जिस दिन से ये लोग इस बोर्ड में आए हैं।

लैंड्स और कैनटोनमेंट्स के बारे में आपने फैसला किया है कि चाहे वह आपकी जमीन हो, या स्कूल हों या अस्पताल हों उनको आप न तो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और न बेचेंगे। जो आपका कांस्टीट्यूशन है उसके मुताबिक इन एरियाज की प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी तो आपने ली है लेकिन उससे आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते। आप कहते हैं कि आपके पास उसके लिए रुपया नहीं है। में तो कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया फौज पर खर्च होना चाहिए। तो आप कैनटोनमेंट एरियाज में सिर्फ प्राइमरी शिक्षा देते हैं और हायर सैकिंडरी शिक्षा नहीं देते। अब आप देखें कि पंजाब में मिडिल तक तो हाल में शिक्षा मुफ्त कर दी गयी है और लड़कियों के लिए दसवीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त है। आपने कैनटोनमेंट स्कूल ले रखे हैं उनमें यह नहीं हैं। न तो आप उन स्कूलों को स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और न यह इंतिजाम खुद करते हैं। चोलीवास एक कैनटोनमेंट स्कूल का ऐसा मामला आपके सामने आया था। उसको आपने मंजूर नहीं किया और टर्न डाउन कर दिया हालांकि स्टेट गवर्नमेंट उसको लेने को तैयार है। मैं समझता हूं कि इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और मुख्तलिफ जगहों के हालात के मुताबिक फैसला किया जाए।

[श्री हेम राज]

जो एक्स सर्विस मैन हैं उन के रिहैबिलिटेशन का सवाल है। आपकी रिपोर्ट से पता चलता है कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। इन लोंगों की तादाद लाखों तक पहुंच गयी है। लेकिन आपके फिगर बतलाते हैं कि आपने ९१५० को सन् १९६१ तक में गवर्नमेंट सर्विस में एम्पलायमेंट दिलवायी और ७३६ को प्राइवेट कारखानों में पता नहीं इस रफ्तार से यह काम कब पूरा हो सकेगा।

जो आदमी सन् १९५० में पेंशन चले गए हैं उनके पेंशन के सवाल आपके सामने हैं। आपने कहा था कि उनको १ अप्रैल सन् १९५८ से पेंशन मिलने लगेगी। कुछ को मिलने लगी है और बहुत सारों को नहीं मिली है। बहुतों का फैसला नहीं हुआ है। बहुत से केसेज रेस्टोरेशन आफ पेंशन और एल टी के पड़े हुए हैं उन का आज तक फैसला नहीं हो रहा है। न उनको पेमेंट हो रहा है। इन का फैसला जल्द होना चाहिए। ये लोग आपके गांव गांव में प्रचारक का काम करते हैं। हमने देखा कि अभी पिछले चुनावों में इन लोगों में से जिन को पैसा मिल गया था वे तो सरकार के गुण गाते थे और जिनको नहीं मिला था वे कुछ सरकार के खिलाफ प्रचार करते थे। मैं अर्ज करना चहाता हूं कि इसके मुताल्लिक खास तौर पर ध्यान देना चाहिए।

एक और चीज चल रही है। कुछ आर्मी के आदमी थे जिनको सन् १९४२ में आपने आर्मी आरडनेन्स में वाच एंड वार्ड में भेज दिया था। उनके पेंशन के केसेज चल रहे हैं जिनका आज तक फैसला नहीं हुआ है। बहुत पुराने केस हो गए हैं। ये लोग आर्मी में थे और अपनी मर्जी से नहीं गए, आपने उनको भेजा था। तो उनकी तरफ ध्यान दें और उन के जो पेंशन के केसेज़ हैं उनको निपटाया जाए।

इसी तरह से एम ई एस का जो परसोनल है, उनमें जो लोग सुपरएन्युएट हो कर जाते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय: मेम्बर साहब जब तकरीर करते हों तो उनकी तवज्जह आफिशियल बाक्स की तरफ न होकर मेरी तरफ होनी चाहिए।

श्री हेम राज: मेरी तवज्जह तो आपकी ही तरफ है। नजर कभी उनकी तरफ हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय: नजर भी मेरी ही तरफ रखिए।

श्री हेम राज: तो मैं एम ई एस परसोनल के बारे में कह रहा था कि जो लोग इनमें से सुपरएन्युएट होकर जाते हैं उनके पेंशन, ग्रेच्युइटी और प्रावीडेंट फंड के मामले जल्द फैसले होने चाहियें। इनमें बहुत देरी होती है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

एक और बात अर्ज कर दूं जोकि पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखती है। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूं। मेरे यहां के बहुत से डोगरे जवान आपकी फौज में हैं लेकिन उनमें ज्यादातर सिपाही ही हैं। शायद उन को आफिसर क्लास मयस्सर नहीं होता है। आपने हर जगह सैनिक स्कूल खोले हैं लेकिन मेरा इलाका सूना है, आपने शायद पंजाब में खोले हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने हमारे यहां मनाली में माउंटेनियरिगं का जो स्कूल खोला है उसके साथ साथ वहां सैनिक स्कूल भी खोला जाए ताकि जहां आप एक जगह से आफिसर तैयार करें वहां दूसरी तरफ माउंटेनियर्स भी तैयार करें। दोनों चीजें साथ साथ चलें तो अच्छा है।

यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस सैनिक स्कूल को चाहे मनाली में कायम करें या धरमशाला में या पालमपुर में। मैं समझता हूं कि अगर आप यह काम करेंगे तो जहां हमारे नौजवानों ने फौज में भरती होकर शानदार काम किया है वहां आफिसर्स क्लास में भी उनको जाने का मौका मिल सकेगा और वह आफिसर्स बनने के काबिल भी हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हेम राज : बस एक और छोटी सी अर्ज करके मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। आपने हमारे नौजवानों के लिए यह ठीक है कि एक नौगोंग में स्कूल खोला है। जूनियर कमिशंड आफिसर्स को एक मौका दिया है लेकिन एक स्कूल इसके लिए नाकाफी है। अब वहां पहले ९० लिये जाते थे तब १५० ट्रेनीज लिये जायेंगे लेकिन वह भी नाकाफी है। उनके लिए और ज्यादा मौका मयस्सर करना चाहिए और उनके लिए और अधिक स्कूल आपको खोलने चाहिएं ताकि उनकी तादाद बढ़ सके और उनको ज्यादा मौका मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की डिमांड्स को सपोर्ट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती (झज्जर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के बजट अनुदानों के सम्बन्ध में बोलते हुए कुछ सुझाव ही सदन् के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने जो बजट उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि जितने पैसों की उनकी मांग है उस को केवल थोड़ा ही न बढ़ा कर दुगना बढ़ा दिया जाये। लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी कि ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेना का राष्ट्र में वही स्थान है जोकि हमारे शरीर में प्राण का होता है। अगर प्राण नहीं है तो शरीर मुर्दा है। इसी तरीके से अगर सेना हमारी सज्जित नहीं है और सुदृढ़ नहीं है तो राष्ट्र के नाश होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए सेना को सुदृढ़ बनाना चाहिए। चूंकि मैं सैनिक परिवार से सम्बन्ध रखता हूं इस नाते मुझे इन बातों का अनुभव है।

यूरोप का जो प्रथम महायुद्ध हुआ था उसमें मैं एक सिपाही था और दो साल मैं ओवर-सीज भी रहा हूं। इसलिए मैं सब बातों को जानता हूं एक सिपाही को आप मान दीजिये। अब सिपाही को यदि आप मान देते हैं तो वह राष्ट्र के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहता है। मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करता कि राष्ट्र की रक्षा तभी हो सकती है जबकि हमारे केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में कोई रिटायर्ड जनरल हो। इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन के मंत्रिमंडलों में भी कोई न कोई रिटायर्ड मिलेटरी का अफसर जरुर होना चहिए जिससे कि वह ऐक्सपर्ट सलाह मशविरा दे सके। यह अत्यन्त आवश्यक है।

राजनीतिक भाई, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि उन में साहस कम होता है लेकिन मिलेटरी वाला भाई साहसी होता है। कश्मीर में युद्ध विराम समझौता करने का यदि हमारे राजनीतिक नेता मिलेटरी के जिम्मेदार अधिकारी को आदेश नहीं देते तो एक दिन के अंदर हमारे जवानों ने हमलावरों को कश्मीर भूमि से बाहर खदेड़ दिया होता और सारी समस्या तभी हल हो गई होती और कश्मीर जैसा कोई प्रश्न हल होने को रह ही नहीं जाता। इस लिए आवश्यकता है कि अपने फौजी जवानों को प्रोत्साहन दिया जाये। साथ में यह भी है कि उन के बालबच्चों की देखभाल आदि के लिए पूरा ध्यान दिया जाये। अब हमारे वह

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

फौजी जवान लद्दाख के पहाड़ पर बैठे हैं या नागालैंड में बैठे हैं, पीछे उनके यहां कहीं चकबन्दी का झगड़ा होता है तो कभी अदालत का मामला आ जाता है और उन बेचारों की सुनवाई नहीं हो पाती है इसलिए यह आवश्यक है कि उधर ध्यान दिया जाये।

साथ ही सैनिक शिक्षा स्कूल व कालिजों में ही अनिवार्य न हो अपितु प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाये। सैनिक प्रशिक्षण हर एक भारतवासी को दिया जाये। सर्विसेज में उसी समय किसी को लिया जाय जबकि कम से कम एक वर्ष के लिये उसने मिलिटरी के अन्दर जाकर ट्रेनिंग ले ली हो। इससे अनुशासन भी बनेगा और दृढ़ता भी आयेगी और अपने राष्ट्र की खातिर वह सारा कामकाज लगन से और दृढ़ता से करेगा।

यह स्वागत योग्य बात है कि वैज्ञानिक लोग यूरोपियन वैज्ञानिकों के ढंग की खोज कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वे इसके लिये अपने घर की ओर भी देखें। यहां भी सब कुछ है। अब एक मिनट के लिये मैं महाभारत की एक घटना सुनाता हूं। जिस समय युधिष्ठिर घबड़ाये कि यह सामने भीष्म जैसा बहादुर व्यक्ति कैसे मरेगा तो अर्जुन ने कहा था :—

"सर्वानपि सामरान् हन्याम् निमेषादिति

मेरे भाई युधिष्ठिर क्यों घबड़ाते हो। आंख मींच कर खोलने में जितनी देर लगेगी उतनी देर में मैं सारे योद्धाओं को ढेर कर दूंगा अर्थात् नष्ट कर दूंगा। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था जिसके कि बल पर उसने ऐसा कहा था। पशुपति कहते हैं विद्युत् को बिजली को। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के अमोघ शस्त्र अस्त्र प्राचीन काल में हमारे लोगों के पास होते थे। आप इनके बारे में अपने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में खोज करायें तो आपको ऐसे अद्भुत अस्त्र मिल सकते हैं जिससे कि यूरोपियन वैज्ञानिकों के घर में हमें देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि मिलेटरी के काम के लिये और इस प्रकार की खोज के लिये संस्कृत के पंडितों को अवश्य स्थान दिया जाये। मुझे आशा और विश्वास है कि वह पुराने समय के बारे में खोज करने के कार्य में विशेष सहायता दे सकेंगे।

सेना जहां बाहर के शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है वहां ऐसे अराजक तत्वों से जोकि हमारे देश के भीतर ही बैठे हुये हैं, ऐसे देश और समाज विरोधी तत्वों से भी सेना के द्वारा ही पूर्ण रक्षा की जा सकती है।

अब स्पष्ट चीज है कि इसके लिये हमें सेना अधिक रखनी पड़ेगी और उस पर होने वाले खर्चे में भी अधिकता करनी पड़ेगी और मैंने कहा भी है कि सैनिक खर्च दुगना कर दिया जाये। अब इसके लिये कहा जायेगा कि पैसा कहां से आये? मेरा सुझाव है कि इसके लिये जितने भी यह सिनेमाओं के अन्दर गन्दे और अश्लील स्त्री, पुरुष के चलचित्र दिखलाये जाते हैं उनको तुरन्त बन्द कर दिया जाये। इसके साथ ही विदेशों से जितनी साज श्रृंगार की चीजें आती हैं उनको तुरन्त बन्द कर दिया जाये। वह सब पैसा लेकर मिलेटरी के काम में दे दिया जाये। इसी तरह से नाच, गाने के नाम पर सांस्कृतिक मंडल विदेशों को भेजे जाते हैं उनको रोक दिया जाये और वह सब पैसा मिलेटरी को दे दिया जाये। इस तरह की कितनी ही चीजें हैं जिनको कि अगर बन्द कर दिया जाय तो कोई हर्जा न होगा वरन् उनका बन्द होना हितप्रद ही होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे आचार, विचार बहुत ऊंचे हों और फौज के अन्दर उच्च कोटि के

आचारवान् राष्ट्रभक्तों के व्याख्यान कराये जायें जोकि हमारी सेना को सुदृढ़ बना सकें और राष्ट्र के प्रति अनुशासन और भक्ति का भाव रखने का पूर्ण शिक्षण दे सकें।

मेरा यह स्वभाव नहीं है कि मैं अधिक समय तक बोलूं। बस मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

"आराष्ट्रे राजन्यः शूर इसव्यो अतिव्याधी महारथो जायताम्"।

हमारे राष्ट्र के अन्दर शूरवीर सैनिक हों। हमारे सिपाही कैसे होने चाहियें ?

"अतिव्याधी"—रोगी न हों—सिपाही रोगी नहीं होने चाहियें।" "महारथः" चतुरंगिणी जो सेना है—क्या आकाश, क्या भूमि, क्या जल पर और क्या जल के नीचे, चारों प्रकार की सेना संचालन विधि में निपुण हों। "इसव्य"—जो निशाने में अचूक हों। जो केवल शस्त्र, अस्त्र को ही नहीं बल्कि सब बातों को जानने वाले हों।

हमें तो अपने फौजी जवानों पर गर्व है। कश्मीर में जब शत्रु घुस आया था तो लेफटिनेंट महाराजसिंह कश्मीर के पहाड़ की चोटी पर मशीनगन लेकर चले गये थे, ६ हजार फीट की ऊंचाई पर चले गये और अपना बलिदान दे दिया। ऐसे बहादुरों के द्वारा ही भारत की रक्षा हो सकती है। आराम गाड़ियों और ऐयर कंडीशंड बंगलों में रहने वाले राजनीतिक लोग जोकि चर्चा मात्र करते हैं राज्य उनके द्वारा नहीं बचाया जायेगा। राष्ट्र तो बचेगा सिपाही से। इसलिये मैंने आप से बार बार निवेदन किया कि सिपाही को आप मान दीजिये। सिपाही क्या चाहता है ? वह इज्जत चाहता है। अब अगर उसको मान भी नहीं दिया जायेगा, धन तो आप देते नहीं तो उसमें उधर जाने की प्रवृत्ति कम होगी और उसका उत्साह क्षीण हो जायेगा।

मैं यह नहीं कहता कि एक विशेष वर्ग वाले ही सैनिक बन सकते हैं। सभी लोग सैनिक बन सकते हैं। परन्तु यह जरूर है कि जो लोग परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी से फौज के अन्दर रहते चले आये हैं, राष्ट्र की जिन्होंने रक्षा की है उनसे सिपाही जल्दी तैयार हो जाते हैं। जिन लोगों ने समय समय पर भारत की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनके अन्दर यह क्षात्र ओज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और वह जल्दी काम कर सकते हैं। जब मिलेटरी का बाजा बजता है मारू बाजा बजता है तो सिपाही हालांकि उसकी कमर पर साढ़े २२ सेर का बोझा लदा हूआ है लेकिन वह दौड़ पड़ता है और उस बोझ को धारण किये २८, २८ मील पैदल मार्च करता हुआ चला जाता है। अब उसमें एक देशभक्ति की भावना होती है, राष्ट्र की सेवा करने और रक्षा करने का भाव रहता है। इस नाते मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप सिपाहियों को प्रोत्साहन दें और मान दें। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहा हूं और वह इसलिये कि मेरा सारा क्षेत्र मिलेटरी का है। घर घर में ऐसे परिवार हैं। उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाये। उनसे भारत की रक्षा इधर भी होगी और उधर भी होगी—चारों तरफ उनसे रक्षा होगी। इसलिये जितना भी सहयोग इस संबंध में माननीय मंत्री दे सकते हैं, वह दें। इधर उधर जो रुपया खर्च किया जा रहा है, उसको बचाना चाहिये। कल मैं एक जगह गया था। वहां मैंने देखा कि बाजे बज रहे हैं—चीं चीं चीं, पूं पूं, पूं। (अन्तर्बाधायें) उनसे क्या होगा। हमने मनोरंजन नहीं करना है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो यहां पर ही वे बाजे बजाने लग गये। (अन्तर्बाधायें)

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : उस पैसे को बचाया जाना चाहिये। अगर बजे तो मिलिटरी का बाजा बजे—ढम ढम ढम।

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

यह कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि मिलिटरी को दृढ़ बनाया जाये और सारी शक्ति उसको दी जाये। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी और राज्यों के मंत्रिमंडलों में भी मिलिटरी का एक एक सदस्य अवश्यमेय हो।

धन्यवाद।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगें आगे से बढ़ गयी हैं। अब ये कुल ३७९ करोड़ रुपये की हो गयी हैं। हमारे जो जवान युद्ध के विभिन्न केन्द्रों में लड़ रहे हैं उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट किये बिना मैं नहीं रह सकता। यह कोई आडम्बर की बात नहीं ठोस तथ्य है कि जब से हमारे वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री इस पद पर आये कुछ न कुछ हो रहा है और हम बार बार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम चाहें तो अन्य देशों की तरह एक बहुत बड़ी सेना का भी निर्माण कर सकते हैं परन्तु हम उस पथ पर चलने में विश्वास नहीं करते। हम तो अपने देश के आर्थिक निर्माण में जुटे हुये हैं। हमारा इरादा किसी देश पर आक्रमण करने का नहीं, अतः हमारी प्रतिरक्षा के लिये जो भी सेना है वह पर्याप्त है। इस समय कोई देश अथवा व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता। यह बात सब जानते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो एक अथवा दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, वह विश्व युद्ध बन कर ही रह जायेगा।

उपकरणों के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मेरा निवेदन है कि हमें अपने साधनों के अनुसार उन्हें अवश्य प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये किसी देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। हम विमान कहां से खरीदें इसका अन्तिम निर्णय हमारे मंत्रालय ने करना है। रूस से एम० आई० जी० विमानों की खरीद हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये अनेक प्रकार से लाभकारी मालूम होती है। प्रतिरक्षा मंत्री को देश के हित में यह सौदा शीघ्र तय करना चाहिये। इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि हेलीकोप्टरों की खरीद को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खाना इत्यादि फेंकने में वे बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

मुझे इस बात का सन्तोष है कि सैनिक प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ हो गया है। यद्यपि इससे पूर्व इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी थी। हर्ष की बात है कि विभिन्न स्थानों पर सैनिक स्कूल खोले गये हैं। यदि सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों में भी सैनक प्रशिक्षण चालू किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सेवा से निवृत्त कर्मचारियों की समुचित देखभाल की जानी चाहिये। उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि नाविक, सैनिक तथा वैमानिक बोर्डों को किसी मंत्री के प्रभार के अन्तर्गत रख दिया जाना चाहिये जो उन मामलों में रुचि ले। इसी प्रकार प्रादेशिक सेना को भी समुचित प्रोत्साहन देने की योजना का निर्माण किया जाना चाहिये और उसे नियमित सेना के स्तर पर लाया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मेरा कहना है कि लोक सहायक सेना किसी काम की चीज नहीं और जो ८० लाख रुपया उस पर खर्च कर दिया जाता है वह बिल्कुल नष्ट किया जाता है। इस धन का सदोपयोग किसी और दिशा में लगाया जाना चाहिये। यह धन प्रादेशिक सेना अथवा रांष्ट्रीय छात्र सेना दल के विस्तार के काम में लगाया जाना चाहिये। झंडा दिवस मनाये जाते हैं और उन दिनों धन एकत्रित किया जाता है। मेरा सुझाव है कि "फ्लैग डे" पर एकत्रित किये गये धन में से सैनिक परिवारों के लिये धन स्वीकृत करने की सरल प्रक्रिया निकाली जानी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि 'क्वीन

---

†मूल अंग्रेजी में

विक्टोरिया मैस" की हालत बहुत खराब है, इसे सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहि इसमें बड़े बड़े सैनिक अधिकारी रहते हैं।

†**श्री अ० व० राघवन** : सब से पूर्व मैं गोआ को स्वतंत्र करवाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। और प्रतिरक्षा मंत्री इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि वह प्रतिरक्षा उपकरणों के लिये भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं। हमारे जैसे साधनहीन देश के लिये यह बहुत बड़ी बात है। इसके कारण के लिये बहुत बड़ी योग्यता और प्रवीणता की आवश्यकता होती है। यह भी सन्तोष का विषय है कि प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी उद्योग क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। आशा है कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की दिशा में प्रगति जारी रखी जायेगी।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे जवानों ने बड़े बड़े शानदार कार्य किये हैं। अपने साहस और वीरता के लिये वे संसार भर में प्रसिद्ध हैं। उनसे देश का काफी गौरव हुआ है। परन्तु जब इन जवानों को सेना से निवृत्त किया जाता है तो इन्हें भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो यह सरकार का कर्त्तव्य है। इसके लिये मेरा सुझाव तो यह है कि सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के लिये केन्द्र तथा राज्यों में २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने चाहियें। यदि किसी कारण से यह संभव न हो तो प्रतिरक्षा बजट का कम से कम ५ प्रतिशत उनके पुनर्वास के लिये आवंटित कर दिया जाना चाहिये।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि बहुत से प्रतिरक्षा कर्मचारियों को पुलिस की जांच रिपोर्टों के आधार पर बिना अपनी स्थिति की सफाई देने का अवसर दिये नौकरी से हटा दिया जाता है। यह बड़े अन्याय की बात है, सरकार को इन मामलों की जांच करनी चाहिये और सैनिकों की शिकायतें दूर करनी चाहियें। इस लोकतंत्रीय संविधान के अन्तर्गत उनके भी अधिकार हैं।

सैनिकों के बच्चों की शिक्षा भी महत्वपूर्ण बात है। सरकार का व्यवहार इसके प्रति उपेक्षापूर्ण है। सैनिकों के बच्चों को भी शिक्षा संबंधी रियायतें तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहियें। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों तथा जिलों के सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कर्मचारियों की सेवा की परिस्थितियों का सुधार किया जाना चाहिये।

मैं हिन्दी के विरुद्ध नहीं परन्तु सैनिकों की पदोन्नति के लिये हिन्दी को अनिवार्य बनाना उचित नहीं

बड़े खेद की बात है कि जवानों की वार्षिक वेतन वृद्धि केवल ५० नये पैसे है। मेरा निवेदन है कि यह वार्षिक वेतन वृद्धि बढ़ाई जानी चाहिये। प्रतिरक्षा क्लर्कों तथा असैनिक क्लर्कों का वेतन बराबर किया जाना चाहिये। दोनों जब एक जैसा काम करते हैं तो यह असमानता क्यों। देश के लम्बे समुद्र तट को दृष्टि में रखते हुये हमारी नौसेना की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये। उसे हर तरह से लैस किया जाना चाहिये। वह प्रत्येक प्रकार से सज्जित हो इस उद्देश्य के लिये अधिक धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि हमारे जवान खुश रहें और देश के लिये अधिक से अधिक बलिदान देने को तत्पर रहें।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (घरवर उत्तर) : अपनी परम्पराओं के अनुसार भारत योद्धाओं का देश रहा है। देश की प्रतिरक्षा के प्रश्न पर सारा देश एक है। हमारे लोगों ने उस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सरोजिनी महिषी]

ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया है जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। और आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की सीमाओं की रक्षा के बारे में हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को देश की एकता कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिये और सीमांत की सुरक्षा पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब कभी भी हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा होगा हमारी सेनायें उसका सामना करने में सफल होंगी। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे परन्तु यदि किसी ने हम पर हमला किया तो सहन भी नहीं करेंगे। शताब्दियों से गुलाम पड़े हुये गोआ को हमारे सैनिकों ने मिनिटों में स्वतंत्र करवा लिया। अतः स्पष्ट है कि यदि हमारे देश का सैनिक जाग उठे तो सब कुछ कर सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था में काफी वृद्धि करनी चाहिये ताकि किसी भी देश को हमारी शक्ति के संबंध में कोई गलत फहमी न रहे। हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को आधुनिक तथा नवीनतम उपकरणों से पूर्ण रूप से सज्जित किया जाना चाहिये। हमें अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना चाहिये ताकि वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिये सचेत एवं तैयार रहें।

मैं कुछ स्वार्थ की बात भी कर रही हूं। वह यह कि १८५७ के युद्ध से पूर्व रानी किट्टूर चेन्नाम्मा अंग्रेजों से लड़ी थी। उसकी स्मृति में मैसूर में एक सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिये।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : प्रतिरक्षा के प्राक्कलनों पर ७ घंटे तक चर्चा चलती रही है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बहुत सी बातों का तो मुझे पता भी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बीरवार ३१ मई, १९६२ ज्येष्ठ १०, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ३० मई, १९६२

९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३५८७–३६१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
११६४	डाकखानों में लिखने का कागज	३५८७–८९
११६५	स्टीमरों की मरम्मत का कारखाना	३५८९–९०
११६६	सेवा निवृत डाक-तार कर्मचारी द्वारा आत्महत्या	३५९०–९१
११६८	सोन नदी पर पुल बनाने के लिये धन देना	३५९१–९२
११६९	डाक तथा तार सेवा	३५९२–९३
११७०	पीने के पानी की संभरण योजनाएं	३५९४–९७
११७२	रक्सौल हवाई अड्डा	३५९७–९८
११७४	रेलवे में अपराध	३५९८–९९
११७५	दिल्ली में बिजली की समान दरें	३५९९–३६००
११७६	मिश्र समिति का प्रतिवेदन	३६००–०१
११७८	केरल में नारियल के वृक्षों को नष्ट करने वाला रोग	३६०२–०४
११७९	चावल क्षेत्र	३६०४–०६
११८१	राजस्थान के लिये भाखड़ा और चम्बल की बिजली	३६०६–०७
११८३	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	३६०७–०९
११८४	नौवहन व्यापार के लिये ब्रिटिश फर्म को ऋण	३६०९–१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३६१०–८४
तारांकित प्रश्न संख्या		
११६७	हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच रेलवे लाइन	३६१०
११७१	अन्तर्देशीय जल परिवहन	३६१०
११७३	अजय नदी पर बांध	३६११

	विषय	पृष्ठ

प्श्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११७७	रिक्शा चालक संस्थायें	३६११
११८०	आंध्र प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत	३६११–१२
११८२	हीराकुद बांध परियोजना	३६१२
११८५	स्कूल स्वास्थ्य समिति की सिफारिश	३६१२
११८६	ग्राम क्षेत्रों में डाकघर	३६१२–१३
११८७	प्रयाग में मालगाड़ी से रेल कर्मचारियों का कट जाना	३६१३
११८८	खड़गपुर से हल्दिया तक रेलवे लाइन	३६१३
११८९	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	३६१४
११९०	सड़क परिवहन प्रबन्ध के लिये त्रिदलीय निकाय	३६१४
११९१	"चम्पावती" यात्री पोत	३६१४–१५
११९२	दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	३६१५
११९३	डाक तथा तार कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	३६१५
११९४	मुंगेर जिलो माल डिब्बों का संभरण न किया जाना	३६१५–१६
११९५	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियां	३६१६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१६८	कृषि विश्व विद्यालय	३६१६
२१६९	उड़ीसा में आदिम जातीय खंड	३६१६–१७
२१७०	सुपारी के वृक्षों का नष्ट होना	३६१७–१८
२१७१	केरल में बीमारियों के कारण काली मिर्च के पौधों का नष्ट होना	३६१८–१९
२१७२	कीटनाशक दवाई छिड़कने के उपकरण	३६१९–२०
२१७३	काली मिर्च के दाम	३६२०
२१७४	करियानकोड पुल	३६२०–२१
२१७५	केरल में राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	३६२१
२१७६	पाठ्य विषय के रूप में सहकारिता	३६२१–२३
२१७७	मद्रास राज्य में पीने के पानी का संभरण	३६२३
२१७८	होगनक्करल परियोजना	३६२३
२१७९	गाजीपुर डाकखाने का भवन	३६२४
२१८०	गोरखपुर डिवीजन में टेलीफोन कनेक्शन	३६२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नो के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१८१	उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था	३६२४
२१८२	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण	३६२४–२५
२१८३	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ	३६२५
२१८४	जूनागढ़ का अनुस्थापना तथा अध्ययन केन्द्र	३६२५–२६
२१८५	चीनी का उत्पादन	३६२६
२१८६	चावल का उत्पादन	३६२६–२७
२१८७	आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालिज	३६२७
२१८८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	३६२७
२१८९	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना	३६२७
२१९०	उड़ीसा में ग्रामीण जल संभरण योजना	३६२७–२८
२१९१	उड़ीसा में चेचक और हैजा	३६२८
२१९२	उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र	३६२९
२१९३	उड़ीसा में सड़कों का विकास तथा विस्तार	३६२९
२१९४	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३६२९–३०
२१९५	पटना में चलते फिरते डाक घर	३६३०
२१९६	इस्पात के पैकिंग के नियम	३६३०
२१९७	आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली	३६३१
२१९८	'आर्गन क्रोमेटोग्राफ'	३६३१
२१९९	पूर्व रेलवे के कंकिनाडा और श्यामनगर स्टेशनों के बीच हाल्ट	३६३१
२२००	बीकानेर रेलवे वर्कशाप श्रमिकों के लिये रेलगाड़ी	३६३२
२२०१	बीकानेर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों का स्थानातरण	३६३२
२२०२	लेखा विभाग में क्लर्क	३६३२–३३
२२०३	दिल्ली में पानी का संभरण	३६३३
२२०४	वन उत्पाद	३६३३–३४
२२०५	विजयवाड़ा और मद्रास के बीच रेलवे लाइन	३६३४
२२०६	चीनी के कारखाने	३६३४
२२०७	मदुरै शहर में "मंगक्मल चतराम" का सुधार	३६३४–३५
२२०८	मूंगफली खाद्य संयंत्र	३६३५
२२०९	किराये की इमारतों में डाकघर	३६३५–३६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२१०	घग्गर में बाढ़	३६३६
२२११	त्रिपुरा में विस्थापित लोगों को ऋण	३६३६
२२१२	दिल्ली जल संभरण	३६३७
२२१३	रेलवे क्वार्टरों का किराया	३६३७–३८
२२१४	सिंचाई परियोजनायें	३६३८
२२१५	केरल में समुद्र द्वारा भूमि कटाव	३६३८–३९
२२१६	रेलों में भोजन-यानों और स्टेशनों के उपाहारगृहों में भोजन के मूल्य	३६३९
२२१७	दिल्ली में वनस्पति का निषेध	३६३९–४०
२२१८	अमरपुर त्रिपुरा के विस्थापित लोग	३६४०
२२१९	देश में चेचक	३६४०
२२२०	रायचूर के लिये अधिक माल डिब्बों का संभरण	३६४०–४१
२२२१	कृषि उत्पादों की प्रति एकड़ उपज	३६४१–४२
२२२२	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में आकस्मिक मजदूर	३६४२
२२२३	पोर्ट ब्लेअर में सरकारी बिजलीघर के लिये इंधन	३६४२–४३
२२२४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पदोन्नति	३६४३–४४
२२२५	बड़ौदा डिविजन में भोजन व्यवस्था	३६४४
२२२६	पहलगाम में अवकाश गृह	३६४५
२२२७	बिजली का उत्पादन	३६४५–४६
२२२८	लाइसेंस शुदा औषधि निर्माता	३६४६–४७
२२२९	त्रिपुरा में कुष्ठ	३६४७–४८
२२३०	त्रिपुरा में पीने के पानी की कमी	३६४८
२२३१	गैस टर्बाइन जेनरेटिंग यूनिटों आदि के लिये आयात लाइसेंस	३६४८–४९
२२३२	ए० आर० टी० कमानी के कोयला खान श्रमिकों को चावल का संभरण	३६४९–५०
२२३३	बिजली की दरें	३६५०
२२३४	फल उगाने वालों को ऋण	३६५०–५१
२२३५	मध्य प्रदेश में डाक घर	३६५१
२२३६	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नये हाल्ट और स्टेशन	३६५१
२२३७	कहराकूल में रेलवे स्टेशन	३६५१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२३८	दक्षिण पूर्व रेलवे पर यात्री शेड	३६५२
२२३९	दक्षिण-पूर्व रेलवे में भद्रक में प्राथमिक स्कूल	३६५२–५३
२२४०	दूर संचार सेवा का बन्द रहना	३६५३
२२४१	आंध्र प्रदेश से कर्मचारियों का स्थानांतरण	३६५३
२२४२	कोट्टायम में डाकघर की इमारत	३६५३–५४
२२४३	डाक तथा तार भवन	३६५४
२२४४	विजयवाड़ा के समीप रेलवे पुल	३६५४
२२४५	बाढ के पानी को निकालना	३६५४–५५
२२४६	नये डाक घर	३६५५
२२४७	सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	३६५५
२२४८	भारत के रक्षित बैंक द्वारा किसानों को ऋण	३६५५–५६
२२४९	रक्षित वन क्षेत्र, त्रिपुरा	३६५६
२२५०	जोगिन्दर नगर-बरोत सड़क	३६५६
२२५१	देहाड़–तत्तापानी सड़क	३६५६–५७
२२५२	मद्रास में भेड़ों की नस्ल बढ़ाना तथा ऊन अनुसंधान केन्द्र	३६५७
२२५३	गोबर	३६५७
२२५४	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी	३६५८
२२५५	दिल्ली के किसान	३६५८
२२५६	ओंगोल नस्ल के सांड	३६५८–५९
२२५७	केरल में "पेकेज" योजना	३६५९
२२५८	ऊनान्हमीरपुर सीधी ट्रंक लाइन	३६५९
२२५९	पंजाब में आयुर्वेदिक संस्थायें	३६६०
२२६०	'लक्जरी' कोच सर्विस	३६६०
२२६१	बिहार में राष्ट्रीय राजपथ	३६६०
२२६२	बिहार में पुल	३६६०–६१
२२६३	बिहार में विद्युत् संभरण	३६६१
२२६४	नंगल बांध में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३६६१
२२६५	मद्रास राज्य में मेडिकल कालिज	३६६१
२२६६	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान	३६६२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२६७	समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलना .	३६६२
२२६८	क्वार्टरों का किराया . . .	३६६२
२२६९	साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात . .	३६६२
२२७०	नागार्जुन सागर परियोजना स्थान पर मजदूर . .	३६६२–६३
२२७१	नलागढ़ समिति . . .	३६६३
२२७२	बन्देल (पश्चिम बंगाल) में विद्युत् संयंत्र .	३६६३
२२७३	आसाम में बिजली	३६६३–६४
२२७४	"बाक्स" प्रकार के वैगनों का निर्माण . .	३६६४–६५
२२७५	उड़ीसा में इन्द्रावती जलविद्युत् परियोजना .	३६६५
२२७६	भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति .	३६६५
२२७७	कलोल में मेहसाना तक दोहरी लाइन . .	३६६५–६६
२२७८	बसों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं को रोकने का यंत्र .	३६६६
२२८०	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	३६६६
२२८१	शेर के बच्चे	३६६७
२२८२	आसाम में जल संभरण योजनायें . . .	३६६७
२२८३	ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर राष्ट्रीय राजपथ .	३६६८
२२८४	ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर डिब्रुगढ़ तक रेल मार्ग .	३६६८
२२८५	स्टीम नेवीगेशन कम्पनी . .	३६६८–६९
२२८६	खंभात की खाड़ी . .	३६६९
२२८७	ग्रामीण डाक सेवा . .	३६६९–७०
२२८८	पेड़ों के रोग	३६७०
२२८९	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम में प्रशिक्षण स्कूल	३६७०
२२९०	दिल्ली में दूध की कमी . . .	३६७१
२२९१	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के स्काइमास्टर विमान	३६७१
२२९२	गवेषणा, प्रारूप और मानक, शिमला में अनुसूचित जाति के पदाधिकारी	३६७१–७२
२२९३	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् . . .	३६७२
२२९४	फाइलेरिया का उन्मूलन . . .	३६७२–७३
२२९५	उरई से जालौन (उ० प्र०) तक रेलवे लाइन . .	३६७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२९६ पोखरायां और कानपुर (मध्य रेलव) के बीच रेल की जंजीर खींचना ३६७३–७४
२२९७ माताटीला बांध बिजलीघर ३६७४
२२९८ रतलाम और मंडल के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की रफ्तार पर प्रतिबन्ध ३६७४–७५
२२९९ रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों का संभरण . . . ३६७५–७६
२३०० रविवार को और छट्टी वाले दिन कोयले का लदान . . ३६७६
२३०१ आंध्र प्रदेश में सिचाई और विद्युत् योजनायें . . ३६७६–७७
२३०२ केरल में कुष्ठ . . . ३६७८
२३०३ सिटी रेलवे बुकिंग आफिस . . ३६७८
२३०४ पंजाब में बाढ़ नियंत्र योजनायें ३६७८–७९
२३०५ पंजाब में पशुधन . . ३६७९–८०
२३०६ टेलीफोन के कनेक्शन ३६८०
२३०७ पंजाब में गोदाम . . . ३६८१
२३०८ चंडीगढ़ स्टेशन का नव निर्माण . . . ३६८१
२३०९ पंजाब में पानी की कमी ३६८१
२३१० फीरोजपुर और दिल्ली डिवीजनों में तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . . . ३६८१–८२
२३११ कोसी नहर ३६८२
२३१२ झाबुआ जिले को मिलाने वाली रेलवे लाइन . ३६८२
२३१३ झाबुआ जिले में सिचाई और बिजली योजनायें . . ३६८२–८३
२३१४ रेलों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन . . ३६८३
२३१५ नागार्जुन सागर परियोजना . . ३६८३–८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३४/६०—ट्रांसपोर्ट ।

पृष्ठ

(दो) दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/५४/६१—ट्रांसपोर्ट ।

(२) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ की धारा ३२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६९९ में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा परिषद (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति) नियम १९६१ की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५६ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३६८४

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

समितियों के लिये निर्वाचन ३६८५

(१) स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हूआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ३६८५—३७२६

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हूई ।

गुरुवार, ३१ मई, १९६२ / १० ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा, तथा निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—118(Ai)LSD—13-9-62-150